असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

17 मार्च, 2016

षोडश विधान सभा **17 मार्च, 2016 ई०**

द्वितीय सत्र **वृहस्पतिवार, तिथि 27 फाल्गुन, 1937 (शक)**

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय 11.00 **बजे पूर्वा०)**

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। प्रश्नकाल। अल्पसूचित प्रश्न।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, महंगाई बढ़ गयी है और ये अच्छे दिन दिखानेवाले लोग....

(व्यवधान)

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर खड़े होकर कुछ बोलने लगे।)

(व्यवधान)

(इस अवसर पर राजद एवं जदयू के माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर खड़े होकर कुछ बोलने लगे।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये। श्याम जी, बैठ जाइये।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-4(श्री सुबोध राय)

श्री महेश्वर हजारी : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्रावणी मेला एवं अन्य अवसरों पर गंगा के घाटों पर बांस बैरिकेटिंग एवं चेतावनी बोर्ड लगायी जाती है। सुरक्षा नौका, लाइफ जैकेट आदि की समुचित व्यवस्था नगर परिषद् सुल्तानगंज के द्वारा की जाती है। जिला स्तर पर एन0डी0आर0एफ0.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सभी माननीय सदस्य, अब अल्पसूचित प्रश्न काल प्रारंभ है और श्री सुबोध राय जी के प्रश्न का माननीय मंत्री, नगर विकास उत्तर दे रहे हैं। सभी माननीय सदस्य कृपया ध्यान से सुनिए। माननीय मंत्री नगर विकास।

टर्न–1/शंभु/17.03.16

श्री महेश्वर हजारी : वर्णित घाटों के लिए रिवर फोर्म डेवलपमेंट का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेज दिया गया है। जिसकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री सुबोध राय : महोदय, सुल्तानगंज का घाट कितना महत्वपूर्ण है, यह हमको सदस्यों को बताने की जरूरत नहीं है। तमाम धार्मिक स्थलों पर जो घाट है उसका निर्माण किया गया है, सुदृढ़ीकरण किया गया है, लेकिन सुल्तानगंज श्रावणी मेला के समय में जब लाखों लोग जुटते हैं तो सिर्फ एक महीना के लिए बैरिकेटिंग की व्यवस्था होती है। आज भी घाट दलदली में है और चार कदम जैसे ही स्नान करनेवाले लोग जाते हैं, गहरे पानी में डूब जाते हैं और 12–13 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए मेरा सरकार से यही प्रश्न है कि क्या सरकार इसके सीढ़ी एवं घाट का निर्माण करायेगी, क्या सीढ़ी की व्यवस्था कराकर घाट का सुदृढ़ीकरण करायेगी ? मैं यही सरकार से जानना चाहता हूँ।

श्री महेश्वर हजारी : महोदय, मैंने पहले ही कहा वर्णित घाट जो है उसका रीवर फोर्म डेवलपमेंट का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है उसको भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। स्वीकृत होकर आयेगा तो शीघ्र कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा।

श्री सुबोध राय : महोदय, भारत सरकार कब स्वीकृत करेगी, नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार सरकार की क्या जिम्मेदारी है। वह अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरा करने के लिए तैयार है ?

श्री महेश्वर हजारी : महोदय, वहां पर सुल्तानगंज में जिला स्तर पर एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 की टीम प्रतिनियुक्ति की जाती है। घाट पर जो मेला लगता है वहां पर उसके संबंध में माननीय सदस्य कह रहे हैं तो चूंकि जब तक घाट की व्यवस्था, सीढ़ी नहीं बन पायेगी या और व्यवस्था नहीं हो पायेगी, तब तक मैं समझता हूँ कि जनहित में नहीं होगा। इसीलिए डी0पी0आर0 तैयार जब तक नहीं होगा, तब तक कैसे होगा, प्रक्रिया तो अपने अनुसार ही चलेगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ माननीय सदस्य को कि जल्द से जल्द उसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम करवा देंगे।

श्री सुबोध राय : ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए डी0पी0आर0 तैयार करवायेगी सरकार ?

अध्यक्ष : वही तो माननीय मंत्री कह रहे हैं।

श्री सुबोध राय : कब तक करा लेंगे मैं इसकी जानकारी चाहता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कहा कि इसका डी0पी0आर0 तैयार करवाया जा रहा है। डी0पी0आर0 तैयार हो जाता है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

श्री सदानन्द सिंह : शायद हमको सुनने में गलती हुई कि क्या– माननीय मंत्री जी ने कहा कि डी0पी0आर0 बनवाकर केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजे हैं तो डी0पी0आर0 यदि

बनवाया गया है और केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है तो डी0पी0आर0 कब भेजा गया है और कितनी राशि का है ?

श्री महेश्वर हजारी : महोदय, श्रावणी मेला एवं अन्य अवसरों पर गंगा के घाटों पर बांस बैरिकेटिंग एवं चेतावनी बोर्ड लगायी जाती है। सुरक्षा नौका, नाविकों, लाइफ जैकेट आदि की व्यवस्था नगर परिषद्, सुल्तानगंज के द्वारा की जाती है। जिला स्तर पर एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 की टीम प्रतिनियुक्त रहती है। महोदय, माननीय सदस्य वर्णित घाट पर जो बोले हैं, सच्चाई बात है कि प्राक्कलन तैयार हो गया है और प्राक्कलन तैयार करके भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि तैयार हुआ तो कितनी राशि का है और कब भेजा गया है। अगर आपके पास सूचना उपलब्ध है तो बता दीजिए, नहीं तो विभाग से लेकर बता दीजिए।

श्री महेश्वर हजारी : महोदय, अभी उपलब्ध नहीं है, बाद में बता देंगे।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, या तो इस प्रश्न को स्थगित कीजिए दूसरे दिन के लिए पूर्ण जवाब लेकर आयें। महोदय, साधारण बात नहीं है सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है और राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का यह स्थल है।

अध्यक्ष : ठीक है, यह प्रश्न स्थगित हुआ। अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-410/डा0 शमीम अहमद</u>

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा : 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बनकटवा प्रखंड की बड़की पकई एवं छोटकी पकई के बीच शेखौना गांव, बिरती बाजार एवं अगरवा गांव में चापाकल के माध्यम से पेय जलापूर्ति की जा रही है। इन गांवों में निर्मित चापाकलों की संख्या निम्नवत् है। बड़की पकई संख्या 840, चापाकल-9, छोटकी पकई आबादी 1200, चापाकल की संख्या 12, शेखौना गांव 3090, बिरती बाजार 307 चापाकल 3, अगरवा गांव 2426, कुल आबादी 8700 और कुल चापाकलों की संख्या 88 इसी से जलापूर्ति की जा रही है।

डा0 शमीम अहमद : महोदय, चापाकल जो गड़ा गया है वह किसी खास आदमी के दरवाजे पर गाड़ा गया है इससे जनरल लोगों को फायदा नहीं होता है। लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि छोटा छोटा टंकी बनाकर सप्लाय किया जाय ताकि सभी लोगों को फायदा मिले।

अध्यक्ष : ठीक है।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-618/श्री विजय कुमार सिन्हा</u>

श्री महेश्वर हजारी : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बस स्टैंड लखीसराय बाइपास रोड में अवस्थित है। बाइपास रोड वर्तमान में चालू नहीं है। बाइपास रोड चालू होने पर वर्णित बस स्टैंड चालू करा दिया जायेगा।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, यह जिला मुख्यालय के बगल में है और जिला मुख्यालय अतिथिशाला के जस्ट सटा हुआ है। बाइपास सड़क पर औलरेडी छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी सब आती है और उसी के बगल में प्राइवेट जमीन पर बस स्टैंड चल रहा है। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि जब बगल में जब प्राइवेट बस खुल रहा है तो बस स्टैंड जो 6 वर्ष से बना हुआ है, समविकास योजना के लाखों रूपये की लागत से और आज उस भवन का अवैध रूप से गलत उपयोग हो रहा है अपराधियों के द्वारा। वहां मिट्टी की कटाई हो रही है, खंडहर की स्थिति बनायी जा रही है तो वहां से चालू करने में क्या समस्या है और कब तक चालू करना चाहेंगे ?

टर्न–2/अशोक/17.03.2016

श्री महेश्वर हजारी : मा. अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि स्पेशली इसको दिखवा करके शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करके चालू करवायेंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : मा. अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री, नगर विकास मंत्री है – इनके विभाग के द्वारा सही सूचना एवं जानकारी क्यों नहीं दी जाती है? और अगर नगर प्रशासक के द्वारा सूचना नहीं दी गई है, इसी तरह से कई योजनाओं में सूचना और कार्रवाई करने की भी माननीय मंत्री महोदय इच्छा रखते हैं ? ऐसी सूचना देने वालो पर ?

अध्यक्ष : शीघ्र भी बोले हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1614(श्री निरंजन कुमार मेहता)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा : इसमें समय चाहिए महोदय ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1615(श्री मों0 जावेद)

श्री महेश्वर हजारी : 1. स्वीकारात्मक है ।

2.समनपुरा जलापूर्त्ति पम्प का संचालन निर्माणकर्त्ता एजेन्सी के कर्मी के द्वारा किया जाता है । उक्त पम्प का संचालन स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप 3–4 घंटा सुबह और 3–4 घंटा शाम स्थानीय नागरिकों को जलापूर्त्ति की जा रही है ।

3. जलापूर्त्ति पम्प का परिचालन नियमित रूप से कराया जा रहा है । ऑपरेटर प्रतिनियुक्ति के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु विभागीय पत्रांक 1865 दिनांक 15.03.2016 द्वारा पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया है ।

श्री(मो.) जावेद : महोदय, यह बहुत ही घनी अल्पंख्यक की आबादी वाली कॉलनी है । माननीय मंत्री ने बतलाया कि 3–4 घंटे– जो हमारी जानकारी है दो घंटा सुबह और दो घंटा शाम और गर्मी का समय आ रहा है ये कम से कम छः घंटे सुबह और छः घंटे शाम और मैं शंक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने चिट्ठी लिखी– मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो सरकारी चालक है वह कब तक आ जायेगा ? नम्बर–दो .एक जानकारी और भी देनाा चाहता हूँ आापके माध्यम से कि ये पाईप तीन जहग टूट चुकी है और प्रेशर पूरा नहीं होने के कारण कई घरों में पानी नहीं जा पा रहा है तो क्या सरकार उस पाईप लाईन को रिप्लेस करने की मंशा रखती है ? और कबतक रखती है– ये दोनों का जवाब चाहेंगे सर आपके माध्यम से ।

श्री महेश्वर हजारी : अध्यक्ष महोदय, पानी का सवाल है, माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूॅ कि एक महीना के अन्दर इसको करवा कर कम्पलिट करा देंगे ।

श्री नितिन नवीन : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूॅ कि पटना में जो उन्होंने कहा कार्यकारी एजेन्सी के द्वारा चलाया जा रहा है, कौन सी कार्यकारी एजेन्सी के द्वारा चलाया जा रहा है ? पटना में प्राय: सभी पम्प हाऊस आम नागरिक के द्वारा चलाये जाते हैं, कई स्थानों पर पम्प ऑपरेटर नहीं है । तो माननीय मंत्री क्या यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आगामी गर्मी के दिनों में सभी जलापूर्त्ति केन्द्रों पर पम्प ऑपरेटर की नियुक्ति करेंगे ?

श्री महेश्वर हजारी : माननीय सदस्य का जो क्योश्चन था उसक उत्तर हमने दे दिया है । आप क्योश्चन कीजिये हम विस्तृत रूप से जवाब देंगे । सब का जवाब अभी मेरे पास एभेलेबुल नहीं है ।(व्यवधान)

श्री(मो.) जावेद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लेमेंट्री है, एक का तो जवाब आया कि एक महीना में वहां ऑपरेटर और पानी सप्लाई की अवधि बढ़ा देंगे लेकिन जो पाईप लाईन डैमेज है वह कितने दिनों मे करवा लेंगे ?

श्री महेश्वर हजारी : प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही न बढ़ायेंगे, प्रक्रिया पूरा करके बढ़ा देंगे, एक महीना में सब काम करायेंगे ।

श्री(मो.) जावेद : वहां पर बहुत घनी आबादी का कॉलनी है सर, तीन जगह कादा(कीचड़) है हर वक्त और उससे बीमारी फैलती है सर, इसको शीघ्र से शीघ्र, हफ्ते दिनों में करवायें - एक महीन का समय तो बहुत हो जायेगा । इसको इमिडियेट, चूंकि जल का मामला है, इसमें डिले करने की कोई गुजाईश नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मा. सदस्य नितिन नवीन जी ने जो कहा है, चूंकि अब गर्मी का समय आ रहा है और पटना में ऐसे पम्प हाऊसेज हैं, जहां पर आपके पम्प चालक नहीं हैं, वहां निश्चित रूप से देख लेना चाहिए- उन्होने अच्छा सुझाव दिया है, क्यांकि अगर प्राईवेट आदमी चलाते हैं तो कब चलाते हैं, नहीं चलाते हैं- जब तक सरकारी आदमी नहीं रहेगा तब तक सुव्यवस्थित ढ़ंग से पम्प नहीं चल सकते इसलिए इसको जरूर दिखलवा लीजिए । आपके ही बात तो कहे ।

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, बैक कॉलनी जो बनना था इससे पहले जो मोटर पम्प लगा था तो पाईप लाईन का विस्तारीकरण नहीं हुआ था ...

अध्यक्ष : इसके बारे में अभी कैसे जवाब देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1616(श्री प्रमोद कुमार)</u>

श्री महेश्वर हजारी : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है । योजना कार्यान्वित करने की कार्रवाई चल रही है । जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा औपचारिक भूमि हस्तनान्तरण की कार्रवाई चल रही है ।

श्री प्रमादे कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने दोनों खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक बतलाया है । हुजूर वर्ष 2015 में इसकी निविदा हो चुकी है और रूपया भी आवंटित हो चुका है और जिलाधिकारी के यहां प्रक्रियाधीन है, वह लगभग एक साल से प्रक्रियाधीन है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह कितने दिन की जो यह प्रक्रियाधीन है, यह कितने दिन की निविदा हुई और कितने दिन के अन्दर प्रक्रियाधीन को क्रियाधीन में बदला जायेगा–प्रक्रियाधीन को हुजूर क्रियाधीन में बदला जायेगा ? इसका टेन्डर भी हो गया और कैसे यह काम होगा मंत्री जी इसको स्पष्ट बतला दें कि क्रियाधीन कितने दिन में करेंगे ?

श्री महेश्वर हजारी : माननीय सदस्य का कहना ठीक है, समय बहुत लग गया है । मैं स्वयं, अपने स्तर से बात करके इसको जल्द से जल्द सौल्भ कराने का कोशिश करूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार : निविदा भी हो गया...

अध्यक्ष : अब तो क्रियाधीन का उपाय कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार : समय बतला दें । समय, समय ।

अध्यक्ष : जल्द से जल्द कहे । समय में बांधियेगा तो और लम्बा हो जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या––1617(श्री सुरेश कुमार शर्मा)</u>

श्री महेश्वर हजारी : महोदय, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवांत लाभ का भुगतान कर दिया गया है, अन्तर सेवांत लाभ की कार्रवाई की जा रही है, सेवानिूत्त कर्मचारियों का अन्तर वेतन फरवरी,1999 से दिसम्बर, 2014 तक का बकाया है । राशि की उपलब्धता के आधार पर अन्तर वेतन की भुगतान की कार्रवाई की जा रही है, ए.सी.पी. लाभ की भी कार्रवाई की जा रही है ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा : महोदय अभी तक बहुत ही कम लोगों का भुगतान हुआ है, लाभांश भी नहीं हुआ है और न इनको किसी तरह की सुविधा दी गई, 9 करोड़ रूपया बाकी है और हम समझते हैं कि 20 स्टाफ तो मर गये पैसे और खाने के बिना हम चाहेंगे कि इसका भुगतान कब तक करायेंगे ? हाईकोर्ट से भी इस पर

निदेश हुआ था तब भी भुगतान नहीं हुआ है तो मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि कब तक उसका करा देंगे, क्या विचार रखते हैं ?

श्री महेश्वर हजारी : अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय सदस्य को कहा है कि राशि की उपलब्धता नहीं थी इसके कारण उनका वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जब राशि की उपलब्धता हो जायेगी तो शीघ्र ही उसको भुगतान करवा दिया जायेगा ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा : महोदय, इनेको तो रजिस्ट्री ऑफिस से भी, वहां दस-दस करोड़ रूपया मिलता है और ऐसा है कि इससे भी किया जा सकता है, बहुत तरह का फंड नगर निगम में आता है जिससे कि भुगतान हेा सकता है । ये नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वहां कई बार धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल हुआ है, डी. एम. साहब ने भी इस पर निर्देश दिया था भुगतान करने के लिए- ये सुनते ही नहीं है । मेरा आग्रह है कि इन लोगों का भुगतान जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्णय रखते हैं और कबतक करेंगे ?

टर्न-3: 17-03-2016- ज्योति

श्री प्रेम कुमार : माननीय मंत्री जी बतायें वर्षों से बकाया है , 9 करोड़ रुपया बकाया है , आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ कि कबतक भुगतान करा देंगे ?

श्री महेश्वर हजारी : माननीय सदस्य को तो हमने कहा कि राशि उपलब्धता के आधार पर होती है , कोई भी राशि डायवर्ट करके कोई फंड दे देंगे , यह बात नहीं है , राशि उपलब्ध होगी, हमने अपने कहा है कि शीघ्र करा देंगें । वेतन वाला सवाल है, विकास वाला सवाल नहीं है कि दो चार दिन रुक जॉय इसलिए जल्द से जल्द करा देंगे ।

श्री प्रेम कुमार : माईक खराब है क्या जी इसमें आवाज क्यों नहीं देते हो ?

अध्यक्ष : आपके माईक में आवाज है ।

श्री प्रेम कुमार : कल से मैं देख रहो हूँ महोदय कही न कहीं से साजिश हो रही है बोलने से रोका जा रहा है, हमें लग रहा है । कल भी हमने देखा था ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष यहॅं अफवाह फैलाने वाले से सावधान रहिये । अफवाह से बचें ।

श्री प्रेम कुमार : कल भी और आज भी मैंने देखा , कई साथी कह रहे थे । हम जानना चाह रहे थे कि राशि कहॉं से आयेगी , कबतक भुगतान करा देंगें , आपका क्या प्रयास है ?

श्री महेश्वर हजारी : अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता प्रेम बाबू बहुत ही सीनियर हैं और इस विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं । जबतक विभाग से स्पष्ट जवाब नहीं आयेगा तबतक डेट हम कैसे फिक्सेशन कर देंगे । लेकिन चूँकि माननीय सदस्य ने क्वेश्चन किया वह भी वेतन के सवाल पर है, हमं स्वयं इसको अपने से देख कर जल्द से जल्द करा देंगें , यह विश्वास दिलाना चाहते हूँ , आप विश्वास कीजिये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 1618 (श्री नारायण प्रसाद)</u>

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा : 1- आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण जिला के मंगलपुर गुदरिया पंचायत में मे0 विश्वा इन्फास्ट्रक्चर द्वारा विद्युत उर्जा चालित पम्प मोटर के साथ मीनी जलापूर्त्ति योजना के तहत केवल नलकूप का निर्माण कराया गया था जो चौक हो गया था । ससमय कार्य पूरा नहीं करने के कारण मे0 विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लिमिटेड का एकरारनामा रद्द कर फर्म को काली सूची में डाल दिया गया है ।

चूँकि प्रश्नाधीन ग्राम में निर्मित नलकूप चोक्ड हो गया है इसलिए योजना कें अन्य काय अर्भी कराया जाना प्रस्तावित नहीं है । वर्तमान में उक्त ग्राम में

32 चापाकल चालू अवस्था में हैं जिससे जलापूर्ति हो रही है एवें विभागीय मापदंड के अनुरुप है ।

श्री नारायण प्रसाद : महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चहता हूँ कि 32 चापाकल का इन्होंने जिक्र किया है , आज जॉच करा लीजिये 5 चापाकल भी वहॉ चालू नहीं है जो चापाकल चालू भी है उससे पीला पानी निकल रहा है । साल भर और डेढ़ साल पहले यह लगा है । सारा चापाकल खराब है जलापूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है । इतने दिनों के बाद आजतक इनके मशीनरी के लोग काम नहीं कर सके तो 7 निश्चय में डर है कि कैसे हर गांव में जलापूर्ति यह 5 साल में कर सकेंगें ? कबतक इस योजना को लागू करेंगें , इसलिए कि आज जल ही जीवन है , अप्रील माह आने वाला है और पानी के लिए पूरे क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ है ।

श्री महेश्वर हजारी : महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह चूँकि जलापूर्ति का काम गांव गांव घर घर पहुंचाने को 7 निश्चयों में शामिल हो गया है इसलिए विभाग अब इसपर स्वाभाविक रुप से और ज्यादा सक्रिय हो गया है और 32 चापाकल की बात जो मैंने कही है रिपोर्ट में तो सदन में आने से पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फोन किया और उनसे बातें भी की है , उनका जवाब पढ़ने के बाद फोन किया और बात किया उन्होंने जो हमें जानकारी दी वही हम माननीय सदस्य को अवगत करा रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जवाब से असहमति प्रकट की है , वह कह रहे हैं कि चापाकल चालू नहीं है , जो चल रहा है उससे साफ पानी नहीं आ रहा है । इसको देखवा लीजिये और जॉच करवा दीजिये ।

श्री महेश्वर हजारी : ठीक है महोदय, इसको मैं देख लेता हूँ ।

डा0 सुनील कुमार : 7 निश्चयों में यह आ गया इसलिए निशिचित तौर पर हम पीने का पानी उपलब्ध करायेंगे । बराबर मैं देखता हूं कि अखबारों में माननीय मंत्री जी का बयान आता है कि हम घर में नल से जल देंगें लेकिन पी0एच0ई0डी0 विभाग के पास मेंटीनेंस के लिए पैसा नहीं है । हमलोगों के शहर में अगर कहीं पाईप टूट जाता है तो उसके मेंटीनेंस का पैसा नहीं है उसके बाद ये बोलते हैं कि हर घर में नल का पानी पहुंचायेंगें तो क्या ये पहुंचायेंगे क्यां ?

अध्यक्ष : ठीक है, प्रश्न संख्या ृ1619 श्री मिथिलेश तिवारी ।

श्री नारायण प्रसाद : मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी 11 साल की जलापूर्ति योजना न जमीन - घरातल पर उतर सकी है तो कैसे 5 साल के अंदर में यह पूरा होगी ?

अध्यक्ष : अब कहॉ उनके सवाल की तरफ बढ़ गए ?

तारांकित प्रश्न संख्या 1619(श्री मिथिलेश तिवारी)

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा : 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या 673 दिनॉक 12-12-2015 के द्वारा 7 निश्चयों के तहत हर घर नल का जल तथा शौचालय का निर्माण हर घर को सम्माने के तहत हर घर में शौचालय के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है अत: इस योजना के अंतर्गत वर्ष 14-15 में योजनाएं लेने का प्रश्न ही नहीं है ।

2- यह स्पष्ट नहीं है कि किस मद की राशि की चर्चा है ।

3- राज्य सरकार के 7 निश्चयं के तहत अगले 5 वर्षों में हर घर नल जल एवं शौचालय निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, यह 7 निश्चय सुनते सुनते हमलोगों का कान पक गया है और मैं .....

(व्यवधान)

हमारा प्रश्न सुनिये, 38 जिले में ।

अध्यक्ष : श्री तिवारी जी सरकार ने उत्तर में कहा है कि 7 निश्चय और हर घर नल का जल यह योजना वर्ष 2016-17 यानी आगामी वित्तीय वर्ष से लागू ही होने वाली है तो अभी आपका कान कैसे पक गया ?

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, हम उसी पर आ रहे हैं ।

(व्यवधान)

सुनिये तो पहले हम क्या कह रहे हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : पूरक पूछ रहे हैं , बिहार के 13 जिले आर्सेनिक प्रभावित हैं । बिहार के 11 जिले फ्लोराईड प्रभावित हैं । 9 जिले आयरन प्रभावित हैं और मात्र 8 जिले में पीने का पानी शुंद्ध मिल रहा है । अध्यक्ष महोदय, ओवरहेड टंकी द्वारा पानी सप्लाई की योजना बहुत पुरानी योजना है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूॅ कि पूरे बिहार में जल मिनार कितने बने , उसमें से कितने जल मिनारे चालू हैं और उस जल मिनार से कितने घर में पानी पहुंचाया जा रहा है ?

श्री श्रवण कुमार्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कान पक रहा है 7 निश्चय सुनके` तो बिहार की जनता ने थम्पिंग मैजरिटी से 7 निश्चय पर हमलोगों की सरकार बनाने और चलाने के लिए भेजा है , माननीय सदस्य का कान कैसे पक रहा है जबकि बिहार की जनता का जनादेश है ।

डा0 सुनील कुमार : यह पहली सरकार बिहार की है पूरे हिन्दुस्तान में जिसने 3 महीने में ही अपना विश्वास खो चुकी है ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : देश से महंगाई मिटा देंगे – देश की जनता का कान पक गया है और ये पहली बार विधायक बनकर आए है तो इनका कान पक गया । यह जॉच का विषय है ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : हमारे माननीय मिथिलेश तिवारी जी ने कहा है कि 7 निश्चय से मेरा कान पक गया है" मैं जानना चाहता हूँ कि भाजपा के भाइ लोगों' से कि ढाई साल हो गए इनकी सरकार ने एक नहीं दर्जनों घोषणा की और अपने मुंह से कहा कि जो मैने कहा जुमला कहा जो एक सौ करोड़ लोगों को धोखा देने वाला है ।

(व्यवधान)

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल सवाल है ।

अध्यक्ष : मिथिलेश तिवारी जी, अंतिम पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, हमने तो एक ही प्रश्न किया उसका भी जवाब नहीं आया । घर घर तक पानी पहुंचाने की योजना पुरानी है उसके लिए जल मिनार बनाया गया तो कितने जल मिनार बने, कितने घर में उससे पानी पहुंचा और कितने जल मिनार आज खराब हैं यही माननीय मंत्री जी बतला दें ।

टर्न.4/विजय/ 17.03.2016

अध्यक्ष: मिथिलेश जी आप अंतिम पूरक पूछिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, हम तो एक ही पूरक पूछे उसका जवाब ही नहीं आया ।

अध्यक्ष: तो अगला पूरक पूछिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी: हम पूछ रहे हैं कि घर घर पानी पहुंचाने की योजना बहुत पुरानी है इसलिए जल मीनार बनाया गया था तो पूरे बिहार में कितना जल मीनार बना, उससे कितने घरों में पानी पहुंचा और कितना जल मीनार आज खराब है यही माननीय मंत्री बता दें ।

(व्यवधान)

श्री नंदकिशोर यादव: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस प्रश्न को गौर से पढ़ा जाय महोदय । प्रश्न में इस बात की चर्चा की गई है कि सभी जिलों के 400 गांव में जो पाइप जलापूर्त्ति की 330 योजनाएं थी जो 2014-15 से प्रस्तावित है उसके बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था उसका कोई जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया। सात निश्चय की बात कहां से घुस गयी और उस पर बात बदल गयी महोदय लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं जो वे कह रहे हैं कि सात निश्चय अभी का कार्यक्रम है तो वे अपनी गलतफहमी दूर कर लें । महोदय मेरे पास सुशासन के कार्यक्रम 2010-2015 की कॉपी है और इसके पेज नं0-12 को महोदय पढ़ें उसमें साफ लिखा है कि, राज्य के सभी शहरों और गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मिशन मोड पर कार्रवाई की जाएगी । यह भी लिखा है फलोराइड, आर्सेनिक और आयरन प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर स्वच्छ पेयजल की आपूर्त्ति की जायगी । महोदय, जब यह कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के तहत जब 330 योजना चयनित की गई 2014-15 में उनकी स्थिति क्या है, उससे कितनों का निर्माण हुआ, उसमें 25 परसेंट राशि ही क्यों खर्च हुई सवाल यह है । मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना करते हुए जानना चाहता हूं इस सवाल का जवाब दीजिये कि जो 250 करोड़ की योजना थी आवंटित था पैसा उसमें 25 परसेंट में ही काम क्यों हुआ बाकी का क्या हुआ इसका भी जवाब दीजिये ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा: महोदय, जो प्रश्न किया गया है खंड 2 में जो प्रश्न है - क्या यह बात सही है कि पिछले डेढ़ साल में आवंटित 250करोड़ में से केवल 25 प्रतिशत की राशि भी अभी तक खर्च नहीं हो पायी है । उत्तर इसका है- यह स्पष्ट नहीं है कि किस मद की राशि की चर्चा है ।

इसके अतिरिक्त जो जानना चाहते हैं उसके लिए अलग से प्रश्न पूछें मैं जवाब दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री नंदकिशोर यादवः महोदय, प्रश्न नहीं करें क्या ? मुझे आप बताइये । अगर प्रश्न करने का अधिकार नहीं है मुझे तो मैं बैठ जाता हूं । कोई नहीं कर पायेगा प्रश्न महोदय उसके बाद।

अध्यक्षः आप पूछिये न ।

श्री नंदकिशोर यादवः मैं पूछ रहा हूं महोदय इस प्रश्न में साफ लिखा है 2014-15 की योजना हो गयी तो 2014-15 में कितनी योजना स्वीकृत की गई इसकी जानकारी प्राप्त कर मंत्री महोदय को आना चाहिए था । महोदय, मेरा आग्रह होगा आपसे बहुत स्पष्ट प्रश्न है महोदर्य वित्तीय वर्ष भी लिखा हुआ है । मंत्री महोदय ने इसकी समीक्षा नहीं की है इसलिए प्रश्न स्थगित कर दीजिये और 2014-15 की जो 330 योजनाएं हैं उन 330 योजनाओं का क्या हश्र है, क्या हाल है इसकी जानकारी प्राप्त कर मंत्री आए, अगले दिन उसका जवाब दें ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्माः महोदय, जो प्रश्न किया गया है उसका उत्तर स्पष्ट रूप से दिया गया है अब इसको उलझा कर के इसको स्थगित कराना चाहते हैं, इनकी बात समझ में नही आती है।

श्री नंदकिशोर यादवः महोदय, हम कहां उलझा रहे हैं 2014-15 का है महोदय । हम दूसरी बात नहीं कह रहे हैं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्माः दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्षः दिखवा लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री विनोद प्रसाद यादवः सुशासन के कार्यक्रम के तहत 2011 में पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार ने घोषणा की थी तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 2011 से जो माननीय मंत्री प्रभार में थे पी0एच0इ0डी0 के क्या उन मंत्रियों ने इस विषय में कोई गंभीरता से काम नहीं किया है ?

श्री नंदकिशोर यादवः यह कहां से आ गया विषय महोदय ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, प्रश्न में जो 2014-15 के लिए 400 ग्राम में 330 योजनाओं के संबंध में कहा गया है उसके संबंध में आप जानकारी कराके माननीय सदस्यों उपलब्ध करा दें ।

श्री नंदकिशोर यादव: महोदय, मुख्य प्रश्न का जवाब ही नहीं आएगा तो क्या मतलब होगा । ये जवाब लेकर आए, ये प्रश्न का जवाब लेकर आएं न । आखिर महोदय होगा क्या इसका । आखिर हम प्रश्न करते क्यों हैं । प्रश्न इसलिए करते हैं महोदय कि जवाब मिले । अगर जवाब ही नहीं मिलेगा तो मतलब क्या है प्रश्न करने का ।

अध्यक्ष: उसके लिए तो जवाब दिलवाने के लिए ही तो कहा है ।

श्री नंदकिशोर यादव: कह रहे हैं 2011 की बात उनको मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री 11 महीने तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस विभाग के मंत्री थे उसका जवाब पहले खोज कर लाइये । भाषण दे रहे हैं आप । महोदय सही कह रहे हैं महोदय, इसका जवाब चाहिए प्रश्न का जवाब चाहिए ।

अध्यक्ष: जवाब आ जाएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1620 (श्री अरूण कुमार सिन्हा)

श्री महेश्वर हजारी: महोदय क्वेश्चन ट्रांसफर हो गया है परिवहन विभाग में ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: उत्तर को जरा एक बार फिर से पढ़िये ।

अध्यध: परिवहन विभाग में स्थानान्तरित हुआ है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1621 (श्री रमेश ऋषिदेव)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा: महोदय, क. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की मार्गदर्शिका के अनुसार सामुदायिक शौचालय का निर्माण तब किया जाएगा जब वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए गांव में जगह की कमी हो और समुदाय/ग्राम पंचायत उनके परिचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी ले तथा इसके लिए विशिष्ट मांग करे । मार्गदर्शिका के अनुसार दो लाख तक की राशि का सामुदायिक शौचालय का निर्माण लाभार्थियों के 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान अर्थात 20 हजार के साथ मांग प्राप्त होने पर किया जा सकता है । मधेपुरा जिला के कुमारखंड, सिंहेश्वर एवं शंकरपुर प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2013-14 में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु समुदाय/ग्राम पंचायतों से लाभार्थी अंशदान के साथ मांग अनुरोध प्राप्त नहीं होने के कारण इन प्रखंडों में 2013-14 में सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है। इन प्रखंडों में लाभार्थी अंशदान के साथ मांग प्राप्त होने पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा दिया जाएगा ।

ख. अस्वीकारात्मक है । स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राशि जिला जल एवं स्वच्छता समिति के बैंक खाते में रखी जाती है जिसे इस अभियान के प्रावधान के तहत उपयोग किया जाता है ।

सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु अलग से कोई राशि जिला पदाधिकारी के पास नहीं रखी जाती है ।

ग. उत्तर उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री रमेश ऋषिदेवः महोदय, सामुदायिक शौचालय किसी एजेंसी के द्वारा पी0एच0इ0डी0 विभाग के एक्जीक्यूटिव ने 2013-14 और 2014-15 में काम करवाया है । जिला के अनुश्रवण समिति की बैठक में हम इस सवाल को उठाये तो पी0एच0इ0डी0 विभाग के एक्जीक्युटिव ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में दो दो सामुदायिक शौचालय हम बनवायें हैं । तो अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री का यहां से चिट्ठी नहीं गया और पैसा यहां से नहीं गया तो कैसे काम उसने करा लिया और किस एजेंसी से करवाया है काम ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्माः महोदय, उत्तर में स्पष्ट रूप से मैंने कहा प्रश्न में है कि- क्या यह सही है कि उक्त प्रखंडों के शौचालय निर्माण की रशि वर्ष 2014 से मधेपुरा जिला पदाधिकारी के पास पड़ा हुआ है ?

ऐसी बात नहीं है, वह राशि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राशि जिला जल स्वच्छता समिति के बैंक खाते में रखी जाती है जिसे इस अभियान के तहत उपयोग किया जाता है ।

टर्न–5/बिपिन/17.3.2016

श्री रमेश ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक शौचालय जिला में बना है और जिला के अनुश्रवण समिति की बैठक में भी उठाए थे । काम नहीं हुआ है और पैसा उठा लिया गया है । जो सबूत है, यदि आदेश हो तो जिला से रेकर्ड मंगवाए हैं, वह आपको जमा करवा देंगे ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा: हम इसको दिखवा लेते हैं महोदय ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदय, यह जो शौचालय निर्माण होती है पंचायत में, व्यवहारिकता में हमलोग भी देखते हैं कि इसमें एक रैकेट बना हुआ है और चूँकि राशि अधिक होती है तो 20 प्रतिशत राशि लाभुक को देना पड़ता है तो उससे सिर्फ सहमति लिखवाता है। माननीय प्रश्नकर्त्ता का जो प्रखंड है तो उसमें भी माननीय मंत्री जी कहते हैं कि नहीं बना है । जो शौचालय निर्माण पहले से है, उसे दिखाते हैं कि हम बनाए हैं । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं, वैसे माननीय मंत्री जी का उत्तर तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पदाधिकारी जवाब वहां से भेजे । जब प्रश्न हुआ तो कह दिया कि हम बनाए ही नहीं हैं । तो ये किसी पदाधिकारी से, पी.एच.इ.डी. छोड़कर डी.एम. या किसी दूसरे आफिसर से जांच करवा ली जाए कि इस तरह के शौचालय बनवाए थे और प्रश्न के आने के बाद वे मुकर गए तो यह तो बहुत निन्दनीय बात है । तो क्या माननीय मंत्रीजी उसका जांच करा लेंगे जिला स्तर के पदाधिकारी से, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि अनुश्रवण समिति की बैठक में वही एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कहता है कि बनवाए हैं और जब प्रश्न गया तो कहता है कि हम बनवाए ही नहीं हैं । इसीलिए वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच करवा लेंगे क्या ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा: महोदय, माननीय सदस्य की भावना को मैं समझ रहा हूं और व्यक्तिगत् रूचि लेकर जो वहां के पदाधिकारी हैं, उनसे इसपर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहता हूं और असंतुष्ट होने पर मैं इसकी जांच भी करवा दूँगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । प्रश्न सं0–1622

श्री विनोद कुमार सिंह: महोदय, मैं व्यवस्था के सवाल पर हूं ।

मेरी व्यवस्था है कि माननीय मंत्री जी जो जवाब देते हैं तो जवाब में यह कहते हैं 'दिखवा लेंगे', 'दिखवा लेंगे' तो 'दिखवा लेंगे' शब्द को विलोपित करके, 'करवा देंगे', यह शब्द जोड़ा जाए ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0: 1622 (श्री सुदामा प्रसाद)</u>

श्री महेश्वर हजारी: अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

2. वर्त्तमान में ऐसी कोई कार्य–योजना नहीं है । भविष्य में इस संबंध में कार्य–योजना बनाकर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री सुदामा प्रसादः महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक यह योजना बनेगी ?

श्री महेश्वर हजारीः महोदय, चूँकि ग्रामीण इलाका है और अभी शहरी इलाका में चल रहा है ...

श्री सुदामा प्रसादः शहर है, शहर है । नगर पंचायत है वह ।

श्री महेश्वर हजारीः तो पहले अभी नगर निगम में यह योजना चल रहा है, बाद में वहां पर हमलोग चलाएंगे तो उसके बाद चिंहित करके वहां पर कार्य करवा दिया जाएगा ।

तारांकित प्रश्न सं0: 1623 (श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

श्री महेश्वर हजारीः अध्यक्ष महोदय, विभागीय पत्रांक सं0-2 दिनांक 4.1.2016, पत्रांक-600 दिनांक 25.1.2016 एवं पत्रांक-1113 दिनांक 19.3.2016 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों से 2011 की जनगणना के आधार पर विस्तृत प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निकाय गठन के संबंध में विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2004 में मेरे इस प्रश्न पर उस समय के मंत्री जी ने वायदा किया था कि बसंतपुर को नगरपालिका की दर्जा दे दी गई है और अभी इन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर समाहर्त्ता से रिपोर्ट की मांग की गई है ।

मेरा कहना है कि जब 2004 में यह घोषणा कर दी गई तो उसे कार्य-रूप क्यों नहीं दे दिया गया ?

श्री महेश्वर हजारीः अध्यक्ष महोदय, 12000 जनसंख्या वाले जितने भी पंचायत हैं, उसको हमलोग नगर पंचायत का दर्जा देने के लिए घोषणा किए हैं लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है, वहां के जिला समाहर्त्ता से, जब तक एरिया वहां से उस पंचायत की नहीं आ पाएगी, तब तक कैसे घोषणा कर सकते हैं, इसलिए प्रतिवेदन मांगा गया है जिला समाहर्त्ता से और आने के बाद शीघ्र उस पर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, उस पंचायत में बाजार में मेरा घर है, उसकी जनसंख्या 13000 है । वह मुख्यालय है । सब कुछ वहां है । कोई सरकारी निकाय वहां बाकी नहीं है । कलक्टर साहब का रिपोर्ट आएगा, 2004 में जो रिपोर्ट दिया कि वह नगरपालिका के लायक बाजार है, वह बाजार लाखों-करोड़ों रूपया टैक्स देता है और उस बाजार में नगरपालिका नियमानुकूल बनना चाहिए और कलक्टर साहब से कब प्रतिवेदन मांगेंगे ? जब प्रतिवेदन नहीं आया तो जवाब कैसे आ गया ?

अध्यक्ष : रिपोर्ट शीघ्र मंगवा लीजिए ।

श्री महेश्वर हजारीः महोदय, इससे पहले दो-दो पत्र लिखा गया । एक बार 4.1.2016 को लिखा गया है, फिर जब दुबारा माननीय सदस्य कोश्चयन किए हैं तब फिर 19.2.2016

को पत्र लिखा गया है । पत्र आने के साथ ही उक्त प्रतिवेदन पर हमलोग विचार करेंगे ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में बसंतपुर बाजार को नगरपालिका का दर्जा दे देंगे ?

अध्यक्ष: इस वित्तीय वर्ष में कहां से होगा ? आपके प्रश्न के महत्व को देखते ही मंत्री जी ने कहा है कि हम इस पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0: 1624 (श्री अशोक कुमार)

श्री महेश्वर हजारी: अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । करनसराय के मदरसा रोड के अगल-बगल निजी मकान में गोदाम होने के कारण भारी वाहन में लगे फल को निकासी के क्रम में कभी-कभी मार्ग अवरूद्ध होता है । स्थल का चयन किया जा रहा है । स्थल प्राप्त होते ही प्रारभ्भिक स्थल से फल मंडी हटाने की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री अशोक कुमार: अध्यक्ष महोदय, नगर पर्षद में रेसिडेन्शियल प्लेस अलग होता है और कॉमर्शियल प्लेस अलग होता है । माननीय मंत्री ने अपने सवाल में स्वीकार किया है कि वहां पर गोदाम है और माल निकालने में रास्ते अवरूद्ध हो जाते हैं और इन्होंने यह भी कहा कि जगह मिलने पर, तो वहां तो 40एकड़ का बाजार समिति है । रेसिडेन्शियल प्लेस पर व्यापार करने का कोई औचित्य नहीं है और पूरा रोड जाम रहता है, नाला जाम रहता है फल गिरने से, इसलिए बाजार समिति में स्थानान्तरित करने का आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री महेश्वर हजारी: महोदय, हमने जवाब में पहले ही कहा है..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि क्या सड़क पर जो बाजार लगता है उसको सरकार बाजार समिति प्रांगण में स्थानान्तरित करना चाहती है ?

श्री महेश्वर हजारी: अध्यक्ष महोदय, हमने जवाब में पहले ही कहा कि स्थल प्राप्त होते ही प्राभ्भिक स्थल से फल मंडी हटाने की कार्रवाई करेंगे ।

श्री अशोक कुमार: अध्यक्ष महोदय, बाजार समिति ऑलरेडी है । बाजार समिति वहां अवस्थित है । जगह खोजने की आवश्यकता नहीं है । सरकार की नीयत वहां से हटाने की होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं जगह की उपलब्धता का, उसको सरकार ग्रहण करे और उसकी जांच कराकर देखवा ले कि वहां जा सकता है कि नहीं ।

श्री अशोक कुमार: अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अशोक कुमार: जी । सुन लें ।

अध्यक्ष : क्या है व्यवस्था ? कौन नियम का उल्लंघन है ? आप कुछ बता रहे हैं या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री अशोक कुमार: सुना जाए महोदय, 'दिखवा लेंगे' कोई बात नहीं है सर । या सरकार कहे कि मैं कराउँगा या नहीं कराउँगा । 'दिखवा लेना' कोई संसदीय शब्द नहीं है । सरकार इस बात के लिए है कि वह करेगी काम कि नहीं करेगी, लेकिन दिखवा लेना, यह बीच का रास्ता है ।

श्री महेश्वर हजारी: अध्यक्ष महोदय, सरकार नियम पर चलती है, किसी के दबाव पर नहीं चलती है ।

टर्न–6/राजेश/17.3.16

श्री अशोक कुमारः– अध्यक्ष महोदय, दबाव की बात नहीं है, माननीय मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं, इनको काम करने की नीयत होनी चाहिए.....(व्यवधान)

अध्यक्षः– माननीय सदस्य अशोक जी, आप अंतिम बात कह लीजिये।

श्री अशोक कुमारः– महोदय, सरकार की नीयत जनता के काम की होनी चाहिए, यह कहना की हम नहीं करेंगे, नीयत अच्छी नहीं है, स्थानीय विधायक होने के नाते जब मैं जमीन दे रहा हूँ तो ये कहें कि मैं वहाँ पर स्थापित करुंगा।

अध्यक्षः– मा0 सदस्य अशोक जी, जब सरकार ने कह दिया कि आपके सुझाव की जांच कराकर कार्रवाई करेगी, तो आपका सुझाव क्या है, बिना उसकी जांच कराये, बिना उसको दिखाये, कह देगी कि करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई सुझाव माननीय सदस्य दें और सरकार कह दे कि हम करा दिया, ऐसा कभी नहीं होता है,सरकार बिना जांच कराये कैसे कहेगी ?

<u>तारांकित प्रश्न संख्याः–1625(श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव)</u>

श्री राम विचार रायः– महोदय, 1:– रब्बी वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार द्वारा गेहूं के तीन पटवन एवं रब्बी के दो पटवन के लिए डीजल अनुदान के निर्णय की स्वीकृति दिनांक 27.11.2015 को मंत्रिमंडल द्वारा दी गयी है।

2:– जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–878, 879 एवं 880 दिनांक 9.12.2015 द्वारा मीनापुर प्रखंड को रब्बी वर्ष 15–16 में डीजल अनुदान मद में 35 लाख 56 हजार 400 रुपये की राशि उप–आवंटित की गयी। मीनापुर प्रखंड में डीजल अनुदान हेतु कुल 8323 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 7653 आवेदन सत्यापित किये गये। सत्यापित आवेदनों में से 5579 किसानों के खाते में 28 लाख 45 हजार 803 रुपया आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 29.1.2016 से 10.3. 2016 तक भुगतान किया गया है। शेष 2014 सत्यापित आवेदनों के भुगतान की इसी वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादवः– अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि जिस 28 लाख 45 हजार रुपये की बात इन्होंने कहा है कि किसान के पास चला गया, प्रखंड से दिसम्बर का पत्रांक–416 दिनांक 29.1.2016 को 13 लाख 21 हजार रुपया गया, फिर पत्रांक–417 से 29.1.2016 को 35 लाख रुपया गया, फिर पत्रांक–937 से 8 लाख 78 हजार 95 हजार गया और फिर पत्रांक–938 से 13 लाख 40 हजार 250 रुपया गया, यह पैसा केवल महोदय

बैंक में गया और अभी तक किसानों का रब्बी फसल जो अब कटने के कगार पर है,एक भी किसान के खाते में अभी तक एक रुपया भी नहीं गया और यहॉ तक महोदय कि पिछला खरीफ का पैसा जो प्रखंड में गया है,उसका भी एक पैसा अभी तक मीनापुर प्रखंड में नहीं बॅटा है, तो क्या माननीय मंत्री महोदय बताना चाहेंगे कि जिस पदाधिकारी ने गैर जवाबदेही का काम किया है,क्या उसपर कार्रवाई करेंगे और जितना जल्द से जल्द हो सके किसानों को अनुदान बॅटवायेंगे ?

श्री राम विचार राय:- महोदय, मैंने बताया कि किस पत्रांक एवं दिनांक के द्वारा राशि दी गयी है लेकिन माननीय सदस्य का यह मानना है कि वहॉ पहुंचा नहीं है, बैंक में है, तो इसकी जांच हम जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से कराकर इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान करा देंगे।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव:- महोदय, उस पदाधिकारी का क्या होगा, जो पदाधिकारी इतना गैर जवाबदेही का काम किये है ?

श्री राम विचार राय:- उसको भी देखेंगे,उसपर भी कार्रवाई करायेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार:- महोदय, यह पूरे राज्य भर का मामला है। हमारे मोतिहारी में भी पूछ लिया जाय, कहीं भी किसानों को राशि नहीं मिली है तो क्या माननीय मंत्री महोदय जो अनुदान की राशि किसानों के बीच नहीं बॅटी है,उसकी जांच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

तारांकित प्रश्न संख्या:-1626 (श्रीमती कुंती देवी)

श्री अवधेश कुमार सिंह:- अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत नीमचक बथानी प्रखंड मुख्यालय में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय नीमचक बथानी विभागीय संकल्प संख्याा-2255 दिनांक 24.8.2012 के आलोक में वर्तमान समय में सरकारी भवन नहीं होने के कारण किराये के मकान में संचालित है। यहॉ पशु चिकित्सा का कार्य किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि उपलब्ध होने पर भवन का भी निर्माण करा दिया जायेगा।

श्रीमती कुंती देवी:- महोदय, पशु चिकित्सालय नहीं रहने के कारण बहुत पशु मर रहे हैं, वहॉ इसके इलाज की व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष:- माननीय मंत्री जी इसको देख लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या:- 1627 (श्री सैयद अबु दौजाना)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा:- महोदय, उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत चेरौत प्रखंड के भंटावारी पंचायत के ग्राम जमुनिया की

जनसंख्या 1108 है, इसके लिए 10 चापाकल चालू अवस्था में है एवं जलापूर्ति हो रही है,जो विभागीय मापदंड के अनुरुप है।

श्री सैयद अबु दौजाना:- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जो बता रहे हैं कि 10 चापाकल चालू है तो इसकी इनक्वायरी करा लिया जाय, कोई चापाकल नहीं चल रहा है और दूसरा जो क्वेशचन हमारा है कि जलमीनार कब तक बनकर तैयार होगा और कब से चालू होगा।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा:- महोदय, जलमीनार के निर्माण का जहॉ तक सवाल है, यह 7 निश्चय वित्तीय वर्ष में जो हमारा है और उसमें चालू जब होगा, तो स्वाभाविक रुप से यह सब बनना शुरु हो जायेगा, इसलिए तब तक के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, चूंकि यह सात निश्चय में इनक्लुडेड है, कोई परेशानी की बात नहीं है,पाईपलाइन से पानी की व्यवस्था हमलोग कर रहे है।

तारांकित प्रश्न संख्या:- 1628 (श्री अचमित ऋषिदेव)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा:- महोदय, उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के कोशिकापुर दक्षिण पंचायत के कोशिकापुर ग्राम की आबादी 4435 है, इसके लिए 26 चापाकल चालू अवस्था में है, जिससे जलापूर्ति की जा रही है,जो विभागीय मापदंड के अनुरुप है। लौह प्रभावित क्षेत्रों में चरणबद्व तरीके से ट्रीटमेंट यूनिट के साथ जलापूर्ति योजना लिये जाने का कार्यक्रम है, तदनुसार प्रश्नाधीन ग्राम की भी कार्रवाई की जायगी।

श्री अचमित ऋषिदेव:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि रानीपुर प्रखंड के कोशिकापुर ग्राम में सरकार आयरन तथा भारी तत्वों को दूर करने वाला वाटर प्यूरिफाई प्लांट कब तक लगाना चाहती है ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा:- महोदय, मैंने बताया कि यह कार्यक्रम में शामिल है, इसलिए थोड़ा सा वक्त की जरुरत है, यह काम तो स्वाभाविक रुप से चालू हो जायेगा।

अध्यक्ष:- प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाए।

टर्न–07/कृष्ण/17.03.2016

कार्य–स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,

आज दिनांक 17 मार्च,2016 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कुल 7 कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :–

माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार खेमका, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विद्या सागर केसरी, श्री अशोक कुमार सिंह एवं श्री जिवेश कुमार ।

आज दिनांक 17 मार्च,2016 को सदन में वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांग में से ऊर्जा विभाग की मांग पर वाद–विवाद तथा मतदान होने कार्यक्रम निर्धारित है । बिहार विधाान–सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 99 (प) (पप) के तहत उपर्युक्त सभी कार्य–स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज ऊर्जा पर बहस होगी । लेकिन माननीय सदस्यों ने जो कार्य–स्थगन दिया है, वह स्वास्थ्य पर है । पूरे राज्य की स्वास्थ्य सेवायें चरमरा गयी है । न डाक्टर हैं और न दवा है । हमारे माननीय सदस्यों ने कार्य–स्थगन लाया है और 105 के तहत हमलोगों ने वाद–विवाद के लिये भी आग्रह किया है कि पूरे राज्य में महोदय, स्वास्थ्य सेवायें चरमरा गयी है, न दवा है, न डाक्टर है और गरीब आदमी जो हैं, दवा के अभाव में उनकी जान जा रही है । हमारे माननीय सदस्य विस्तार से बातों को बतायेंगे ।

अध्यक्ष : शून्यकाल । श्रीमती गायत्री देवी ।

शून्यकाल

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के रीगा थाना क्षेत्र के मझौड़ा मोड़ के निकट दिनांक 16.03.2016 को

(व्यवधान)

(इस अवसर पर भाजपा के सभी मा0 सदस्यगण अपनी–अपनी जगह पर खड़े हो कर बोलने लगे ।)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष हर दिन कुछ न कुछ नये सवाल को उठाते हैं । सवाल को उठाने का जो नियम है महोदय, उसका अनुपालन लगातर नहीं

हो रहा है । प्रश्नकाल चला है और शून्यकाल बाधित करने के मूड में से लोग हैं । तो मैं नेता,प्रतिपक्ष से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार तो जवाब देने के लिये तैयार है । लेकिन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के आलोक में उठाईयेगा, तभी न उसका जवाब मिलेगा । रोज कोई न कोई सवाल ऐसे उठा रहे हैं । महत्वपूर्ण सवाल है, उसके उठाने के लिये नियमावली बना हुआ है । खाली ये अखबार की सुर्खियों में जाना चाहते हैं, इससे बिहार की जनता की समस्या का हल होनेवाला नहीं है ।

अध्यक्ष : श्रीमती गायत्री देवी । शून्यकाल पढ़िये ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के रीगा थाना क्षेत्र के मझौड़ा मोड़ के निकट दिनांक 16.03.2016 को दाल व्यवसायी मोहन प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है।

हत्यारे की गिरफ्तारी कर स्पीडी ट्रायल चलाने एवं मृतक के आश्रित को 10 लाख रूपया मुआवजा की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती प्रखंड के सावठ पंचायत में योजना के नाम पर वर्ष 2008, 2009, 2010, 2011 में 18,85,942/–रू0 निकाल लिया गया है और योजना में काम नहीं किया गया है, जिसमें 8,21,000/–रू0 की प्रशासनिक स्वीकृत भी नहीं है । मैं सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड के तोल–ढेंगों रोड से गोगो, तोल ढेंगों रोड से बैरिया, नबीनगर–वारून रोड से वरूआ, जयपुर रोड से सहरसा, बरडीहा रोड से लखनपुर तथा बारून प्रखंड के बारून–दाउदनगर रोड से महथा–रामगुलाम बिगहा तथा नबीनगर–बारून रोड से परसा रोड का पक्कीकरण करावें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला के महम्मदपुर से मलमलिया (सिवान) जानेवाली मुख्य सड़क अत्यंत ही जर्जर हो चुकी है, पूरे सड़क में गड्ढे नजर आ रहे हैं। आये दिन इस सड़क पर दुर्घटना हो रही है । लगभग 22 कि0मी0 की दूरी के इस मुख्य सड़क की मरम्मति अविलंब की जाय ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला के रतनी फरीदपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत पंडौल के ग्राम पति विगहा, बन्धु विगहा,तुला विगहा में विद्युतीकरण नहीं होने से आम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

अत: इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रश्नाधीन गांवों के विद्युतीकरण की मांग करता हूं ।

(इस अवसर पर भाजपा के सभी माननीय सदस्यगण वेल में आकर नारा लगाने लगे ।)

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, 7 मार्च राात्री में दरभंगा सदर थानान्तर्गत सारामोहनपुर गांव में 8 अवैध बंगलादेशी फर्जी पासपोर्ट एवं अन्य अवैध सामग्री के साथ गिरफ्तार किये गये, कांड संख्या 20/16 धाारा 170, 120(बी), 12 पासपोर्ट अधिनियम, 14 विदेशी अधिनियम दर्ज हुआ है । मामले की गंभीरता को देखते हुये उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर अनुमंडल जिला बनने का सारी अर्हता पूरा करता है क्योंकि यहां अनुमडल,व्यवहार न्यायालय एवं जेल भी पूर्ण रूप से कार्यरत है ।

अत: इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं दाउदनगर को जिला बनाने की मांग करता हूं ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, मोतिहारी जिला के पकड़ीदयाल अनुमंडल के अनुमंडलीय अस्पताल में एक भी महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति नहीं रहने से बड़ी आबादी को इलाज कराने में परेशानी होती है । अत: अनुमंडलीय अस्पताल में महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति कराने की कृपा की जाय ।

(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के अंदर छूटे हुये विधवा तथा वृद्धा लोगों का नाम पेंशनधारी की सूची में जोड़ने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिला के प्रखंड नरकटियागंज में चांदनी चौक से अनुमंडल मुख्यालय तक लगभग 10 सड़े हुये जर्जर लोहे का पोल एवं नंगे तार को गार्ड वायर तार के साथ बदलने की मांग करती हूं ।

श्री बशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम में कलेक्टेरियट एवं मुख्य बाजार के पास बस डिपो होने से प्रतिदिन घंटो जाम लगा रहता है, जिससे शहरवासियों एवं आम जनता के आवागमन में कठिनाई होती है ।

सरकार से मांग करता हूं कि बस डिपो को सासाराम शहर से बाहर निर्माण कराया जाय ।

(व्यवधान)

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, रोहतास प्रखंड के कोड़ियारी, हरेया, करपफूट्टी, बलूआही, पिपरडीह सहित दर्जन गांव चेचक के प्रकोप से तबाह है, न डाक्टर जा रहे हैं, न दवा मिल रही है ।

सरकार से मांग करते हैं कि उक्त ग्रामीणों को इस चेचक के महामारी से बनवासी आदिवासी को दवा व्यवस्था कर जान बचायें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी शहर के बीचाबीच बस स्टैंड रहने के कारण बुरी तरह से जाम होता है ।

अतः मधुबनी शहर से बाहर बस स्टैंड ले जाने की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णियां जिला आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का मानदेय 8 महीना से बंद है, केन्द्र का भाड़ा दो साल से बकाया, आगनबाड़ी केन्द्र भवन शहर में बनाने, सेविका को फैलेक्सी का भुगतान शहरी क्षेत्रों में रिक्त पदों पर बहाली एवं पोषाहार की राशि बाजार भाव से करने हेतु मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

टर्न–8/सत्येन्द्र/17–3–16 .

(व्यवधान)

श्री विनोद प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय,गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के शेखपुरा से घाघर होते हुए झारखंड सीमा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्माणाधीन सड़क का निर्माण कार्य संवेदक द्वारा जमीन का गलत प्रतिवेदन दिलवाकर कार्य बंद कर दिया गया है।

अतः वरीय पदाधिकारी से जांच कराकर सड़क निर्माण कराने की मांग करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री सी0एन0 गुप्ताः अध्यक्ष महोदय,छपरा के सदर अस्पताल में,तत्कालीन विधान पार्षद श्री रघुबंश प्रसाद यादव के पार्षद मद का 2008 में विशाल पेईंग वार्ड बनकर तैयार हुआ किन्तु अबतक उसका उपयोग इस रूप में नहीं हो सका है।

अतः सरकार,पेइंग वार्ड के सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करे।

मो0 नेमातुल्लाहः अध्यक्ष महोदय,गोपालंगज जिला के मांझा प्रखंड के नेमुइयां ग्राम में दिनांक 16–3–16 को भीषण आग लग जाने के कारण लगभग 152 घर जलकर राख हो गया हैं लोगों को कपड़ा लत्ता,अनाज,आभूषण सभी कुछ जल गया। जीवन चलाने के लिए कुछ नहीं बचा है।

अतः सरकार से आग्रह है कि नेमुइयां ग्राम के लोगों को उचित मुआवजा एवं तत्काल रहने की व्यवस्था शीघ्र की जाय।

श्री विजय कुमार सिन्हाः महोदय,लखीसराय सहित पूरे राज्य में बिजली बिल मीटर रीडिंग लेने वाले प्राइवेट कर्मियों की लापरवाही से अधिक दिया जा रहा है तथा बिल कम कराने के नाम पर बिचौलियों द्वारा अवैध राशि की वसूली की जाती है।

अतः ऐसे पदाधिकारियों एवं कम्पनियों पर कार्रवाई की मांग करता हूँ।

(व्यवधान)

डॉ0 सुनील कुमारः अध्यक्ष महोदय,नालंदा जिला मुख्यालय,बिहारशरीफ महिला थाना कांड संख्या 15/16 के अभियुक्त राजवल्लभ यादव एवं सुलेखा देवी को नालंदा पुलिस बचाने की साजिश कर रही है।

अतः उपरोक्त कांड की जांच केन्द्रीय अन्वेषण संस्थान से कराने हेतु मैं शून्यकाल में सूचना देता हूँ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय,डी0एम0सी0एच0,दरभंगा में भर्त्ती सदर प्रखंड लोआम पंचायत निवासी मो0 मुमताज की गर्भवती पत्नी नर्गिस खातुन के साथ डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरतने एवं मारपीट के साथ अमानवीय व्यवहार के कारण अस्पताल में ही दिनांक 13-3-16 को मुत्यु हो गयी।

अतः लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई करते हुए मृतक परिजन को मुआवजा की मांग करता हूँ।

श्री प्रहलाद यादवः महोदय,लखीसराय जिला के वुधौली बनकर एवं उरैन पंचायत के दर्जनों गांव में पेयजल संकट है। सरकार से मांग है कि उक्त पंचायत के गावों में पेयजल हेतु पानी टंकी की व्यवस्था करें।

(व्यवधान)

श्री विद्या सागर केसरीः महोदय,अररिया जिलान्तर्गत फारविसगंज प्रखंड के परमेश्वर सोनी,जोगवनी राजू मेहता एवं पंकज दास बथनाहा,रामवृक्ष मेहता टेढ़ी मुसहरी, हृदयलाल वर्मा,आरटीमोहन पंचायत निवासी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गयी। जो परिवार के भरण पोषण का एकमात्र माध्यम थे। सरकार द्वारा उपरोकत्त परिवार को न्यूनतम चार लाख रू0 मुआवजा दिया जाय।

श्री जिवेश कुमारः महोदय,दरभंगा जिलान्तर्गत जाले प्रखंड के मुरैठा गांव में दिनांक 16-8-12 को अतिरिक्त स्वास्थ्य उप केन्द्र का शिलान्यास किया गया,जो दिनांक 24-2-13 को संवेदक द्वारा तैयार भी कर दिया गया। निर्माण कार्य पूर्ण हुए 3 साल से ऊपर होने पर भी इसे चालू नहीं किया गया। अतः इसे अबिलम्ब चालू किया जाय।

(व्यवधान)

<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य</u>

श्री नौशाद आलम,श्री वीरेन्द्र कुमार एवं अन्य छः सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार(शिक्षा विभाग)की ओर से वक्तव्य।

श्री नौशाद आलमः अध्यक्ष महोदय,राज्य सरकार ने 2459+1 कोटि के मदरसों को अनुदान की श्रेणी में शामिल किया है। सभी अर्हताएं पूरी करने के बावजूद बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्वीकृति दिये गये 339 मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने हेतु 2459+1 मदरसों के साथ भूलवश सचिव,बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड,पटना ने शिक्षा विभाग,बिहार,पटना को नहीं भेजा। विशेष निदेशक के पत्रांक 10/व1-07/2014 -1015 दिनांक 12-12-14 में प्राप्त निदेश पर सचिव,बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना ने अपने पत्रांक 474 दिनांक 21-1-15 के द्वारा शिक्षा विभाग को 339 मदरसों की सूची उपलब्ध करायी। लेकिन एक वर्ष के उपरांत अबतक इन मदरसों को अनुदान की श्रेणी में नहीं लाया गया है जिससे बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो गया है।

अतः उपरोक्त 339 मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।

टर्न–9/मधुप/17.3.16

(व्यवधान)

श्री अशोक चौधरी : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अन्तर्गत प्रस्वीकृत 2459+1 कोटि के मदरसों के अतिरिक्त 2459+1 कोटि के मदरसों के मामले पर ही विचार करने का निर्णय लिया गया है । उक्त 2459+1 कोटि के मदरसों में 339 कोटि का मदरसा सम्मिलित नहीं है ।

राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1128 मदरसा में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को देय वेतनमान के आधार पर भुगतान किया जाता है तथा 2459+1 कोटि के अन्तर्गत 205+609 अर्थात् 814 प्रस्वीकृत मदरसा को नियत वेतन दिया जाता है । 2459+1 कोटि के अन्तर्गत शेष बचे 1646 मदरसों को ही अनुदान की श्रेणी में लाया जाना है । इन 1646 मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने के उपरान्त ही किसी अन्य मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने पर विचार किया जायेगा ।

श्री नौशाद आलम : अध्यक्ष महोदय, 2034 शिक्षकों के भविष्य का सवाल है । 29 साल हो गये, 29 साल से वे लोग कार्यरत हैं । अगर जल्द यह नहीं किया जायेगा तो उनलोगों का भविष्य खतरे में पड़ जायेगा, जबकि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29.12.1980 की सारी शर्त्तों को यह पूरा करता है । जब 2459+1 मदरसों को दिया जा रहा है तो 339 को भी दिया जाना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्रीमती पूर्णिमा यादव, श्री अशोक कुमार सिंह एवं श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्रीमती पूर्णिमा यादव : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के रोह प्रखंड का अनुमंडल रजौली है, जिसकी दूरी 50 किलोमीटर है । रोह से रजौली नवादा होकर जाना पड़ता है । जनता को रोह से पहले नवादा आना पड़ता है फिर सवारी बदलकर रजौली जाना पड़ता है, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । छोटे से काम हेतु भी इन्हें दिनभर का समय व्यतीत करना पड़ता है साथ ही अधिक भाड़ा का भी भुगतान करना पड़ता है । रोह प्रखंड का अनुमंडल नवादा सदर हो जाने पर अनुमंडल की दूरी मात्र 15 किलोमीटर हो जाती है ।

अतः रोह प्रखंड को नवादा सदर अनुमंडल से जोड़ने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण प्रदेश में नए प्रमण्डल, जिला, अनुमंडल, प्रखण्ड या अंचल बनाने या पुनर्गठन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अतः रोह प्रखण्ड को रजौली अनुमंडल से हटा कर नवादा सदर अनुमंडल में जोड़ने का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

श्रीमती पूर्णिमा यादव : अध्यक्ष महोदय, यह जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में नहीं तो अगले वित्तीय वर्ष तक जरूर यह काम करा देंगे ।

(व्यवधान)

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री कपिल देव कामत : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 146(2) के तहत बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 / बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जांच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014 / बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (अधिसूचना सं0-59, दिनांक 01.04.2015) / बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (अधिसूचना सं0-2516, दिनांक 05.05.2015) / बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मैं सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में दर्ज विभिन्न वर्षों की कंडिका आपत्तियों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या- 590, 591, 592 एवं 593 (स्वास्थ्य विभाग) को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम '239' के अन्तर्गत सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल)

टर्न–10/आजाद/17.03.2016

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य ।

उर्जा विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है तथा इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	– 59 मिनट
जनता दल (युनाईटेड)	– 52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	– 39 मिनट
इन्डियन नेशनल कांग्रेस	– 20 मिनट
सी0पी0आई0(एम.एल.)	– 02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	– 02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	– 02 मिनट
निर्दलीय	– 03 मिनट

	कुल – 180 मिनट

प्रभारी मंत्री, उर्जा विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :–

'' उर्जा विभाग'' के संबंध में 31 मार्च,2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 143,67,84,49,000/– (एक सौ तैंतालिस अरब सड़सठ करोड़ चौरासी लाख उनचास हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य डॉ0 सुनील कुमार, श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री संजय सरावगी, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री नीरज कुमार सिंह एवं श्री मिथिलेश तिवारी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं और जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य डॉ0 सुनील कुमार का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य डॉ0 सुनील कुमार अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' इस शीर्षक की मांग 10/- रूपये से घटाई जाय । ''

राज्य सरकार की उर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

अध्यक्ष : आपको 12 मिनट का समय दिया गया है ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । साथ ही साथ सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बिहार के विभिन्न कोने से सफल होकर आये सभी माननीय सदस्यों का अभिनन्दन भी करना चाहता हूँ क्योंकि इस बार के विधान सभा में सदन में करीब-करीब 99-100 सदस्य पहली बार सफलता प्राप्त करके आये हैं । मैं दो पंक्ति कहना चाहता हूँ अपनी बात शुरू करने से पहले -

सफलता एक सुन्दर पुष्प है, तो विनम्रता उसकी सुगन्ध है,
जिन्दगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि
आपकी मंजिल का रास्ता, लोगों को दिलों को तोड़ता हुआ न मिले ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से जिस क्षेत्र से जीतकर आता हूँ बिहारशरीफ से, वहां के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे चौथी बार चुनाव जीता कर सफल करके यहां भेजा है ।

बिहारशरीफ की लोगों की निगाहें हमारी पहचान है,
सफलता उनकी हमारी जान है और बिहार की प्रगति हमारी उड़ान है,
और बिहारशरीफ के लोगों को और आपलोगों का साथ हमारी जान है ।

अध्यक्ष महोदय, भाजपा को जुमलों और झाँसों की सरकार बराबर महागठबंधन के मंत्रीगण और मुख्यमंत्री कहते आये हैं । बराबर ये आरोप लगाते रहे हैं कि केन्द्र की सरकार बिहार के साथ भेदभाव करती है । लेकिन हमने देखा कि 2015 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी केन्द्र सरकार की योजनाओं को नाम बदल कर , 7 निश्चय का नाम देकर, बिहार की जनता को झाँसा देकर, आरक्षण का भय दिखाकर सत्ता में काबिज हो गये । हिन्दुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं बनी, जिसने 3 महीने के कार्यकाल में ही जनता का विश्वास खो दिया । आज बिहार में अपराध चरम सीमा पर है । बहू-बेटियों की इज्जत दांव पर लगी है । हर जगह बलात्कार हो रहा है । बिहार के बच्चे मारे जा रहे हैं । जरा धैर्य रखें, बिजली पर ही बोलूँगा । जरा धैर्य रखिए, आ रहा हूँ बिजली पर ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिहार की जो स्थिति है, पहले स्थिति को तो बताऊं, तब न बिजली पर आऊँगा । मेरा जीवन ही नहीं रहेगा तब बिजली लेकर क्या होगा ? मैं कहना चाहता हूँ कि तीन महीना के अन्दर ही सरकार ने जनता में विश्वास खो दिया और उसपर सत्ता पक्ष के लोगों का ब्यान आता है कि आप पाँच साल तक छाती पीटते रहिए, आपकी बहू-बेटियों की इज्जत जाती है तो जाती रहे, आपके बच्चों की हत्या होती है तो होती रहे लेकिन यहां तो कानून का राज है। कैसा कानून का राज ? महोदय, पहले बिहार में कानून व्यवस्था ठीक की जाय, बिहार की जनता से जो वादा करके महागठबंधन के लोग सत्ता में आये हैं, पहले उस वादा को निभाने का कोशिश करें ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली का सवाल है तो बिजली मंत्री बैठे हुए हैं । आईना दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्लेन आईना और एक होता है ओवल आईना । यहां के पदाधिकारी, बिजली विभाग के पदाधिकारी माननीय मंत्री जी को ओवल आईना दिखाते है, जो दाढ़ी बनाने में काम आता है । 6 ईंच के फोटो को 6 फीट दिखाता है और जो प्लेन आईना होता है, वह बिहार की वस्तुस्थिति दिखाता है । तो मैं माननीय मंत्री जी को बिहार का प्लेन आईना दिखाना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग को अगर यह कहा जाय कि भ्रष्टाचार की जननी है तो यह कहीं से गलत नहीं होगा । अगर विभागों में कम्पटीशन किया जाय भ्रष्टाचार का तो पहला नम्बर में पुलिस विभाग आयेगा लेकिन दूसरा नम्बर में उर्जा विभाग भी आयेगा । आज बिहार की गरीब जनता बिजली विभाग से इतना त्रस्त है कि बिजली विभाग आज बिचौलियों के हाथों में चला गया है । मीटर रीडिंग बिचौलियों के द्वारा होता है, बिलिंग बिचौलियों के द्वारा होता है । एक कमरे के घर में जो गरीब रहता है, उसको तीन हजार से तीस हजार रू0 का बिल दिया जाता है और फिर बिचौलियों के द्वारा कम करने के नाम पर उसका शोषण किया जाता है । इतना ही नहीं बिजली शुद्धिकरण का दावा करती है विभाग, बराबर कहती है कि हमने काऊन्टर खोल दिया लेकिन उस काऊन्टर पर जाकर देखिए कि बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं होता है । अगर बिहार के पूरे शहरों की बात करें, अगर उनके संचरण व्यवस्था की बात करें, अगर तारों की बात करें तो बिहार की जितनी बच्चों की लाशें बिजली के करेन्ट लगने से उनकी मृत्यु हुई है । बिजली विभाग अपने जर्जर तारों को बदल नहीं पा रही है । जो ट्रांसफर्मर 40 वर्ष पहले लगे, 63 के0वी0ए0 के, 100 के0वी0ए0 के, 200 के0वी0ए0 के, जनसंख्या बढ़ गई, उपभोक्ता बढ़ गये लेकिन उनका अपग्रेडेशन सभी जगह नहीं किया गया । जब तक आप बिजली विभाग के पदाधिकारियों को कुछ चढ़ावा नहीं देंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है । तार बदलने की बात करें उनसे, अगर पैसा दिये तो तुरंत तार

बदल देंगे, अगर पैसा नहीं दिये तो वे कहेंगे कि स्टीमेट बोर्ड को भेज दिया हूँ और वह बोर्ड से कभी वापस नहीं आयेगा । हम 10 साल से विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के जिस एरिया का बोर्ड में गया है, आज तक वापस नहीं आया है ।आज तक उसके तार बदले नहीं गये । ..... क्रमशः .....

टर्न–11/अंजनी/दि0 17.03.16

....क्रमशः....

डॉ0 सुनील कुमार : महोदय, सरकार घोषणायें करती रहती है कि शहर में 24 घंटे में और देहात में 72 घंटे के अन्दर जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जायेंगे, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाय तो जब तक आप कुछ लेन–देन न करेंगे, तबतक ट्रांसफार्मर बदले नहीं जायेंगे । अगर आपने अधिकारियों को फोन किया तो यही कहेंगे कि अच्छा ट्रांसफार्मर जल गया, मुझे तो सूचना ही नहीं है ? तो इस तरह के असंवेदनशील बिजली विभाग के पदाधिकारी हैं सरकार अभी इसको मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना में जोड़ी है कि हम घर घर में बिजली पहुंचायेंगे, हम सरकार से पहले आग्रह करेंगे कि जिन घरों में बिजली का कनेक्शन आपने दिया है, कम–से–कम पहले उनको लगातार बिजली देने का तो वादा कीजिए, लगातार बिजली तो दीजिए । कहीं ट्रांसफार्मर खराब है, तो कहीं तार खराब है, आप बिजली नहीं दे पाते हैं लेकिन दोषारोपण जरूर करते हैं । केन्द्र पर दोषारोपण जरूर करते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि महान वे कहलाते हैं जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं और वो कायर होते ह ैंजो दूसरे को बेवजह बदनाम कर और गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं । पूरे देश में बिजली पहुंचाने के लिए केन्द्र राज्य सरकारों को हर संभव मदद कर रही है, कई योजनायें बिहार में भी चल रही हैं– जैसे समेकित विद्युत विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना और उसमें काफी पैसे भी आये हैं, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से जोड़ा गया है, जिसमें 9 हजार करोड़ रूपया बिहार को मिलेगा । बांका में चार हजार मेगावाट का अल्ट्रा प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली है । केन्द्र की इतनी सहायता के बावजूद अभी–भी बिहार में 37 हजार मेगावाट यूनिट ही बिजली उपलब्ध है, जबकि जरूरत 6500 से ज्यादा है । पूरे अगर हिन्दुस्तान की बात करें तो बिहार के लोगों को पर व्यक्ति बिजली 144 किलोवाट की जरूरत पड़ती है और पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को 927 मेगावाट की जरूरत पड़ती है तो कितनी बिहार पीछे है, यह आप समझ सकते हैं। बिहार सरकार और ऊर्जा विभाग की शिथिलता के कारण बिहार की कई परियोजनायें चली गयी, डगमरा बिजली परियोजना ठंढ़े बस्ते में बंद हो गयी, कोसी बराज 5.5 जल विद्युत परियोजना वह ठंढ़े बस्ते में चल गयी, नवीनगर

बिजली परियोजना, इसलिए उड़ीसा ने और डी0भी0सी0 ने अपना अंशदान छोड़ा, अगर बिहार सरकार जागरूक होती तो वह दावा करती, उससे पहले यू0पी0 ने दावा कर दिया और अब उन योजनाओं से बिजली यू0पी0 को मिलेगा न कि बिहार को । तो बिहार सरकार बराबर बोलती रहती है कि हम इस तरह का विकास कर रहे हैं, उस तरह का विकास कर रहे हैं, लेकिन कभी अपने आपको झांकती नहीं है । कभी सोचती नहीं है कि जो अधिकारी हैं, वे हमको आईना देखा रहे हैं । वह ओवल आईना है और हमको प्लेन आईना देखना चाहिए । मैं सरकार को आपके माध्यम से दो लाईन कहना चाहता हूँ कि....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुनील जी, आप तो आईना दो ही प्रकार के बता रहे हैं, आईना तो तीन प्रकार का होता है । एक प्लेन होता है, एक कनवेक्स होता है, जिसमें आप कहे कि बड़े-बड़े दिखते हैं और एक कनकेभ होता है जिसमें चीज छोटे दीखते हैं ।

डॉ0 सुनील कुमार : वो हमने नहीं देखा है । वे आप देखें होंगे । तो मैं आपके माध्यम से सरकार को दो लाईन कहता हूँ कि बिहार की फिक्र कर नादां, मुसीबत आनेवाली है, तेरे बर्बादियों के धुऐं हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे, ओ महागठबंधनवालों, तुम्हारी दास्तान न होगी ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री अशोक कुमार, आपका समय 09 मिनट है ।

श्री अशोक कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो बजट आया है, मैं उसके पक्ष में और जो कटौती प्रस्ताव आया है, उसके विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आज जो ऊर्जा विभाग है, किसी भी देश या किसी भी राज्य के लिए बिजली बहुत महत्वपूर्ण चीज है । बिजली के बिना न तो हरितक्रांति की कल्पना की जा सकती है और न ही औद्योगिक क्रांति की कल्पना की जा सकती है । बिजली ही एक ऐसी चीज है जो खेतों में हरियाली दे सकती है और फैक्ट्रियों के चिमनियों से धुआं निकाल सकती है । आज बिहार खाद्यान्न के मामले में माननीय नीतीश कुमार के राज में जिस बिहार के खाद्यान्न का बढ़ा है खेतों से, उसमें सिर्फ नहर ही नहीं बल्कि बिजली का भी बहुत योगदान है । इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में जब से बिजली आयी है, माननीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले बिहार की खपत 800 मेगावाट और पीक आवर में एक हजार मेगावाट लेकिन आज बिहार की खपत आज के डेट में 3449 मेगावाट और अगले इस वर्ष के अंत तक यह बढ़कर क्षमता 5000 मेगावाट तक हो जायेगी । तो 800 से 5000 मेगावाट तक इस बिहार में बिजली खपत पहुचाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया और बिजली मंत्री

जी ने किया । किसी भी देश का और बिहार का विकास का पैमाना ऊर्जा की खपत से होती है और माननीय नीतीश कुमार जी ने 800 से 5000 मेगावाट बिजली को बढ़ाया तो बिहार में विकास का दर इस हिसाब से पांच सौ गुणक करने का काम किया । इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार को धन्यवाद देते है, बधाई देते हैं ।

(इस अवसर पर श्री हरिनारायण सिंह ने सभापति का पद ग्रहण किया)

माननीय सभापति महोदय, पेपर में छपा था कि 2015 के लिए बिजली विभाग की उपलब्धता देश में सर्वोत्तम रही है । प्रति व्यक्ति जो खपत 145 यूनिट था, बिहार सरकार के क्रिया-कलापों के चलते यह खपत बढ़कर 203 प्रति यूनिट हो गया, जो देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है । देश का 40प्रतिशत् उपलब्धि बिहार में जो बढ़ी, वह हमने नही, केन्द्र सरकार ने माना कि देश की सबसे बड़ी बिजली उपलब्धि बिहार में हुई है । माननीय सभापति महोदय, हमारे मित्र ललन भाई हैं बराबर गुप्ता धाम की चर्चा करते रहते हैं कि बिजली नहीं पहुंची है, मैं इनको पेपर का एक कटिंग दे दूंगा, जिसमें सरकार का लिखा हुआ है कि 68 साल आजादी के बाद पहली बार गुप्ता धाम में लोग बिजली देखेंगे । यह देन नीतीश कुमार जी का है । यह पेपर का कटिंग मैं आपको दे दूंगा । ये केन्द्र सरकार की बात करते हैं, एक दिन बिहार में 1500 या 1600 केन्द्र सरकार ने आधी बिजली कटौती कर दी और बिहार के एक दर्जन ग्रीड बंद हो गये ।

....क्रमशः....

टर्न–12/शंभु/17.03.16

श्री अशोक कुमार : क्रमशः.....भाषण नहीं आंकड़ों में आइये आप। केन्द्र सरकार ने बिजली नहीं दी और बिहार का एक दर्जन ग्रिड बंद हो गया, यह आपकी उपलब्धि है। हमारे माननीय विरोधी दल के नेता इस बिहार के सबसे गर्म शहर में रहते हैं। जब गर्मी का परवान चढ़ता है तो गया सबसे गर्म शहर गिना जाता है। लेकिन बिजली हमलोगों ने इतनी उपलब्धता करा दी कि अपने घर में ए0सी0 लगाकर के शिमला का आनंद लेते हैं। इसीलिए तो कम से कम माननीय विरोधी दल के नेता हमारी सरकार को धन्यवाद दे दें। मैं अपने क्षेत्र के तरफ जाना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, हमारा क्षेत्र बिजली पर आधारित क्षेत्र है। वहां 3–4 सब स्टेशन तिलौथु में है, लेकिन ग्रिड नहीं रहने के कारण बिजली हम दूसरे जिले से लाते हैं और दूसरे जिले से बिजली लाते हैं तो हमारे यहां 22 घंटा बिजली रहती है, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है, काम आगे बढ़ रहा है– करपा में ग्रिड बनाने का, कार्य प्रगति पर है। माननीय मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूँगा कि इस काम को जल्द से जल्द कराने की कृपा की जाय। सासाराम में पी0एच0डी0 विभाग को 33 हजार का लाइन खींचने के लिए हमने वहां के अभियंताओं से बात किया– 33 हजार का लाइन देने के लिए वहां के कार्यपालक अभियंता ने बिजली बोर्ड को आदेश लेने के लिए पत्र भेजा है। मैं अनुरोध करूँगा माननीय मंत्री जी से कि उसको भी करवाने का काम कीजिएगा। हमलोगों का डेहरी और सासाराम का एक अहम सवाल है– माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसकी समीक्षा की जरूरत है। जो बोरिंग चलाकर किसान खेतों में पानी डालते हैं उनपर 20 वर्ष, 30 वर्ष का बिल बकाया रह गया है। मैं नहीं कहता हूँ कि हमारी लापरवाही है, लेकिन विद्युत् विभाग के अभियंताओं को चाहिए था कि हर दो तीन महीने में बिजली बिल का कलेक्शन कर लें। यह लापरवाही किसानों की कहिये या विभाग की कहिये– आज एक–एक किसान पर 20 लाख, 30 लाख का बिल बकाया है। आज किसान बिल देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनको 1, 2 एकड़ जमीन है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इसकी समीक्षा करके उस बिजली बिल को माफ कराने की कृपा करें या कम से कम मूलधन ले लें, जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको माफ कर दें ताकि किसान अपना बिल दे दे और हमारे किसानों को लाइन मिलने लगे। हुजूर, कम से कम ऋण माफ कर देंगे, चूंकि इन्होंने अभी एक नियम बना रखा है कि जिस जिले से जितना राजस्व की प्राप्ति होगी उतना ही हम बिजली दे पायेंगे।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें।

श्री अशोक कुमार : हुजूर, आप ही की मैं बात कर रहा हूँ। महोदय, अगर यह नियम लागू हो गया और जो 20 लाख, 25 लाख का बिजली बिल बाकी है वह वापस नहीं कर पायेंगे। किसानों का सब काम बंद हो जायेगा। इसलिए महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री विजेन्द्र बाबू बिजली के बहुत जानकार आदमी है और उदारवादी मंत्री हैं, किसान के बेटे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि बहुत दिये हैं और किसानों का बिजली बिल माफ करेंगे, यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : श्री निरंजन कुमार मेहता जी, आप समय 10 मिनट है।

श्री निरंजन कुमार मेहता : लोकतंत्र के इस पवित्र सदन में सबसे पहले माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का मैं अपनी ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस सदन से अपने बिहारीगंज विधान सभा की तमाम जनता का, महागठबंधन की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आज ऊर्जा विभाग द्वारा जो वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट पेश किया गया है उसमें आय व्ययक सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर ऊर्जा विभाग पर हो रहे वाद-विवाद में सरकार के समर्थन में अपनी बातें बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विकास के 7 निश्चय में हर घर बिजली एक महत्वपूर्ण विषय है। सम्पूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण की ओर बढ़ रहे बिजली की मांग और आपूर्ति का अंतर घट रहा है। पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या बढ़ने के बाद भी बिजली की आपूर्ति संतुलित ढंग से हो रही है। सभापति महोदय, बिहार में सभी परिवारों को मुफ्त कनेक्शन देने की योजना से मांग में वृद्धि हुई है। उससे भी ज्यादा रफ्तार से आपूर्ति के प्रयास किये जा रहे हैं और आपूर्ति हो भी रही है। अभी-अभी हमारे माननीय तिवारी जी बोल रहे थे कि गांव में बिजली नहीं रहती है। महोदय, मुझे यह लग रहा है कि तीन बार से माननीय विधायक जी विधायक बन रहे हैं, मुझे लगता है कि गांव में घूमते हैं। सभापति महोदय, एक समय हुआ करता था- शांत रहिये माननीय सदस्य.....शांति रहिये। हम जब आपलोगों का सुनते हैं तो आप भी सुनिये। विरोधी का कद्र होता है, लेकिन कद्र कीजिए ढंग से। माननीय सभापति महोदय, एक समय हुआ करता था जब गांव के लोगों की आंखें तरस जाती थी बिजली के लिए और आज वर्तमान में ऊर्जा विभाग के सौजन्य से गांव में 16 से 18 घंटे, पटना राजधानी सहित, जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली रहती है। मैं दावा के साथ कहूंगा- मेरा

विधान सभा बिहारीगंज बहुत सुदूर देहाती क्षेत्र है, मैं दावा के साथ कहूंगा, मैं घूमता हूँ.....पहली बार सदस्य बनकर आया हूँ महान जनता की ओर से, महागठबंधन की ओर से और हमारे क्षेत्र में 18 घंटे बिजली सुदूर देहात में रहती है। मैं अपने आंख से देखा हूँ और बिजली की एक भी शिकायत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा राज्य अन्तर्गत योजनाओं की चर्चा मैं इस सदन में करने जा रहा हूं। सभापति महोदय, मुजप्फरपुर ताप विद्युत् प्रतिष्ठान इकाई का आधुनिकीकरण, नवीनीकरण का कार्य समाप्त हो चुका है और इन दोनों इकाइयों से उत्पादन भी शुरू है। राज्य योजना अन्तर्गत बरौनी ताप विद्युत् प्रतिष्ठान का विस्तार किया जा रहा है। बरौनी ताप विद्युत् प्रतिष्ठान का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। नवीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी प्रा0लि0 द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रतिष्ठान का निर्माण किया जा रहा है। सभापति महोदय, राज्य सरकार के अथक प्रयास से तीन महत्वपूर्ण ग्रिन फिल्ड परियोजना पर कार्य कराने का भी निर्णय लिया गया है। चौसा, पीरपैंती एवं कजरा में ग्रिन फिल्ड का ताप विद्युत् परियोजना स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। सभापति महोदय, बिहार में गैर परंपरागत माध्यमों से बिजली उत्पादन लगभग शून्य है, बिहार सरकार ने गैर परंपरागत माध्यमों से बिजली उत्पादन की योजना पर भी कार्य कर रही है। बिहार में सोलर पावर में भी कदम बढ़ाया है, आनेवाले वर्षों में यहां बृहत स्तर पर सोलर बिजली पैदा होगी। यह योजना कार्यरत भी है। सभापति महोदय, राज्य के बदले परिवेश में कई निजी एवं मल्टी नेशनल कंपनी के द्वारा थर्मल पावर प्लांट एवं विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के सोलर, बायोगैस, बाहरी कचरा एवं डबल फ्यूल पावर प्लांट लगाने हेतु सरकार को प्रस्ताव मिला है, जिनपर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। बथनाहा, निर्मली एवं अरार घाट जल विद्युत् परियोजना के द्वारा राज्य में जल विद्युत् उत्पादन का भी प्रयास किया जा रहा है। सभापति महोदय, यह अरार घाट जल विद्युत् जो है यह हमारे विधान सभा क्षेत्र में आता है इसपर भी कार्य वहां पर किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ....क्रमशः।

टर्ल–13/अशोक/17.03.2016

श्री निरंजन कुमार मेहता : क्रमशः माननीय सभापति महोदय, राज्य के सभी राजस्व अनुमंडलों में पावर ग्रिड उपकेन्द्र की स्थापना की जा रही है, जिसे अप्रैल 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है । वितरण के प्रक्षेत्र में परियोजनाओं को तीव्र गति से कार्यान्वित कराया जा रहा है ।

सभापति महोदय, मुयमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत जले ट्रांसफार्मरों को बदला जा रहा है, टुल्लू ट्रांसफार्मरों को बदल कर 63 केवी 100 केवी तथा जरूरत के मुताबिम अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाये जा रहे हैं, राज्य भर में नये पावर स्टेशनों का निर्माण हो रहा है । ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचाने का कार्य तीव्र गति से हो रहा

है । बिजली व्यवस्था में भी अब एम्बुलेंस जुड़ गया है, जिससे शीघ्र सेवा लोगों के बीच उपलब्ध हो जाता है ।

सभापति महोदय, हमारा बिहार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में विकास की ओर तीव्र गति से कदम बढ़ा रहा है । जिसकी तारीफ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं की है । उन्होंने तारीफ करते हुऐ कहा है कि गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना को गति देने में पूरा सहयोग के लिए मैं बिहार सरकार का आभारी हूँ । केन्द्र और राज्य अगर तय कर ले तो बिहार, गांवों में सबसे पहले बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने वाला गौरवशाली राज्य बनेगा, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा हाजीपुर के छोकिया सभा में कहा गया है ।

सभापति महोदय, बिहार की जनता ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ महागठबंधन की सरकार को चुना है, बिहार सरकार, बिहार की जनता को यह विश्वास दिलाती है कि वर्तमान समय में बिहार विकास की दिशा में तीव्र गति से चल रहा है आने वाले समय में भी बिहार विकास की दिशा में और गतिशील रहेगा ।

सभापति महोदय, माननीय उर्जा मंत्री के द्वारा सदन में जो उर्जा विभाग का बजट पेश किया गया है मैं पूरा समर्थन करता हूँ । इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

जय हिन्द, जय बिहार, जय महागठबंधन ।

श्री संजय कुमार तिवारी : माननीय सभापति महोदय, 16 वीं विधान सभा के बजट सत्र में पर्यटन एवं उर्जा विभाग के आय–व्यय के वाद–विवाद पर अपने सत्ता पक्ष की

ओर से बजट के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में अपनी बात को रखने के लिए आपने मौका दिया, मैं आभार व्यक्त करते हुये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी को भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी के साथ मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी सह शिक्षा मंत्री एवं विधान मंडल दल के नेता सदानन्द बाबू का आभार व्यक्त करते हुये मैं जिस क्षेत्र बक्सर से आता हूँ वह महर्षियों और देवों की भूमि रही है। महोदय, मैंने पर्यटन का विषय इसलिए चुना चूंकि हमारा क्षेत्र हमेशा से उपेक्षित रहा है, मैं सदन के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ कि हम महागठबन्धन के चार साथी, उस संसदीय क्षेत्र में हमारा छः विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें हम पांच जीत कर आये हैं महागठबन्धन के तहत । हमने दानवरूपी बी.जे.पी. से मुक्ति दिलाने के लिए महागठबन्धन तैयार किया । महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय सदस्यों का ध्यान अकृष्ट करना चाहूंगा कि वह पवित्र स्थल, भगवान राम, विश्वमित्र की तपोभूमि और मर्यादा पुरूषोत्तम राम की शिक्षास्थली, भगवान बावनराम की जन्म स्थली और आज तक जितने भी ऋषि-महर्षि है वे सभी बक्सर में बास करते हैं । परम पूजनीय स्वामी जी महाराज का और नाथ बाबा का वहां आश्रम हुआ करता है । माननीय सभापति जी, आपके आसन के द्वारा ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जैसे पावापुरी, नालन्दा और गया को विकसित किया गया हमारे बक्सर को रामायण सर्किट से जोड़ा गया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आपके आसन के माध्यम से आकृष्ट कराना चाहूंगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र के दो मंत्री, श्री जय कुमार सिंह जी और श्री संतोष कुमार निराला जी यहां बैठे हैं, हमारे साथ ददन पहलवान जी, भाई शम्भु जी और मैं- मैं चारो आदमी की तरफ से, मैं सदन की तरफ से मांग करता हूँ कि जैसे पावापुरी, पटना साहिब और गया, नालन्दा, राजगृह जैसे जगहों को शार्ट सर्किट के माध्यम से जोड़ा गया- मैं आपसे मांग करता हूँ कि बक्सर को भी रामायण सर्किट के तहत जोड़ते हुये बक्सर को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाय ताकि आने वाले दिनों में शाहाबाद के बरोजगार लागों की बेरोजगारी दूर हो सके और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि बक्सर को पर्यटन का दर्जा दिया जायेगा तो वहां के नौजवानों में रोजगार सृजन की व्यवस्था होगी । महोदय, मैं सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि हमारे यहां आज भी स्क्वॉन के लोग जाते हैं, वहां घूमते हैं और तीर्थ-स्थल को देखकर के रोमांचित और गौरवान्वित होते हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री की सराहना करता

हूॅ कि जिस तरह से 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो हमारे पास था खेती और पर्यटन और आपके राज्य में, आपके शासनकाल में 2005 से 2015 तक बिहार में बिहार से बाहर से आने वाले पर्यटकों की संख्या आज करोड़ों में पहुंच गई, विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या लाखों में पहुंच गई । मैं धन्यवाद देता माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं धन्यवाद देता हूॅ पर्यटन मंत्री जी को, जो हमारे शाहाबाद क्षेत्र से ही आती है श्रीमती अनीता जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि हमारे बक्सर को विशेष रूप से पर्यटन का दर्जा देने की मैं पुरजोर वकालत करता हूॅ और अपने साथियों से भी कहता हूॅ कि आने वाले समय में आप भी मेरी मांग को अपनी मांग बनाकर बक्सर को पर्यटन का दर्जा दिलायेंगे तो पूरा शाहाबाद में एक नये रोजगार का सृजन होग और नौजवानों में अनेक भाषाओं के लोग, भाषा-भाषी के लोग आते हैं, जैसे कि आज गया में, जैसे कि आज नालन्दा और राजगीर में लोग आते हैं- फिलिपिन्स, म्यांमार, जापान श्री लंका से लोग आते हैं और वहां के नौजवान उन भाषाओं को सीखने के लिए विभिन्न जगहों पर जाकर उनके प्रचलन की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उन भाषाओं के जानकार हो रहे हैं, इससे हमारे बिहार में नौजवानों की बेरोजगारी दूर होगी । मैं माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से उर्जा मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने चौसा में जो 1320 मेगावाट बिजली देने की क्षमता पैदा की, विभिन्न ताप विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु जो आपने कार्य किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूॅ चूंकि हमारे विधान सभा क्षेत्र में ही आता है मान्यवर । मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं तमाम अपने महागठबन्धन के सदस्यों, विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों का नमन करते हुये, अभिनन्दन करते हुये अपनी वाणी को विराम करता हूॅ । जय हिन्द, जय भारत ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार यदव । 9 मिनट में समाप्त करेंगे ।

श्री अनिल कुमार यादव : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मै शुक्रगुजार हूॅ । महोदय, मैं शुक्रगुजार हॅ सामाजिक न्याय की मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और न्याय के साथ विकास के कर्मी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और कॉग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी का जिन्होंने एक सही समय में महागठब्न्धन का निर्माण किया और बिहार को गर्त में जाने से बचाने का काम किया । सभापति महोदय, बिहार ने देश को रोशनी देने का काम किया है और चुनाव में भी बिहार के मतदाता मालिकों ने हमारे कर्मवीर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का जनादेश

दिया और उसी क्रम में मैं आज उर्जा विभाग के बजट के पक्ष में और विपक्ष के द्वारा पेश किये गये कटौती प्रस्ताव के विरूद्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, आज बिहार राज्य उर्जा के क्षेत्र में उतरोत्तर प्रगति कर रहा है । उर्जा मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी काफी अनुभवी एवं वयोबृद्ध हैं । क्रमशः

टर्न-14-17-03-16-ज्योति

क्रमशः

श्री अनिल कुमार यादव : और इनके नेतृत्व में आज गांव गांव में बिजली पहुंचाने का काम हो रहा है । गांव गांव में बिजली पहुंचायी जा रही है । जहाँ एक साल पहले गांव में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 168 यूनिट थी आज 203 यूनिट पर पहुंच गयी है । मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उर्जा मंत्री महोदय को, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में सघन विद्युतीकरण के लिए 8206.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महोदय, उर्जा मंत्री जी को 4980.57 करोड़ रुपये के वितरण एवं संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए दिया गया है और ब्रेडा के द्वारा सोलर प्लान्ट अधिष्ठापना का कार्य किया जा रहा है जो पर्यावरण के दृष्टिकोण स भी बहुत उचित है और इसके मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मंत्री जी को । महोदय, विधान सभा के चुणाव परिणाम में उर्जा विभाग की कहीं न कहीं सहभागिता जरुर रही थी । एक तरफ हमारे गठबंधन के नेता हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी अपने 7 निश्चयों में से एक निश्चय घर घर बिजली पहुंचाने की बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक सभा में कहा करते थे कि बिजली मिली , बिजली मिली और लोग खरीदे हुए टट्टू वहाँ कहते थे कि नहीं मिली, नहीं आयी लेकिन बिजली आयी और पूरे सूबे की महान जनता समझती थी और देखती थी कि उनके गांव में बिजली पहुंच रही है और जहाँ पहुंचाना बाकी है वहाँ प्रगति का काम जारी थी । वैसे लोगों को बिहार की महान जनता ने ऐसा जवाब देने का काम किया महोदय, आज वह एक कोने में बैठकर निगेटिव एप्रोच की बात करते हैं । आज बार बार सदन को बाधित किया जाता है । उस दिन हमारे माननीय नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहेब ने कहा था, गुजारिश की थी - उन्होंने कहा था नये नये सदस्य चुनकर आए हैं और यहाँ की परम्परा रही है कि नये सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाय । टोका टोकी नहीं किया जाय लेकिन जनहित की बात जहाँ उठती है और उसके लिए क्वेश्चन आवर होता है जिसमें अल्पसूचित प्रश्न आते हैं लेकिन आज क्या हो रहा है कि झूठ-मूठ की बात की नखरेवाजी हो रही है , क्या कर रहे हैं ? आप यह कौन सी पोजिटिव सोच रख रहे हैं । आज विज्ञान का युग

है और विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि में उर्जा का भी महत्वपूर्ण रोल है । उर्जा और बिजली का ही महत्वपूर्ण रोल है और बिजली के साथ सड़क निर्माण हाता है यदि आपको पौजिटिव रोल - मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से यदि उनकी सकारारत्मक सोच है उस दिन माननीय उपमंत्री तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था उनको कि आपके प्रधानमंत्री नहीं , हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आप भी साथ दीजिये और बिहार की मांग को मांगने का काम कीजिये । मैं पूछना चाहता हूँ अपने प्रतिपक्ष के साथियों से जिस समय इन्ही के नेता इस देश के प्रधानमंत्री हैं और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी और यू.पी0ए0 वन और यू0पी0ए0- टू के समय में भी उसका सफल संचालन हुआ था और बिहार को ढेर सारा पैसा मिला था आज क्या हो रहा है । 40 प्रतिशत की राशि मांगी जा रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उस समय जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जिस ` स्टेट का डेवलप्ड था वहॉ सड़के बनी लेकिन बिहार जैसे पिछड़े राज्य उसमें हमारा मिथिलांचल पूर्णिया,मधेपुरा, सुपौल,अररिया,किशनगंज जैसे पिछड़े जिला रह गए और वैसी जगहों पर आज बिहार सरकार जो 40 परसेंट जुगाड़ करेगी तो यहॉ सड़क का निर्माण होगा । मैं पूछना चाहता हूँ सभापति महोदय अपने विपक्ष के साथियों से कि वे इस बात पर हल्ला क्यों नहीं करते हैं और जहॉ तक बिजली की बात है तो यह 2016 के लास्ट तक पहुंचनी ही है ,बिजली तो पहुंच ही रही है । इसके बाद फिर बिजली का जहॉतक मामला है कि केन्द्र प्रक्षेत्र से

(व्यवधान)

सभापति महोदय, केन्द्रीय प्रक्षेत्र से 3017 की आवश्यकता है और आवश्यक 2250 मिल रहा है ` । सभापति महोदय , मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूँ कि वे विकास के काम में रोड़ा अटकाने का काम नहीं करें मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आप अभी जहॉ हैं उससे भी नीचे बिहार की जनता आपको पहुंचाने का काम करेगी यदि आप विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम नहीं करें । सभापति महोदय, अंत में मैं सरकार को कह देना चाहता हूँ गठबंधन की सरकार के नेता को- संयोग से मेरा सौभाग्य है कि मेरे सामने में हमारे नेता बैठे हुए हैं , घबराने की जरुरत नहीं है । एक कवि ने कहा है :

''वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या,
जिनकी राहों में सूल नहीं ,
नाविक की धैर्यकुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल नहीं ''

इसलिए ये बिहार बढ़ेगा । सभापति महोदय, ं विपक्ष के साथी ं सूल लटकाने का काम करें , बिहार बढ़ेगा , बिहार बढ़ता ही रहेगा ,हर घर में बिजली मिलेगी , हर जगह सड़क बनेगी । बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : माननीय सदस्य , रामप्रीत पासवान जी ।

श्री रामप्रीत पासवान : सभापति महोदय, मैं उर्जा विभाग की मांग पर जो कटौती प्रस्ताव पेश हुआ है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं अपने नेता और सभापति , हमारे माननीय ुमुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ ।

(व्यवधान)

आपलोगों का जो आचरण है - आपलोग हॉ पक्ष में बैठे हुए हैं और हम ना पक्ष में और यदि ना पक्ष नं हो तो हॉ पक्ष की कोई मर्यादा नहीं है । आप पक्ष में है और हम विपक्ष में । कभी हम पक्ष में थे ं तब आप विपक्ष में थे । आप बोलने तो दीजिये । आप पक्ष में हैं और हम विपक्ष में है इसलिए आपकी मर्यादा है । जिस विद्यालय में सहायक नं हों वहॉ प्रधानाध्यापक नहीं होते । हम विपक्षा में ें इसलिए आपकी मर्यादा ज्यादा है और इसका पालन आपलोग निश्चित रुप से करें । ं हमको तो लगता है कि मैं पक्ष में हूँ ै और आप विपक्ष में है । आपलोग इतना हल्ला करते हैं ैमैं देख रहा हूँ सदन में और इससे पहले भी सदन में मैं सदस्य था । हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं क्या मेरा काम हल्ला करना है । मेरा काम आपको आईना दिखाना है एक समय था इससे पहले हम तो आपसे ज्यादा संख्या में हैं ंजो राजद के मित्र हैं वह 22 में संख्या सिमट गये थे और हम तो अभी 56 में है । आप कोना ं मे भी ं थे हम सारे लोग उधर थे , हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ म हमलोग ें थे । आईये हम चर्चा करते हैं उर्जा विभाग्र पर, हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी , यह महागठबंधन आपने बनाया है । एक समय था जो 22 आपकें जीत कर आए थे और 22 के 22 मंत्री बन गये थे राजद के शासन में । अब सपना मत देर्खिये । हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे पुल का उद्घाटन किऐ और उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी थी थे ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सयदस्य आसन की ओर देखकर बोलें ।

श्री रामप्रीत पासवान : यह बिजली आयी कि जो आप चर्चा करते हैं । हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के सामने में कहा है आपको जितना लगाना हो लगाईये मैं पूरे बिहार को बिजली दूँगा , हमारे मुख्यमंत्री जी वहॉ मौजूद थे तो बिजली आयी तो उस बिजली को लाने में हम भी साझीदार हैं । भारत सरकार के प्रधानमंत्री आपको एक समय 35 रुपया देते हैं और 25 रुपया आप देते हैं तब ं बिजली आती है इतना मत

इतराईये । वह जनता सब देख रही है । आपको लगता हो कि मैं महागठबंधन बना लिया तो कब आपका महागठबंधन खतम हो जायेगा , कोई जानने वाला नहीं है इसलिए इस बात से मत इतराईये ें माननीय सभापति महोदय, कि उर्जा विभाग– उर्जा वह गति है गति जब जब जीवन में आती है तो बिना गति का उर्जा – उर्जा विभाग से ही गति मिलती है तो जीवन में निश्चित रुप से उर्जा की आवश्यकता है ।

क्रमशः

टर्न–15/विजय/17.03.16

श्री रामप्रीत पासवानः क्रमशः निश्चित रूप से उर्जा की आवश्यता है । हमारे माननीय उर्जा मंत्री हमारे बगल के हैं बराबर हम विधायक बीच में नहीं थे तब भी एक संबंध है । मोबाइल से बताते थे कि सर फंला जगह ट्रांसफारमर नहीं है । जो सही बात हो उसको बोलना चाहिए । पहले बिजली मिलती थी 8 घंटा 10 घंटा । अब बिजली में सुधार हुआ है 20 घंटा से 22 घंटा बिजली मिलती है । सही बात कहने में कोई संकोच नहीं है । सभापति महोदय ये लोग जितना बड़ाई करते हैं और पुनः सरकार का विरोध करते हैं एक बार वे बड़ाई करते है पुनः विरोध करते हैं । अपने मुंह से अपनी बात की निंदा करते हैं हम सदन में देख रहे हैं । महोदय, हम उर्जा मंत्री जी का घ्यान आकृष्ट करना चाहेंगे बिजली मिलती है लेकिन आपके विभाग के पदाधिकारी पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यह कौन परिस्थिति है हरदम बिजली रहती है और जब शाम को 6 बजता है तो 6 से 9 बजे रात्रि तक बिजली नहीं रहती । जब बच्चो को पढ़ना रहता है तो जेनरेटर चलता है । सभी गांव में जेनरेटर चल रहा है । 6 से 8 बजे तक बिजली नहीं मिलती है । आखिर ये कौन परिस्थिति है कि 6 बजे से 8बजे तक बिजली नहीं मिलती है। हमलोग जेनरेटर चलाकर अपने बच्चों को पढ़ातें हैं । इसमें निश्चित रूप से सुधार हो यह हमारा आग्रह है। यही स्थिति गांव में भी होता है और शहर मे भी होता है । वहां बिजली विभाग के पदाधिकारी यदि सुनते हों तो निश्चित रूप से सुनें । कहीं न कहीं वे पदाधिकारी जेनरेटर वालों से लिप्त है उससे रिश्वत लेते हैं । 6 बजे बिजली बंद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं 6 बजे ही बिजली बंद हो जाती है और 8 बजे तक सोने के लिए चलते हैं तो बिजली आती है । तो ये पूरे बिहार में है हमारे यहां सबसे ज्यादा जयनगर की स्थिति है । माननीय मंत्री जी से दूसरी बात मैं कहना चाहता

हूं छठ का दिन था और गांव के लोग गए थे केला खरीदने के लिए जयनगर शहर में । हमारे माननीय विधायक सीताराम बाबू बैठे हैं । वहां बिजली का तार गिरा 5 युवा जिसकी उम्र 25 और 18 के बीच थी उनकी मृत्यु हो गयी । हमने बार बार कहा था बिजली विभाग के पदाधिकारियों से कि जयनगर के जर्जर तार को बदलिये लेकिन नहीं बदला गया और उसका परिणाम हुआ कि पांच युवक मर गए । एक उसमें सिपाही भी था वह भी मर गया । इसके बाद बिजली का तार लगा और लग भी रहा है । तो मेरा कहना है माननीय मंत्री जी बिजली का तार जब घटना घट जाती है तब आपके विभाग के अधिकारी तार लगाते हैं अन्यथा नहीं लगाते । उस पर निश्चित रूप से घ्यान देना चाहिए यह हमारा सुझाव है । अभी जहां गांव में बिजली लग रही है भारत सरकार को हो, बजाज का हो या आप करवाते हों एक पंचायत है जिस पंचायत के सभी टोले में बिजली लग जाना चाहिए । होता क्या है एक टोला में लगा दिया दलित महादलित टोला को छोड़ दिया गया । मैं 43 पंचायत का एम0एल0ए0 हूं और 43 पंचायत में कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जहां दो टोला तीन टोला छुटा हुआ नहीं है । बाकी जगह बिजली लगा दिया और दलितों के गांव को छोड़ दिया । इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर भी निश्चित रूप से अपने पदाधिकारी को निदेश दें कि जब एक पंचायत का शुरू करे तो पूरे पंचायत में बिजली का काम निश्चित रूप से होना चाहिए। जर्जर तार बदला जाय । परसों मेरे ही क्षेत्र> के परिहार गांव में जब तार नीचे गिरता है तो जबतक कहते नहीं हैं तार नहीं जोड़ा जाता है। परिणाम होता है कि मवेशी मरते हैं । एक साढ़ परिहारपुर गांव में मर गया परसो । तो निश्चित रूप से आपसे आग्रह करूंगा कि इसमें सुधार होना चाहिए ।

यहां विधान सभा में जो बहस होता है तो बहस के क्रम मैं यह बात निश्चित रूप से कहूंगा कि हम भी सुझाव देते हैं, ऐसा नहीं है सुझाव नहीं देते हैं हम भी इस बिहार के वासी हैं । कैसे हो सुधार बिजली विभाग में हम भी चाहते हैं । कैसे हमको 24 घंटा बिजली मिले यह हमारी भी चिंता है । इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो ।

तीसरा कहना है कि गलत बिजली विपत्र आता है । बिजली जलाते हैं हम 200 रू0 का बिल आता है 2000 रू0 का । मेरे यहां 34 हजार का बिजली बिल चला गया। मैं गांव में रहता हूं मुश्किल से बिजली जलता है 3-4 बल्ब अभी भी और 34 हजार का बिल आया । और जब मैं एक्जीक्युटिव इंजीनियर को कहने गया तो कहा-सर सुधार हो जाएगा लेकिन आज तक वह

सुधार नहीं हुआ । यह जो स्थिति है, प्रक्रिया है, इसमें निश्चित रूप से सुधार हो ।

महोदय, बिजली विभाग में जो लोग हैं वे पोल पर चढ़ते हैं वे आपके कर्मचारी नहीं हैं जो प्राइवेट आदमी है वह बिल पहुंचाता है । यदि नहीं पहुंचाता है तो मधुबनी के बाजार में एक दूकानदार के यहां रखता है वहां से हम बिल ले जाते हैं तब इसका भुगतान होता है तो इसमें निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए महोदय यह मेरा आग्रह है। महोदय, खासकर के जो दलित महादलित का मोहल्ला है जो बी0पी0एल0 परिवार है बी0पी0एल0 परिवार को कहा गया था मुफ्त में बिजली देंगे । लेकिन जब बी0पी0एल0 परिवार को बिजली दिया जता है तो जितना भी ऑफिस है अनुमंडल ऑफिस हो, प्रखंड का हो सब बिचौलिया रखे हुए है और बिचौलिया के माध्यम से कहा जाता है 500 रू0 दो तो कनेक्शन लगायेगें 2 हजार रू0 दो तो कनेक्शन लगायेंगें । अभी परसो या तरसो मैंने आपसे कहा था ट्रांसफारमर के लिए और आपसे फरियाद किया था इसके बाद मैंने एक्जीक्यूटिव को कहा कि महादलित की बस्ती है वहां आज तक ट्रांसफारमर नहीं लगा उसके पहले योजना चली थी जब यू0पी0ए0 की सरकार थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का वह 25 के0भी0 का ट्रांसफारमर देता था और दो से तीन दिन में खत्म हो जाता था । निश्चित रूप से केन्द्र सरकार ने गरीबों के साथ मजाक किया कहीं योजना नहीं चली आप सारे लोग इस बात को जानते हैं महोदय । कहीं योजना नहीं चली 25 के0वी0 का दिया और 2 से 3 दिन में ट्रांसफारमर उड़ गया और वहां गरीबों के यहां ही पड़ा हुआ है । हमलोग निश्चित रूप से आपसे मांग करते हैं 25 के0वी0 का जहां जहां ट्रांसफारमर लगा हुआ है दलित के बीच में बिजली नहीं लगी उसको भी सुधार करें यह मेरा आग्रह है ।

महोदय,यहां पक्ष और विपक्ष में आते जाते रहते हैं । यह कोई ठीक नहीं है आप कभी इधर आइयेगा हम उधर जायेंगे । लेकिन इतना नहीं करिये कि कटुता बढ़ जाय । आपलोग कटुता बढ़ाने की बात करते हैं । माननीय मुख्यमंत्री कल नहीं थे कल जो घटना घटी और जब मैं अपना डेरा से यहां आता हूं तो बहुत अच्छे लोग मिलते हैं रोड पर कहा कि आपलोग इतना तू तू मैं मैं करते हैं जो टी0वी0 पर लोग देखता है । महोदय, मैं देखा हूं माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को मैंने उनके साथ काफी समय बिताया है । इमरजेंसी के समय में मैं उस समय शिक्षक था और मेरे घर के बगल में गए थे वे रहने के लिए । वे पक्ष के लोगो से डा0 जगन्नाथ मिश्रा जी से भी बात करते थे उनको थोड़ा भी हिचक

नहीं था अपने डेरा से उठकर जाते थे मंत्री के यहां बात करने के लिए वे विपक्ष के नेता थे । कभी भी कटुता नहीं होती थी । और इस तरह की कटुता होती है तो पूरे समाज के लोग उसका मजाक बनाते हैं । इसलिए निश्चित रूप से अपने मर्यादा का पालन करना चाहये । हमलोग अपने मर्यादा का पालन करते हैं । मैंने पहले ही कहा मेरा अधिकार बनता है हम विपक्ष में हैं आपकी आलोचना करने का अधिकार बनता है । इसका मतलब यह नहीं कि हर बात में धमकी दें और इस तरह का काम करें । निश्चित रूप से यह निंदनीय है । इसकी चिंता होनी चाहिए ।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा । आज का एक मुद्या है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग का भी आज बजट है । हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं । मैं 2005 से लेकर आजतक जितने भी आवासीय विद्यालय हैं आज तक शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई । उस समय भी कहा गया था । हमारे समाज के लोग कल्याण मंत्री होते हैं लेकिन एक विज्ञापन निकला है दस वर्ष से आवासीय विद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षक नहीं हैं । जहां 51 शिक्षक होने चाहिए मधुबनी जिला में तीन आवासीय विद्यालय है वहां मात्र 9 शिक्षक हैं । इसलिए निश्चित रूप से आपसे आग्रह करता हूं ।

सभापति(श्री हरि ना0 सिंह): अब आप समाप्त करें ।

श्री रामप्रीत पासवान: एक मिनट महोदय । एक पत्र मैं देखा हूं कल्याण विभाग से पत्र गया है कि अब अनुसूचित जाति के बच्चे का नामांकन पहला में नहीं होगा छठा से होगा । यह निशचित रूप से गलत है निश्चित रूप से पहला से ही आवासीय विद्यालयों में नामांकन कराइये उसको खंडित नहीं करें । इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुन: सभापति जी को बधाई देता हूं और अपने नेता को बधाई देता हूं और अपनी बातों को समाप्त करता हूं । जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम ।

श्री राहुल तिवारी: सभापति महोदय जी, मैं आज 2016-17 के बजट के समर्थन में और उर्जा बजट अनुदान के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं । साथ ही साथ यहां उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि पिछले गठबंधन की जो सरकार थी फासिस्ट ताकतो को रोकने के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी की परवाह न करते हुए महागठबंधन तैयार किया । इससे बिहार में जो महान सफलता माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं ।

क्रमश:

टर्न–16/बिपिन/17.3.2016

श्री राहुल तिवारी: क्रमश: आज मैं यहां ऊर्जा के विषय पर बोल रहा हूं । मैं बताना चाहता हूं कि ऊर्जा के बिना जीवन अधूरा है । ऊर्जा हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए अनिवार्य अंग हो गई है । इसका इस्तेमाल हमने आर्थिक विकास में तेजी लाने, रोजगार पैदा करने, गरीबी दूर करने, मानव विकास के लिए किया जाता है । सभापति महोदय, बिहार की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हो रही है । इस विकास को आगे ले जाने के लिए बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका है । मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चुनौती से निबटने के लिए हमारी सरकार ने पिछले दो वर्षों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है इसलिए बिजली का औसत उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में जो पिछले 6–7घंटे हुआ करती थी, आज के दिन में 17–18घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मिल रही है और शहरी इलाके में जो 16–17घंटे, 18घंटे हुआ करती थी, आज 20–22घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है । यह हमारी सरकार की उपलब्धता है । इस दृष्टिकोण से बिहार में जो आज 40प्रतिशत् बिजली की, ऊर्जा की बढ़ोत्तरी हुई है जिसके चलते बिहार देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है । मैं यह बताना चाहता हूं कि बिहार बिजली उत्पादन की खरीद 2010–11 में 01,088करोड़ यूनिट बढ़कर 2014–15 में 1741करोड़ यूनिट हो गई है । बिजली की खरीद के बढ़ने के साथ–साथ वसूली भी बढ़ी है । सभापति महोदय, 2011में 62प्रतिशत् बढ़कर 2014–15 में 90प्रतिशत् करीब पहुंच गई है । फलत: इससे हमारी वित्तीय हानि जो थी वह 31प्रतिशत् से घटकर 11प्रतिशत् हो गई है । यह हमारा सराहनीय कदम है । साथ–ही–साथ सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 88प्रतिशत् ग्रामीण आबादी वाला बिहार सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रीय राज्य है । इसको देखते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के नाम से जाना जाता था, उसके तहत 38 जिलों में बिहार राज्य सरकार द्वारा विद्युतिकरण का कार्य चल रहा है । सभापति महोदय, बिहार सरकार ने बिहारवासियों के लिए 24घंटे बिजली देने की योजना बनाई है । इसके लिए बिहार सरकार ने कुछ कार्य बिहारवासियों के लिए किये । विशेष शिविर लगाकर कनेक्शन देने की व्यवस्था की जा रही है । परियोजनाओं के उचित अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर उपयुक्त अभियंता पदस्थापित किए गए हैं । राजस्व प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय अधिकारी के मासिक परीक्षण का कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है । नए कनेक्शन के लिए और बिजली की शिकायतों के लिए ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । बिजली बिलों के भुगतान के लिए नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा बिहारवासियों को उपलब्ध कराई गई है । यहां तक कि कॉटी थर्मल पावर का जीर्णोद्धार करके जो ढ़ाई सौ मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, उसको 500मेगावाट किया गया

है। बरौनी थर्मल पावर का जो ढ़ाई सौ मेगावाट था, उसका विस्तारीकरण करके 500मेगावाट किया गया है । चौसा में 320मेगावाट पावर प्रोजेक्ट के लिए बिहार सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण की गई है । इन सारी बिहार की उपलब्धियों को देखते हुए आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बिहार एक आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्य है । इसको पैसे की जरूरत है और केन्द्र सरकार कई शहरी योजनाओं के मद में जो आर्थिक मदद बिहार सरकार को दे रही थी, उन योजनाओं में काफी कटौती की गई है । इस तरह के कटौती प्रस्ताव की मांग का मैं विरोध करता हूं क्योंकि बिहार को पैसे की जरूरत है । मैं कुछ अपने क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके में तीन पंचायत काफी पिछड़ा है - लालू का डेरा, दामोदरपुर पंचायत और सोहिया पंचायत । अभी तक बिजली नहीं पहंच पाई है । पहले बिजली थी लेकिन उसकी तार जर्जर अवस्था में है । हम कहना चाहेंगे कि इसको ध्यान में रखकर मंत्री महोदय और ...

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त करें ।

श्री राहुल तिवारी: एक मिनट । प्राइवेट कंपनियां जो काम कर रही है मेरे इलाके में, जो बजाज कंपनी है, उसके सुपरवीजन का कार्य जो कर रहा है, उसकी देख-रेख करने वाले में आती है। जो हमलोग समस्या उस कंपनी को बताते हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे पास पोल की उपलब्धता की कमी है जिसके चलते इस पर भी ऊर्जा मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए । जल्द-से-जल्द पोल उपलब्ध कराएं ताकि बिजली गांव में सरल तरीके से पहुंच सके । बोलने देने के लिए सभापति महोदय, धन्यवाद ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा: महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा जो अनुदान मांग प्रस्ताव सदन में रखी गई है, मैं उस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं ।

महोदय, बिजली जीवन की बुनियादी मानवीय आवश्यकता है । आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए रोजगार पैदा करने के लिए, गरीबी निवारण, मानव विकास में बिजली की मुख्य भूमिका है । औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए, परिवहन के विकास के लिए, घरेलू विकास के लिए बिजली की आवश्यकता है । मानव विकास का यह आधार स्तभ्भ है । बिजली के बिना मानव की जीवन गति रूक जाती है । बिजली के कारण मनुष्य के जीवन में आर्थिक स्थिति पर काफी असर पड़ता है । बिजली की खपत हर जगह जरूरी है । यूं कहिए तो हर पल बिजली की जरूरत है । बिजली के अभाव में राज्य और देश की उन्नत्ति और विकास संभव नहीं है । बिजली से आज बिहार की अर्थ-व्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है । लेकिन बिजली की कमी के कारण टिकाऊं होने की आशंका है । महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूं कि बिजली का जो उत्पादन है, बिहार में जो पूर्व में था,

वह नगन्य था । यहां संचरण, वितरण की स्थिति काफी दयनीय थी लेकिन माननीय श्री नीतीश जी के अथक प्रयास से बिजली में काफी सुधार आया है । इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी को और ऊर्जा मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि अथक प्रयास उन्होंने किया जिससे आज बिजली में सुधार हुआ है । आज बिजली की स्थिति काफी अच्छी है । हम समझते हैं कि 24घंटे में 22घंटे, 24घंटा बिजली उपलब्ध रहता है । महोदय, प्रति व्यक्ति खपत बिजली 145किलोवाट से बढ़कर 2014-15 में 203किलोवाट हो गई है, जो अब तक के वर्षों में 40प्रतिशत् की वृद्धि हुई है । महोदय, आपको जानकार खुशी होगी कि बिहार अकेला राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने में सबसे अव्वल है, सबसे आगे है । आपको जानकर खुशी होगी कि 37हजार गांव में बिजली पहुंचा दी गई है और मात्र 1385 गांव ही बचे हुए हैं जहां बिजली पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है । महोदय, देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचाकर गांव को स्मार्ट बनाना चाहती हैं । देश के किसी भी अन्य राज्य में अब तक ऐसा काम नहीं हुआ है । महोदय, श्री नीतीश कुमार जी के सात निश्चय, हर घर बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य है, अगले दो वर्ष में निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा । सरकार अपने संसाधन के माध्यम से सभी घरों को बिजली कनेक्शन की सुविधा सुनिश्चित करने के साथ 24घंटे बिजली उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक अद्भुत सरकार ने फैसला किया है । महोदय आजादी के 69वें साल में बिहार ने जो मुकाम हासिल किया है, नीतीश कुमार जी ने जो गांव को स्मार्ट बनाने का बीड़ा उठाया है, घर-घर बिजली पहुंचाने का, नल, पानी, गली, नाला, शौचालय बनाने का जो फैसला किया है, इसके पहले देश के अन्य किसी राज्य में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ । महोदय, विपक्षी सदस्य तो हल्ला करते ही रहते हैं, मैं बताना चाहता हूं विपक्षी सदस्य को कि जरा बिजली पर जो चर्चा कर रहे थे हमारे सम्मानित डाक्टर साहब, सुनील जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि इसके पहले जो बिजली उत्पादन था, वह भी देखे हैं । आज की बिजली की स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री ने जो क्रांति लाई है, उत्पादन, संरक्षण, वितरण के लिए ठोस पहल किया गया । महोदय, सरकार अथक प्रयास कर तीन लंबित परियोजना पर कार्य कर रही है .. क्रमशः

टर्न–17/राजेश/17.3.16

श्री उमेश सिंह कुशवाहा, क्रमशः- चौसा–बक्सर–पिरौती–कजरा का ग्रीन फिल्ड परियोजना सरकार शुरु कर रही है, 2017 में हम खुद आत्मनिर्भर होकर दूसरे राज्य में बिजली देगे। सभापति महोदय, बिजली के क्षेत्र में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण योजना चला रही है, स्पेशल प्लान फेज–1 एवं फेज–2 के तहत बिहार बिजली के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति आयी है, विभिन्न अनुमंडलों में पावर सब स्टेशन, नया ट्रान्सफर्मर प्लांट, एच0टी0/ एल0टी0 लाइन का अभियान चलाकर विद्युतीकरण का कार्य चलाया जा रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिजली में जो आज क्रांति आयी है,वह देखने लायक है, यहाँ 22 से 24 घंटा बिजली उपलब्ध रहती है महोदय, बिजली का काम बहुत ही तेज गति से हो रहा है, यह सब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देन है, मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एवं उर्जा मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी को बहुत–बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अथक प्रयास से जो बिजली में सुधार लाया है, इन्होंने जो काम किया है,वह सराहनीय है। महोदय, मैं अब अपने क्षेत्र की ओर ले चलता हूँ जहाँ जनदाहा में हम समझते हैं कि महनार–जनदाहा में 11 के0भी0ए0 का ट्रान्सफर्मर जला हुआ है,हलाँकि हमारे क्षेत्र में काफी बिजली का काम हुआ है, पर 11 के0भी0ए0 एवं 16 के0भी0ए0 के ट्रान्सफर्मर जो हैं,वह जला हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको राज्य योजना से बनवाया जाय और महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार हमारा कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ जो हैचरी जो कृषि आधारित रोजगार यहाँ चल रहा है, हैचरी है, कोल्डस्टोरेज है,हम जानते हैं कि कृषि पर आधारित अनेक योजनाएँ चल रही हैं,इसलिए हम चाहते हैं कि कृषि पर आधारित जो रोजगार चल रही है उसके संबंध में माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि उसको सहायता के लिए उसको भी अनुदान दिया जाय और कृषि के लिए जो अनुदान अन्य राज्य में है और कृषि पर आधारित जो यह सब योजनाएँ हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय उर्जा मंत्री जी से मांग करता हूँ कि वे कोल्डस्टोरेज, हैचरी और चुज्जा उत्पादन और चिप्स आदि सभी चीजों में अनुदान दिया जाय, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं तमाम उपस्थित सदस्यों को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह):- माननीय सदस्य विनय वर्मा जी, इंडियन नेशनल कॉग्रेस, आप 6 मिनट में अपनी बात को रखें।

श्री विनय वर्माः- सभापति महोदय, मैं उर्जा एवं पर्यटन विभाग के बजट के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोल रहा हूँ। मैं बिजली विभाग के लिए हमारे माननीय मंत्री श्री

विजेन्द्र प्रसाद यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और बिजली विभाग के पदाधिकारियों को मैं अपनी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि इनलोगों के अथक प्रयास से आज बिहार में बिजली की समस्या लगभग 80 प्रतिशत सौल्व कर दी गयी है। जहॉ तक बिजली का सवाल है,इसमें सिर्फ एक कमी महसूस हो रही है और यह सच्चाई भी है कि लोगों को जरा ज्यादा बिल आ रहा है,अगर उस बिल को विभाग सुधार करें, तो हमें लगता है कि कोई भी कमी बिजली विभाग में नहीं रह जायगी और दो साल में जब हमलोग वोट मॉगने जायेंगे, तो हमारे विपक्षी साथियों को हमारे विरुद्व कोई भी बात बोलने का नहीं रह जायेगा। सभापति महोदय, मुझे पर्यटन पर बोलने के लिए कहा गया है, तो पर्यटन का जहॉ तक सवाल है, तो बिहार का गौरवशाली अतीत, समृद्वि, सांस्कृतिक विरासत, पौराणिक एवं धार्मिक स्थल इसकी बहुरंगी प्रकृति छटा सदियों से पर्यटकों को बिहार आकर्षित करती रही है। सभापति महोदय, बिहार शब्द का उद्गम बिहार से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है घर, इसलिए वास्तव में हमारे पर्यटकों का बिहार घर है, आज के दौर में पर्यटकों की दृष्टि में बिहार जैसा और कोई दूसरा स्थान नहीं है। यहॉ हर धर्मावलंबी के लिए पर्यटक स्थलों की भरमार है। पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा जगह है जहॉ 6, 7 सर्किट हैं, जैसे बौद्व सर्किट है, जैन सर्किट है, रामायण है, सूफी है, सिख है और गॉधी से संबंधित पर्यटन स्थल सर्किट है। जहॉ तक बौद्व सर्किट का सवाल है सभापति महोदय, बौद्व सर्किट में दर्शनीय स्थान ये सभी बिहारवासियों को पता है कि बोध गया, मुंडेश्वरी, राजगीर, नालंदा, वैशाली, लौरिया, नंदनगंज एवं केसरिया आते है, उसीतरह जैन सर्किट में जैन स्वावलंबियों को बिहार में खास महत्व है, नालंदा जिला के पावापुरी में जल मंदिर, राजगीर में सोन भंडार, मनियारमठ, कुंडलपुर और विरायतन है,नवादा जिला में जैन मंदिर गोनहा, भोजपुर जिला के आरा में पेशराम मंदिर एवं मंसारा मंदिर है, बॉका जिला में मंदार पर्वत, जमुई जिला में लछुआर मंदिर, पटना जिला में कमालदह मंदिर एवं भागलपुर जिला में चंपानगर, उसीतरह रामायण सर्किट में बिहार में अनेक स्थान राम-सीता से जुड़े हुए हैं,इनमें से प्रमुख है मिथिला-सीतामढ़ी गिरजा स्थान, कालेश्वर महादेव शिवमंदिर, धनुका, अलिया स्थान एवं बाल्मिकीनगर, यहॉ सूफी सर्किट के अनेक सूफी केन्द्र हैं, जैसे मनेरशरीफ, बिहारशरीफ,फुलवारीशरीफ,पटनासिटी में शाह अरजानी की दरगाह, खामखाह मुनिमियॉ, मंगल तालाब पर स्थित खानोखा ईमादिया प्रमुख सूफी केन्द्र हैं, इसके अतिरिक्त हमारे माईनरिटी मुसलमान भाईयों के लिए भी कई महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे हाजीपुर में हजरत जमदाहा का मकबरा, मुजफ्फरपुर के पास पक्कीसराय में मकबरा, जहानाबाद के पास काको में हजरतगिरी-कमाजसाहिबा का मकबरा, औरंगाबाद में अम्बरशरीफ और

खगड़िया जिला में पीरनगर, सिख सर्किट जो यहाँ का पॉचवा सर्किट गिना जाता है, को पटना साहिब सिख भाईयों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैै, तख्त हरिमंदिर जी गुरुद्वारा जहाँ गुरु का वास अपेक्षित है, पर्यटन विभाग ने विगत वर्षो में राज्य भर के पर्यटक स्थलों पर सुविधा में वृद्वि हेतु कई कार्य किये है, गत वर्ष पर्यटक स्थलों पर एक करोड़ 61 लाख रुपये की योजना पूर्ण की गयी है, जिनमें से प्रमुख राजगीर स्थित पांडुपोखर, गया में दशरथ मांझी स्मारक का विकास, मनेर शरीफ स्थित खानका में पर्यटक सुविधाओं का विकास, सुपौल जिला के वीरपुर में होटल वीरविहार का विकास, सीतामढ़ी के टुनौरा ग्राम में प्रवचन हॉल का निर्माण, बक्सर में कन्फ्रेंस हॉल का निर्माण, मधेपुरा में विष्णु राउत मंदिर में पर्यटकीय सुविधा का विकास इत्यादि महत्वपूर्ण है। बिहार में पर्यटकों को और अधिक बढ़ावा देने और उस स्तर तक बिहार की पहचान बनाने के लिए राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के राजगीर महोत्सव, बौद्व महोत्सव, हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के साथ-साथ कई मेलाओं का आयोजन किया जाता है। बिहार पर्यटन के लिए 2016-17 एवं 17-18 अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इस अवधि में हमारे यहाँ दो अति महत्वपूर्ण आयोजन किया जाना है, जिसपर पूरी दुनिया की दृष्टि होगी। आगामी 2017 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविन्द सिंह जी की 350 जयंती समारोह की पूरे श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जाना है, हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर से इस अवसर पर 50 लाख से 1 करोड़ लोग पटना के पटना साहिब के पवित्र स्थान के दर्शन के लिए पधारेंगे।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह):- अब आप समाप्त करें।

श्री विनय वर्मा:- जी। अब आ गया गॉधी सर्किट। गॉधी सर्किट में महात्मा गॉधी 1917 में हमारे चंपारण से निलो के खिलाफ सत्याग्रह शुरु किये थे।

क्रमशः

टर्न-18/कृष्ण/17.03.2016

श्री विनय वर्मा (क्रमशः) महोदय, मैं चम्पारण का रहनेवाला हूं । मैं नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र से आता हूं । चम्पारण में लौरिया में अशोक स्तम्भ है और रामपुरवा एक गांव है, जहां सोलर यूनिट लगाया गया है । रामपुरवा गांव में जो स्तम्भ था, उस पर बैल का चिन्ह है जो याद दिलाता था कि यह खेतीबाड़ी की जगह है और वहां पर बुल का जो चिन्ह था वह आज राष्ट्रपति भवन में अशोका हॉल के सामने रखा हुआ है ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें ।

श्री विनय वर्मा : महोदय, मैं चम्पारण जिला पर्यटन के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है । दो मिनट दिया जाये, दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । सन् 1911 में जब कलकत्ता से राजधानी उठकर दिल्ली दरबार होने जा रहा था, उस समय किंगजोर शिफ्ट वहां पर आये हुये थे । वह शिकार के लिये आये थे । वहां प्रकृति की, हिमालय की छटा इतनी सुन्दर है कि उस जगह को लोगों ने चुना था । सन् 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आये थे ओर सन् 1938 में यहा के वायसराय लॉर्ड आये थे ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री शंभुनाथ यादव जी, आपका 6 मिनट समय है ।

श्री शंभुनाथ यादव : सभापति महोदय, मैं इस सदन का नमन करता हूं और इस सदन के माध्यम से पूरे बिहार के दलित, महादलित, तमाम जनता को सलाम करता हूं । महोदय, अभी मुझे बिजली के विषय में बोलने के लिये मौका मिला है । बिजली क्या, विकास कोई छिपी हुई चीज नहीं है । यदि हमारे साथियों को बिजली देखना है तो चलिये हमारे ब्रह्मपुर विधान सभा क्षेत्र में जहां पूरा का पूरा दियारा का इलाका है और उस दियारा इलाका में 70 साल के बाद, आजादी के बाद इस शासनकाल में बिजली गयी है, आज की तिथि में लोग श्री नीतीश कुमार जी का माला जप रहे हैं, महागठबंधन का माला जप रहे हैं । महोदय, वह एक ऐतिहासिक जगह है, जहां हमने उस दियारा में खास प्लांट लगाया है, सोल हरजोत फ्लावर मिल, जो एक प्राईवेट लिमेटड कंपनी है, मैं महीने का 10 लाख रूपये का बिजली बिल देता हूं । उस दियारा में मैं अपना 24 घंटे मिल चलाता हूं । लोग तो बोलने के लिये कुछ भी बोल देते हैं । लेकिन मैं एक उदाहरण हूं इस सभा में महोदय ।

महोदय, समय के हिसाब से मैं अपने क्षेत्र की कुछ समास्याओं को सदन में रखना चाहता हूं । हमारे यहां 2009 में पानी का एक सर्फेस प्लांट खोला गया था जिसको 30 महीने में तैयार होना था । लेकिन उस काम को ठीकेदार या सरकार क्या कहा जाय, बुरी तरह से वह छितरा गया है, करोड़ो रूपया सरकार का उसमें खर्च हो गया है और आज वह वीरान पड़ा हुआ है और कोई देखने के लिए तैयार नहीं है । खास करके हमारे दियारा इलाका का इतना दूषित पानी है, काफी समय तक समाचार पत्रों में निकलता रहा, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि उस काम को देख लिया जाय चूंकि लोगों को काफी परेशानी हो रही है, उस काम के हो जाने से काफी लोगों को राहत मिलेगी और लोगों का मनोबल ऊंचा होगा । महोदय, उसी तरह की समस्याा

एक और है । हमारे दियारा इलाका में गंगा छाड़न एक जगह है, जो दो पंचायत के बीच में पड़ता है । वहां एक नदी है भागड़, हमलोग दियरा को भागड़ कहते हैं, नदी के इस पार 60 हजार लोग रहते है । वहां एक पुल बनना आवश्यक है । आजादी के 70 साल के बाद आज भी लोग नाव पर चढ़कर उस पर खेती बारी करने जाते हैं क्योंकि इधर के लोगों का नदी के उस पार खेत है । दियारा के लोगों का आजादी के बाद भी आज उस पार जाने का केवल वही एक रास्ता है । इसलिए मैं आप के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उस पुल के बन जाने से वहां के लोगों को काफी राहत मिलेगी । हमारे दियारा इलाका में एक गंगा जी हैं, हमलोग यू0पी0 के बोर्डर पर बसे हुये हैं । बोर्डर पर गंगा जी के बाढ़ को रोकने के लिये बक्सर कोईलवर तटबंध बना हुआ है । मेरा सुझाव है कि उस तटबंध को यदि सरकार रोड बना देती तो वह सुरक्षित बच जायेगा । वह 1980 का बांध बना हुआ है, आज की तिथि में वह जहां-तहां से कट गया है । उसको सुरक्षित रखने के लिये उस पर यदि रोड सरकार बना देती है तो वह सुरक्षित रह जायेगा, उसमें काफी राशि सरकार ने खर्च की है । महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में ब्रह्मपुर एक गांव है, वहां बहुत बड़ी एक बस्ती है, वहां 14 हजार वोट है, काफी जनसंख्या है और उस गांव में बहुत बड़ा नाला है, उसके बगल में मस्जिद भी है और मंदिर भी है और दोनों सटा हुआ है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब यात्रा में थे तो संयोग से वहां रूके हुये थे, जैसाकि लोग बताते हैं । इनके कहने के बाद बात कुछ आगे बढ़ी थी लेकिन वह काम अधर में पड़ा हुआ है । जब पानी होता है तो उस मस्जिद और मंदिर में पानी घुस जाता है । वह विधायक फंड के बस का नहीं है । सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस काम को ब्रह्मपुर विधान सभा क्षेत्र में कराना अत्यंत ही आवश्यक है ।

महोदय, जिस तरीके से हमसे कल माफी मंगवाया गया, तो मैं आप से जानना चाहता हूं चूंकि जो खोखता है, उसका भी सी0डी0 तैयार होता है । तो हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, गाली दिया तो वह सामने आना चाहिये । चूंकि हमको तो रातभर लोगों ने सोने नहीं दिया । लोगों ने कहा कि भई, आप क्या कर दिये कि आपको माफी मांगना पड़ा । हमने तो उस तरह की कोई गलती नहीं की तो फिर भी आसन का आदेश हमने माना । जब हल्ला हुआ तो कोई भाई बोल रहे थे । हमने अपने कान से सुना । यह सिपाही है हो । इसका मन बढ़ गया है । महोदय, मैं इस सदन में इस बात को गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि कभी एक सिपाही, जब ये लोग राजनीति में नही आये होंगे तो एक

सिपाही मंत्रिमंडल में मंत्रालय चलाया है । माननीय रामानन्द तिवारी एक सिपाही थे, वह सिपाही से सदन तक आये और पुलिस मंत्रालय चलाये । सभापति महोदय, आपको धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और विपक्ष को भी बता देता हूं । भगवान इतना बढ़िया हमको चेहरा दिये हैं और यह पूर्व जन्म का कमाई है कि हम यहां पहुंचे हुये हैं । हम बहुत बड़ा टीका कर लेते हैं और हाथ में लाठी ले लेते हैं और एक अनबोलता जानवर को मारते-मारते उसको बेहोश करके धरती पर गिरा देते हैं ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य,आप बैठ जाईये । माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार जी, जनता दल यूनाईटेड । आप का 10 मिनट का समय है ।

श्री मनीष कुमार : सभापति महोदय, आसन से आज बिजली विभाग के बजट प्रस्ताव के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर मिला है । मैं आपके माध्यम से आसन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं । साथ ही अपने नेता का आभार व्यक्त करता हूं । महोदय, जिस विषय पर मुझे बोलने का अवसर मिला है वह आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है और कहा जा सकता है कि बिजली आधुनिकता का एक प्रतीक है और आज इसी विषय पर मुझे बोलने का अवसर मिला है ।

क्रमश :

टर्न-19/सत्येन्द्र/17-3-16

श्री मनीष कुमार(क्रमशः) मानव शरीर के सफल संचालन के लिए जिस प्रकार से धमनियों में सफल रक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से इस आधुनिक युग में सफल संचालन के लिए बिजली की भी महत्ता है महोदय। अगर शरीर के धमनियों में रक्त प्रवाह में अगर किसी प्रकार की बाधक आती है तो सचमुच शरीर बिचलित हो जाता है शरीर कष्टदायक हो जाता है महोदय और लोगों को अस्पताल दौड़ना पड़ता है उसी प्रकार से इस आधुनिक युग में अगर बिजली की कटौती हो जाय, बिजली न होने की ही कल्पना से हमारा शरीर सिहर उठ जाता है और सारा काम ठप्प हो जाता है। महोदय,अंधेरे की कल्पना मात्र से ही शरीर सिहर उठ जाता है महोदय और उस अंधेरे को दूर करने का संकल्प हमारे नेता विकास पुरूष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प लिया है इस विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय विकास पुरूष श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी के प्रयास से उस संकल्प को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। महोदय, मैं इसके लिए आज माननीय मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी के कार्यशैली को देखते हुए पूरे सदन के माध्यम से उनके

प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में बिहार में बिजली की गुणवत्ता में अथक सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। महोदय,जिस प्रकार से बिजली पहले बड़े घराने के रौनक हुआ करती थी, बड़े घराने की राज रजबाड़े की पहुंच हुआ करती थी महोदय, एक जमाना हुआ करता था जब हमलोग भी छोटे थे तो सचमुच गांव में जो सबसे बड़े घर होते थे उसके यहां यह सिर्फ बिजली की पहुंच होती थी और हमलोग अंधकार में रहते थे। महोदय यह उस समय का काल था हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने यह संकल्प लिया है कि जो चीज बड़े घराने की पहुंच होती थी आज हर गरीब के घर तक उसे पहुंचाने का निश्चय आदणीय नीतीश कुमार जी ने लिया है, हर घर को, हर गरीब घर को घर तक बिजली पहुंचाने का संकल्प आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लिया है महोदय। आज बिजली उपलब्धता के बारे में हमारे साथीगण के द्वारा जो कहा गया बिल्कुल सच्चाई है, हम लोग भी गांव के परिवेश से आते हैं और गांव में एक समय ऐसा था सचमुच बिजली नगण्य रहती थी। महोदय, महीनों में एकाध बार कभी बिजली देखने का अवसर मिलता था और आज जब गांव जाते हैं तो सचमुच हमारे साथीगण कह रहे थे कि 22 घंटे मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि मैं जिस गांव से आता हूँ वहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। ठीक ही कहा हमारे साथी ने कि हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तो शहर से आते हैं हालांकि सिर्फ प्रतिपक्ष के नेता नहीं महोदय हमारे प्रतिपक्ष के जितने साथीगण है उनमें से ज्यादातर शहर से आते हैं उनलोगों ने बचपन से बिजली को आभास किया है इसलिए बिजली की पीड़ा उनको नहीं पता है महोदय। जो ग्रामीण स्तर से लोग आते हैं हमलोग पक्ष के लोग हैं जिन लोगों का सरोकार ग्रामीण क्षेत्र से है, ग्रामीण परिवेश से है हमलोगों ने बिजली के कष्ट को अनुभव किया है महोदय,बिजली की पीड़ा को महसूस किया है महोदय। बिजली सचमुच एक जरूरत की चीज है? आज हर घर में यह एक आवश्यकता की चीज है आज वस्तु के रूप में बिजली है, हर घर की पहुंच, हर घर की चाह हर घर की आवश्यकता बिजली है महोदय आज इसी विषय पर मुझे बोलने का अवसर मिला है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में संकल्प लिया गया है आदरणीय नीतीश कुमार जी की सोच है कि हर घर में बिजली पहुंचायेंगे। महोदय, बिजली विकास द्योतक है बिजली विकास का प्रतीक है हर घर तक में बिजली पहुंचाने का काम हमारे आदरणीय मंत्री आदरणीय विजेन्द्र प्रसाद यादव जी जिनसे कुछ सीखने के लिए मैं उनके पास बैठता हूँ कुछ अनुभव प्राप्त करता हूँ महोदय जितनी देर भी उनके पास बैठता हूँ मैं देखता हूँ कि हमेशा वो ऊंगलियों में गिनते रहते हैं। महोदय, मैं पिछली बार भी अपने भाषण में यह बात कहा था महोदय हमेशा जब वो ऊंगलियों में गिनते रहते थे हमलोग जानते हैं कि वह क्या गिनते हैं लेकिन कोई अनजान व्यक्ति जब उनके पास बैठता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि माननीय मंत्री ऊंगलियों में क्या गिनते हैं?

माननीय मंत्री जी को विकास की चिन्ता है, बिहार के ग्रामीण परिवेश की चिन्ता है, वो हमेशा ऊंगलियों में बिहार में कितने मेगावाट की उत्पादन बढ़े इनकी चिन्ता है। वह हमेशा ऊंगलियों में यह गिनते रहते हैं और उस गिनती में अगर एक मेगावाट का इधर से उधर हो जाता है तो वो विचलित हो जाते हैं कि एक मेगावाट कैसे घटोत्तरी हुआ। उनकी चिन्ता है कि हमारे बिहार में कैसे बिजली उत्पादन बढ़े, कैसे बिजली हर घर तक पहुंचे। स्वाभाविक है महोदय कि बिजली कोई जादू की छड़ी नहीं है महोदय कोई सड़क की तरह नहीं है कि अगर कोई बड़े व्यक्ति आने वाला है तो रात भर रौलर चलाकर और अलकतरा बिछाकर सड़क का निर्माण कराया जाता है ताकि चमचमाती गाड़ी उस अलकतरा वाली सड़क पर फर्राटे के साथ दौड़ पड़े। बिजली को उत्पादन करने में समय लगता है महोदय, बिजली को घर पहुंचाने में समय लगता है उसके लिए जो क्रियाएं है वो पांच से छः वर्ष का समय होता है। मुख्यतः बिजली तीन कार्य पर आश्रित होता है महोदय, पहला कार्य होता है जेनरेशन दूसरा होता है ट्रांसमिशन और तीसरा होता है डिस्ट्रीव्यूशन और अगर तीनों ठीक हो जाय तभी कहा जा सकता है कि सचमुच बिहार समृद्धता की ओर आगे बढ़ रहा है, हर घर में बिजली पहुंच रहा है महोदय। अब शुरूआत करता हूँ महोदय जेनरेशन से, स्वाभाविक है पहले बिजली शहर की शोभा थी, स्वाभाविक है हमारे प्रतिपक्ष के साथीगण ज्यादातर शहर से ही आते हैं महोदय,जो पहले इनके घरों की शोभा हुआ करती थी महोदय। बिजली शहरों में ही दिखा करती थी और पहले जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या और आबादी थी महोदय उसके अनुसार उतना समुचित उत्पादन हमारे बिहार में जो व्यवस्था थी उतनी हमारे लोगों को आवश्यकता जरूरतें नहीं थी।इसकी पूर्त्ति होती थी लेकिन जिस प्रकार से आज हमारे समान्य परिवेश से जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या के साथ -साथ लोगों की जरूरतें भी बढ़ी है आवश्यकतांए भी बढ़ी है और उस आवश्यकताओं को पूर्त्ति करने के लिए उत्पादन करना अनिवार्य है महोदय। पूर्व में हमारे यहां से उत्पादन बहुत कम हुआ करता था लेकिन मैंने कहा कि उत्पादन के साथ-साथ जितनी जरूरतें थे उन जरूरतों की पूर्त्ति होती थी। आज उत्पादन करना अनिवार्य भी हो गया है क्योंकि हमलोगों की जरूरतें बढ़ गयी है, आवश्यकताएं बढ़ गयी है। पहले हमारे यहां दो यूनिट हुआ करता था- एक बरौनी और एक कांटी हुआ करता था और उससे भी बहुत कम मात्रा में उत्पादन हुआ करता था लकिन आवश्यकता के अनुसार उस दोनों थर्मल पावर स्टेशन को उन्नयन कार्य करते हुए सुदृढ़ीकरण करते हुए जहां तक मुझे जानकारी है महोदय कि आज वहां से इसी जून 2016 तक महोदय सारे इकाईयों को ठीक करते हुए 1330 मेगावाट उत्पादन करने की क्षमता हमारे बिहार के कांटी और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की हो जायेगी। इसी प्रकार से महोदय बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लि0 और एन0टी0पी0सी0 से सहयोग ज्वायंट

भेंचर से इसी औरंगावाद के नवीनगर में हमारे यहां 1980 मेगावाट का उत्पादन 2017 तक शुरू हो जायेगा और जब भी उत्पादन होता है बिहार के लिए राज्य के लिए वह गौरव के साथ-साथ उससे हमें हिस्सा मिलती है और बिहार राज्य को जो हिस्सा मिलगा वह 1373. 50 मेगावाट हिस्सा मिलेगा। यह पहले का ही करिश्मा है और दूसरा फेज का कार्य फिर कुछ दिनों के बाद शुरू होगा उसमें भी 1900 मेगावाट का एकरारनामा हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है और उससे 1386 मेगावाट बिहार को बिजली मिलेगा । यह देखा जा रहा है कि हर वर्ष, मैं तो कह सकता हूँ गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हर महीने हमारे यहां उत्पादन की क्षमता बढ़ती जा रही है इसी बिहार में आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है और वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। विकास कार्य प्रगतिशील है बिहार में विकास कार्य इतने ज्यादा हो रहे हैं महोदय उतना ही हमारे यहां उत्पादन क्षमता भी बढ़ रहा है। पहले महोदय मैं कह रहा था कि आज जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने तीन महत्वपूर्ण ग्रीन फिल्ड परियोजनाओं पर भी कार्य शुरू किया है इसमें बक्सर, जहां से हमारे शंभू भाई आते है चौसा का चयन किया गया, भागलपुर जो झारखंड राज्य का बोर्डर है वहां के पीरपैंती है और कजरा है महोदय जो लखीसराय में आता है तीनों जगह का टेंडर और जमीन का अधिग्रहण सम्पूर्ण कर लिया गया है और बहुत जल्द ही तीनों जगह से 3960 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो जायेगा और बिहार के हिस्से में 3366 मेगावाट बिजली मिलेगा। सचमुच यह एक अदभूत करिश्मा बिहार के साथ हो रहा है महोदय। मैंने शुरूआत में ही कहा चूंकि उत्पादन से लेकर उसके वितरण तक में समय लगता है कोई सड़क का यह कार्य नहीं कि रात भर में सड़क बना दिया जाये।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह)अब आप समाप्त करें।

टर्न-20/मधुप/17.3.16

श्री मनीष कुमार : महोदय, राजनैतिक जीवन में जितना दिन संसदीय कार्य में मुझे मौका मिला है, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आप ही सभापति के रूप में हमेशा होते हैं और मुझे संभाषण करने का मौका मिलता है...

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री मनीष कुमार : मैं इसके लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ लेकिन हर बार, मैं आपकी उदारता की प्रशंसा करता हूँ कि आप मुझे दो-चार मिनट ज्यादा देते हैं ताकि कुछ बात मैं बोल पाऊं, महोदय ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें । अब आप बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार जी । 11 मिनट आपका समय है ।

श्री प्रमोद कुमार : सभापति महोदय, मैं बिजली विभाग की मॉग पर पेश कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सबसे पहले मैं आपको और अपने सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे बोलने का मौका दिया गया ।

महोदय, आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली का खपत कनाडा में है जहॉ 15467 है, सबसे कम खपत भारत में है जो 927 है और बिहार में मात्र 144 है। पूरे देश में सबसे कम बिजली का खपत बिहार में है । इसको समझिये और हमारे अधिकारीगण बैठे हुये हैं, समझ रहे हैं । जब-जब दिल्ली में गैर कांग्रेसी सरकार बनी है तब-तब बिहार को बिजली के क्षेत्र में सफलता मिली है । महोदय, आप जानते हैं कि सन् 1977 में देश में मोरारजी भाई की सरकार थी और बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी, माननीय मंत्री विजेन्द्र बाबू जानते हैं, कांटी का थर्मल पावर गैर कांग्रेसी सरकार के समय बना था । जब देश में मान्यवर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने तो बाढ़ का थर्मल पावर बना । महोदय, बीच कालखंड में यू0पी0ए0 सरकार आ गई । जब प्रधानमंत्री मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो एन0डी0ए0 सरकार ने लाया था प्रधानमंत्री बिजली योजना । प्रधानमंत्री बिजली योजना गॉव-गॉव जाना था लेकिन उसके बाद यू0पी0ए0 सरकार आई तो यू0पी0ए0 सरकार ने राजीव गांधी बिजली योजना बना दी । महोदय, राजीव गांधी बिजली योजना के बारे में हम सभी माननीय सदस्य अपने गॉव में देखते हैं राजीव गांधी का बहुत सुन्दर सा फोटो लगा हुआ एक बोर्ड दिखता है लेकिन 25 और 16 का ट्रासंफर्मर इस कदर है कि गॉव के गरीब तक बिजली नहीं पहुँचा सके । (व्यवधान)

बात सुनिये न भाई ! महोदय, जितने सदस्य अभी सदन में बैठे हैं, आपके क्षेत्र के भी सदस्य हैं, देखा जायेगा, मैं सरकारी लोक उपक्रम समिति में रहा हूँ और ऊर्जा सचिव भी वहॉ बैठे हुये हैं, स्वयं वे कई जगह जॉच किये हैं और हमलोग भी जॉच किये हैं, जो हालत है कि गलत-गलत उत्तर आ जाता है । 25 और 16 की जो हालत है, आज भी कई गॉव वंचित हैं जहॉ ट्रांसफर्मर नहीं बदला गया । गॉव के गरीब के पास बिजली वाला पाईप है, मीटर है, तार है । बिजली नहीं मिली लेकिन 10 से 25 हजार रूपये का गलत बिल उसके पास पहुँच गया । महोदय, राजीव गांधी बिजली योजना कागजी खानापूर्ति योजना बनकर रह गयी । इस बात को मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, कोई हिचक के साथ नहीं कहता हूँ

कि राजीव गांधी योजना में खानापूर्ति हुई । एन0डी0ए0 सरकार में जब हमलोग साथ थे विजेन्द्र बाबू, उसी समय हमलोगों ने तय किया था कि 25 और 16 की जगह पर हमलोग 63 और 100 का ट्रांसफर्मर देंगे । यह हमलोगों के एन0डी0ए0 गठबंधन की सरकार के समय में ही तय हुआ था, हुजूर । पहली बार 2010 के चुनाव के हमलोगों के घोषणा पत्र में था, हमलोग साथ मिलकर लड़े थे । (व्यवधान)

सुनिये न भाई ! कौन किधर आयेगा यह तो समय बतायेगा, भ्रमजाल में मत रहें। यह सौभाग्य है, प्रत्यय अमृत जी बार-बार दिल्ली जाते हैं और मैं अपनी आँख से देखा हूँ, भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब से मिनट-मिनट में बात करते हैं और रूपया लेकर आते हैं । ये धन्य हैं, ऊर्जा सचिव धन्यवाद के पात्र हैं और भारत सरकार धन्यवाद की पात्र है लेकिन ये लोग खम्भा और तार में उलझ गये हैं, बिजली का खम्भा और तार भी सही नहीं करा पाये ।

हुजूर, मेरे क्षेत्र में, जब यू0पी0ए0 की सरकार थी तो अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री मान्यवर नीतीश कुमार जी ने, लोक सभा चुनाव 2014 प्रारंभ होने वाला था, जनवरी महीना में राजीव गांधी बिजली योजना फेज-2 का टेन्डर कर दिया। यू0पी0ए0 सरकार रूपया नहीं दे सकी, काम कागज पर, 25 और 16 का ट्रांसफर्मर नहीं दिया । जब नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार दिल्ली में आई, बोलिये ऊर्जा सचिव जी, तब जाकर फेज-2 का रूपया आया । (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं और आसन की तरफ बार-बार अँगुली दिखाते हैं । माननीय सदस्य के पुराने सदस्य होने के नाते इसको संज्ञान में लिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार : सभापति महोदय, अभी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऊर्जा योजना है, इसमें भी भारत सरकार ने उदारता से दिया है, 75 परसेंट राशि भारत सरकार ने दिया है । सभापति महोदय, धन्यवाद की पात्र भारत सरकार है । ये लोग अपना पीठ अपने थपथपाते हैं, अपने जय हो - जय हो कहते हैं । महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ । 2008-09 में मैंने विधान सभा में एक प्रश्न किया था कि सरकार ए0पी0डी0पी0आर0 योजना से अपना बिजली सुधार करायेगी या नहीं । सरकार के पास पैसा नहीं था, बैंक से कर्ज लेकर आज वह काम चार साल से लम्बित है, बैंक के कर्ज का ब्याज दे रहे हैं, विजेन्द्र बाबू जवाब देंगे, अभी तक बैंक के कर्ज का ब्याज दिया जा रहा है, योजना पूरा नहीं करा सके । ...क्रमशः...

टर्न–21/आजाद/17.03.2016

श्री प्रमोद कुमार : (क्रमशः) यह देखिए, यह उस समय का आपके ही गठबंधन के मुख्यमंत्री का फोटो है, देख लीजिए अखबार भी । देखिए जीतन राम मांझी जी पीयूष गोयल को बुलाकर क्या कहते हैं कि हमको बिजली दीजिए । पढ़ लीजिए, अखबार क्या कहता है, हम नहीं कहते हैं । एक उदाहरण है हुजूर, एक बिजली बिल के बारे में उदाहरण दे रहा हूँ.....

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : एक मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार : एक बिजली बिल है विजेन्द्र बाबू, सेक्रेटरी साहेब सुना जाय, यह बिजली बिल जो है नरकटियागंज के एक आदमी का, जो बिजली बिल 19 महीना का 350गुना बढ़ गया रेट, हम कागज भेजवाते हैं, सारा बिल का कॉपी है । उसके बिल में एकाएक 350गुना बिजली बिल बढ़ गया । यह हाल है इनके बिजली बिल का ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री प्रमोद कुमार : हुजूर, एक मिनट पर्यटन पर बोलने दिया जाय । सत्याग्रह के मुख्यालय पश्चिम चम्पारण से मैं आता हूँ ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाईए । माननीय सदस्या श्रीमती पूर्णिमा यादव जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस । आपका समय 6 मिनट ।

श्रीमती पूर्णिमा यादव : सम्मानित सभापति महोदय, आज सदन में उर्जा विभाग के अनुदान मांग और कटौती प्रस्ताव पर जो वाद-विवाद हो रहा है, मैं अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । उर्जा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है । अतः इस महत्वपूर्ण विभाग का उत्तरदायित्व विगत 10 वर्षों से माननीय मंत्री श्री विजेन्द्र यादव जी के हाथ में है । जाहिर सी बात है कि माननीय मंत्री जी एक कर्मठ और योग्य व्यक्ति होने के साथ काफी अनुभवी भी हैं । बिहार विकास मिशन के 7 निश्चयों में एक निश्चय हर घर बिजली भी है । दो वर्ष पूर्व बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जब तक मैं बिहार के प्रत्येक गांव और प्रत्येक टोले में बिजली नहीं पहुँचा देता, तब तक मैं आप लोगों के बीच में वोट मांगने नहीं जाऊँगा । उन्होंने इस निश्चय को बखूबी पूर्ण भी किया । 2015 में पहला फेज में 11 जिलों में जून महीने तक 1149 गांवों में से 1085 गांवों में बिजली पहुँचा दी गई, दूसरा फेज में 27 जिलों के 2927 गांवों में से 407 गांवों में बिजली पहुँचा दी गई है, बाकी बचे हुए गांवों में बिजली पहुँचाने का कार्य प्रगति पर है । कुछ गांवों ऐसे थे जहां बिजली पहले से थी लेकिन किसी कारणवश वहां विद्युत आपूर्त्ति नहीं हो पा रही थी । ऐसे गांवों में बिजली पहुँचाने का काम तेजी से चल रहा है । दिसम्बर,2016 तक बाकी बचे हुए 32000 गांवों में बिजली पहुँचाने का काम शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा । उर्जा के क्षेत्र में 2015 बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि वाला साल रहा है । इस वर्ष 40 फिसदी बिजली उपलब्धता में वृद्धि हुई है । जिस कारण मात्र दो वर्षों में बिजली की खपत 145 यूनिट से बढ़कर 203 यूनिट प्रतिव्यक्ति हो गई है । राष्ट्रीय औसत से बिहार अब भी बिजली के खपत में पीछे है । देश में बिजली की खपत प्रतिव्यक्ति 1010 यूनिट है। इन सबके बावजूद बिहार के गांवों को 14 घंटे बिजली और शहरों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है । 16 के0वी0ए0 एवं 25 के0वी0ए0 के 25747 ट्रांसफर्मर को प्राथमिकता के आधार पर एम0सी0एल0ए0डी0 एवं मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत बदलने का कार्य किया जा चुका है । बिहार में औद्योगिक संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने बिजली की सारी बाधाओं को दूर करने की पहल तेज कर दी है । अपने 7 निश्चयों पर अमल करते हुए पावर होल्डिंग कम्पनी ने सूबे में लगने वाले उद्योगों को बिना रूकावट के अविलम्ब बिजली कनेक्शन देने का फैसला किया है तथा आवेदन देने के 15 दिनों के भीतर ही उन्हें नया कनेक्शन देने की स्वीकृति भी दे दी गयी है । राज्य में पीक लोड पर विद्युत आपूर्त्ति 2015 अक्टूबर तक बढ़कर 3459 मेगावाट हो गयी है । इसके अतिरिक्त बिहार

राज्य के कई जिलों में पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है । कई पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजे जा चुके हैं । बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के अन्तर्गत पाँच जिलों में 560 सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम का अधिष्ठापन कार्य जारी है, जिसमें 493 का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है । बिजली के सुविधा से वंचित रोहतास जिला के चेनारी विधान सभा का एक ऐसा ही कस्बा है, जहां आजादी के 68 साल बाद भी किसी ने बिजली नहीं देखी है । माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से वहां पर बिजली पहुँचाने की व्यवस्था की स्वीकृति दे दी गई है और राशि भी वहां पर उपलब्ध करा दी गई है । इसके अतिरिक्त बिहार में अपना बिजली उत्पादन इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1330 मेगावाट और 2017-18 में 3310 मेगावाट तथा 2021-22 तक 7270 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र गोविन्दपुर,नवादा है । मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ । रोह से कऊआकौल 33के0वी0ए0 का तार बिछाने की स्वीकृति बिजली विभाग के अध्यक्ष द्वारा दिया गया है परन्तु आज तक कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है । गोविन्दपुर विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली विस्तार का काम अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है । गोविन्दपुर विधान सभा क्षेत्र में ही लगभग 100 से ज्यादा जले ट्रांसफर्मर हैं, जिनकी सूची विद्युत विभाग को हमने पूर्व में ही दिया है लेकिन अभी तक उसपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है । नवादा जिले में उपभोक्ताओं को बिजली का बिल जहां 500रू0 आता है, वहां 1500रू0 का बिल चुकाना पड़ता है । इससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ और माननीय सदस्यों के प्रति भी । धन्यवाद ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्या श्रीमती समता देवी, राष्ट्रीय जनता दल, आपका समय 6 मिनट ।

श्रीमती समता देवी : महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत उर्जा विभाग की माँग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ ।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सात निश्चय में एक है घर-घर बिजली, गरीबों को मुफ्त कनेक्शन । हम संकल्पित हैं राज्य के गरीबों को रोशनी पहुँचाने के लिये । पहले जब दीपक की रोशनी में गरीब के बच्चे पढ़ते थे तो उनकी आँखों की रोशनी चली जाती थी लेकिन अब चकाचक रोशनी सब तरफ है ।

कितना बड़ा बवाल खड़ा किया कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर घर-घर बिजली नहीं दूँगा तो वोट मांगने नहीं आऊँगा लेकिन सच्चाई क्या है ?

सच्चाई यह है कि 15 अगस्त को उन्होंने भाषण दिया था कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो 2015 में मैं वोट मांगने नहीं जाऊँगा ।

सभापति महोदय, क्या सुधार नहीं हुआ है ? आप देखिये, सुधार हुआ है । शहरों में 20 से 22 घंटे तक, कहीं कहीं निर्बाध 24 घंटे तक शहरों में बिजली दे रहे हैं हम। देहाती और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटे तक दे रहे हैं । पहले जहॉ दो घंटे, चार घंटे बिजली मिलती थी वहां 14 घंटा से 16 घंटा बिजली मिल रही है । क्या यह सुधार नहीं है ? आप कौन सा सुधार चाहते हें ? आप तो कटौती करने में विश्वास करते हैं? राजीव गॉधी विद्युतीकरण योजना का नाम दीनदयाल कर दिया आपने लेकिन राशि में कटौती कर दी ।

मैं बहुत आंकड़े नहीं दूँगी लेकिन एक तुलनात्मक स्थिति बता देना चाहती हूँ । वर्ष 2007-08 में बिजली की उपलब्धता, आपकी मॉग थी 1800 मेगावाट और उपलब्धता थी 1244 मेगावाट, वर्ष 2008-09 में मॉग थी 1900, उपलब्धता थी 1348, वर्ष 2009-10 में मॉग थी 2200 मेगावाट और उपलब्धता थी 1508, वर्ष 2010-11 में मॉग थी 2250 मेगावाट और उपलब्धता थी 1664 मेगावाट, वर्ष 2011-12 में मॉग थी 2500 मेगावाट और उपलब्धता थी 1712 मेगावाट, वर्ष 2012-13 में मॉग थी 2650 मेगावाट और उपलब्धता थी 1802 मेगावाट, वर्ष 2013-14 में मॉग थी 3000 मेगावाट और उपलब्धता थी 2335 मेगावाट और वर्ष 2014-15 में मॉग है 3500 मेगावाट और उपलब्धता थी 2831 मेगावाट । ..... क्रमशः .....

टर्न:22/अंजनी/दि0 17.3.16

....क्रमशः...

श्रीमती समता देवी : बगैर ऊर्जा के आज कुछ नहीं हो सकता लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पीछे हैं । अल्ट्रा पावर प्लांट, अल्ट्रा पावर प्लांट सुनते-सुनते कान पक गये, आज तक शुरूआत नहीं हुई, जल्दी शुरूआत करा दीजिये, विपक्ष के सभी माननीय महानुभाव लोग । बिजली में 10 प्रतिशत् तक ट्रांसमिसन लॉस हो रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा व्यवसायी लोग चोरी कर रहे हैं । महोदय, मैं फिर कहना चाहती हूँ कि किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार है ऊर्जा, इसलिए राज्य सरकार सड़क और शिक्षा के बाद सबसे अधिक पैसा बिजली पर ही खर्च कर रही है और परिणामस्वरूप आज बिजली की उपलब्धता में गुणात्मक सुधार आया है । राज्य सरकार ने विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के उद्धेश्य से अनेक कार्यक्रम की शुरूआत की है । न्याय के साथ विकास की यात्रा पर लगातार कदम बढ़ाते हुए कई

क्षेत्रों में अपनी विशिष्ठ पहचान बनायी है, जिसे देखने-सुनने के लिए दूर-दराज से लोग बिहार आते हैं। कृषि, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य मानव विकास के साथ-साथ बिजली के क्षेत्र में भी सरकार ने सार्थक कदम उठाये हैं । जिसके सार्थक परिणाम आने लगे हैं । बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि पर निर्भर है, यह हम सभी लोग जानते हैं । हमारे राज्य में अधिकांश जगहों पर बहुत कम गहराई में भूगर्भीय जल उपलब्ध हैं । सिंचाई की उचित व्यवस्था और कृषि का आधुनिकीकरण कृषि क्रांति के लिए बहुत आवश्यक हैं और इस क्रांति के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण आवश्यकता है । बिजली के अभाव में कृषि उत्पादन के साथ-साथ औद्योगिक निवेश में भी कठिनाईयां आती थीं । विपक्ष के भाइयों, राज्य सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर छोटे शहरों तक में बिजली पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं और इसका लाभ भी मिल रहा है । बरौनी, कांटी थर्मल पावर में बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है । एन0टी0पी0सी0 में 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है । कांटी में 110 मेगावाट की दो इकाईयों का जीर्णोद्धार किया गया है, उसका नवीनीकरण किया गया है और उसके परिणामस्वरूप आज विद्युत की स्थिति में सुधार हुआ है । हमारे यहां 2017-18 तक यह उपलब्धाता बिजली की बढ़कर 6 हजार से 7 हजार मेगावाट हो जायेगी और इसकी पूर्त्ति के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प हैं । आपने मुझे समय दिया है, उसके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं पुन: मांग का समर्थन करती हूँ ।

गया जिला के बिजली मंत्री के प्रयास से गया जिला में बिजली में काफी सुधार हुआ है । गया जिला में एस0पी0एम0एल0 कम्पनी के द्वारा काम किया जा रहा है ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्रीमती समता देवी : महोदय, जो कार्य कराया जा रहा है, वहां दलित, महादलित टोले में विद्युतीकरण कार्य नहीं हो पा रहा है । बिजली कम्पनी जैसे तैसे कार्य पूरा कर रही है, जबकि अभी आधा ही काम हुआ है ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम, आपका दो मिनट समय है ।

श्री सत्यदेव राम : सभापति महोदय, आज ऊर्जा विभाग के बजट पर बात हो रही है । मैं समझता हूँ कि ऐसे तो सरकार के जितने भी विभाग हैं, वह सभी महत्वपूर्ण हैं, हम किसी को कम करके नहीं देखते हैं । कृषि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं लेकिन महोदय ऊर्जा विभाग एक ऐसा विभाग है कि सदन में सारे माननीय सदस्य बिहार के आधुनिकीकरण की बात करते हैं, सरकार आधुनिकीकरण की बात करती है तो मैं समझता हूँ कि बिहार के सुदूर इलाकों तक गांव-गांव में विद्युतीकरण

होना बिल्कुल आवश्यक है, जरूरी है । अगर इसमें किसी तरह की कोताही या उपेक्षा होती है तो आप बिहार के विकास की बात या दावा नहीं कर सकते हैं । इसलिए महोदय, मैं देख रहा हॅ कि गांव में अभी तार, पोल गड़ रहे हैं जरूर लेकिन कई स्तरों में इतनी कमजोरियां हैं कि जिससे हमारी समझ बदल जाती है । चाहे योजना जो भी चले एक तो मैं सारे विभागों के योजनाओं के बारे में जान रहा हूँ, विभाग की कोई भी योजना जाती है तो वह गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है और आज भी जो विद्युतीकरण की बात हो रही है, वह गरीबों के मुहल्ले छूट जा रहे हैं महोदय, दलित बस्तियां छूट जा रही हैं महोदय । यहीं नहीं, अगर कहीं-कहीं गया है तो जो एजेंसी काम करा रही है वह वसूली के नाम पर, बी0पी0एल0 धारियों को जो कनेक्सन देने का प्रावधान है, उसमें पांच-पांच सौ, एक-एक हजार रूपया वसूलने का काम किया जा रहा है और इसकी देखरेख नहीं हो रही है महोदय । हम कहना चाहते हैं खास करके सरकार से, माननीय बिजली मंत्री जी से कि हम बात भले ही लंबी-चौड़ी कर लें या बजट बना दें, इतने भर से काम नहीं चलेगा, इसपर आपको निगरानी करनी होगी, कई स्तरों पर निगरानी करनी होगी । महोदय, जहां अभी बिजली के तार नहीं लगे हैं, पोल गड़ गये हैं लेकिन उनके यहां बिल चला गया है महोदय । अगर इस तरह की कमजोरियां रहेंगी तो हम आधुनिकीकरण की बात नहीं कर सकते हैं, आधुनिकीकरण नहीं हो सकता है ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, हम अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूँ । जो दु:ख है, जो तकलीफ है, उसको मैं कह रहा हूँ । में नीति पर कोई बहस या आलोचना नहीं कर रहा हूँ । इसी बिहार विधान सभा के चुनाव में, मेरे दरौली विधान सभा क्षेत्र में कई गांव में लोगों ने बिजली के सवाल पर चुनाव का बहिष्कार किया, गुठनी प्रखंड के देवरिया गांव में ....

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी ।

श्री सत्यदेव राम : चुनाव का बहिष्कार किया । आंदर प्रखंड के, एक मिनट महोदय, बारी टोला ढ़ाई-तीन सौ घर यादवों का घर है, पहली बार उन लोगों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया कि हम वोट नहीं डालेंगे, इसलिए कि हमारे यहां बिजली नहीं लगा है ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी, आपका दो मिनट समय है ।

श्री राजू तिवारी : आदरणीय सभापति महोदय, मैं बजट कटौती के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, दो मिनट समय मिला है, दो-तीन विन्दु पर आपके माध्यम से आदरणीय बिजली मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ । मेरे विधान

सभा क्षेत्र गोविंदगंज जो जिला पूर्वी चम्पारण में पड़ता है । एक नम्बर पर वह कम्पनी है ई०एम0सी0, मैं वहां का भुक्तभोगी हूँ । जरूरत पड़ा तो मैं सदन को सबूत भी पेश कर सकता हूँ । वहां ई0एम0सी0 कम्पनी ने टेंडर ली है, उसके बाद उसने दिया है माता रानी कम्पनी को, माता रानी ने दिया है सोलंकी को और सोलंकी दे रहा है गांव के किसी बिचौलिए को और हर पंचायत के बारे में दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि एक लाख से डेढ़ लाख रूपया लेकर बिजली लगाने का काम किया जा रहा है । पहले पैसा लेकर बिजली लगाने का काम किया जा रहा है तो क्या यह सरकार की उपलब्धि है ? मैं पहली बार जीतकर आया हूँ, सरकार के खिलाफ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ । सरकार की उपलब्धि है कि आज बिजली गांव में है । यह मैं भी मानता हूँ दिल से कि बिजली है लेकिन सरकार के पदाधिकारी निरंकुश हैं, गांव में दो साल, तीन साल से ट्रांसफार्मर जल गया है और तीन साल के बाद ट्रांसफार्मर लगा है, फिर भी उसके बीच की अवधि का बिजली बिल आया है । हमलोग विधायक हैं, पैरवी करते हैं लेकिन बिजली विभाग के पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । गरीबों की हालत यह है कि जिसने ब्लौक तक नहीं देखा है, खाने के लिए मोहताज हैं, दिन भर किसी के यहां बनिहारी करेगा, तब वह जाकर 200 रूपया कमायेगा । अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि उसके यहां टंग गया बकुली, बिजली नहीं है, उनके यहां 20हजार, 30 हजार रूपये का बिल आ गया है ।

क्रमशः

टर्न–23/शंभु/17.03.16

श्री राजू तिवारी : क्रमशः.....महोदय, क्या होगा ऐसे हमलोग विकास की बात करेंगे गांव में ? आज बिजली सबसे बड़ा मुद्दा है, गांव में रोड से भी ज्यादा लोग बिजली को चाह रहे हैं। अब आवश्यकता है मोबाइल चार्ज करने में, सबकुछ चार्ज करने में बिजली पर आश्रित हैं। महोदय, इस तरह से अगर बिजली लगेगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि बिहार सरकार की उपलब्धि मानी जायेगी, यह बिचौलियों की उपलब्धि मानी जायेगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार दावे के साथ कह रहा हूँ आदरणीय मंत्री जी कि अगर जरूरत पड़ा तो मैं बी0डी0ओ0 या जो पदाधिकारी हैं टेंडर कंपनी का मैं प्रूफ रखा हूं, अगर हमको बुलाया जायेगा तो मैं प्रूफ दूंगा। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि ऐसे बिचौलिये जो पेटी पर पेटी देकर काम करा रहे हैं। महोदय, अभी मुखिया का चुनाव है, मुखिया के चुनाव में

प्रत्याशी बहुत हैं- मिल जा रहे हैं लोग वहां पर बिजली, पोल गड़ाने के लिए जा रहे हैं, वे सीधे बिचौलिये के घर जा रहे हैं और वहां पर दिनभर यही काम हो रहा है कि इतना रूपया आप देंगे तो आपके टोला में लगवा देंगे, इतना रूपया आप देंगे तो आपके टोला में लगा देंगे। इसपर अंकुश लगाया जाय। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, आपका समय 7 मिनट है।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, आपने पहली बार सदन में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने माननीय नेता अमित शाह जी का, माननीय नेता सुशील कुमार मोदी जी का, राधा मोहन सिंह जी का, प्रेम कुमार जी का जिन्होंने मुझपर भरोसा करके टिकट देने का काम किया और मैं आभार प्रकट करता हूं कुढ़नी की महान जनता का जिन्होंने उसपर मुहर लगाने का काम किया है। महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, कुढ़नी मेरा विधान सभा क्षेत्र है। कुढ़नी पूरे बिहार में 39 पंचायत का पहला प्रखंड है और पहला प्रखंड एक प्रखंड होने की वजह से कुढ़नी का विकास नहीं हो रहा है। यह संयोग है मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का और इनके साथ साथ इस सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों को भी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि बिहार की जनता ने आपको मैनडेट दिया है। मैं चाहता हूँ कि कुढ़नी विकास नहीं हो रहा है सिर्फ एक प्रखंड होने की वजह से, वहां पर दूसरा प्रखंड मनिहारी की मैं मांग करता हूँ और जब तक कुढ़नी का- आप अगर शपथ लिये हैं, आपका निश्चय है बिहार का विकास करना तो कुढ़नी का विकास किये बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली बिना जीवन अधूरा है, बिजली की अधिकांश आबादी गांवों में बसती है और खेती बारी करके किसान भाई अपना जीवन बसर करते हैं। उन किसानों के लिए सरकार ने अलग से इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। अभी तक किसानों के लिए अलग फेज में बिजली उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जिससे कि किसानों को पटवन और कृषि कार्य में अधिक सहयोग प्राप्त होता। मैं महोदय आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि सस्ती दर पर किसानों के लिए अलग फेज में बिजली मुहैय्या कराकर इनकी खेती एवं कृषि समेत अन्य कार्यों में पूर्ण सहयोग करें। महोदय, यह बात सही नहीं है क्या कि पंजाब, गुजरात,

मधयप्रदेश, राजस्थान में जिस प्रकार से वहां की सरकार कृषि क्षेत्र के लिए अतिरिक्त फेज में सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराती है उसी प्रकार से बिहार में क्या किसानों के लिए यह व्यवस्था नहीं किया जा सकता है। महोदय, हमारा क्षेत्र मुजप्फरपुर जिला का कुढ़नी विधान सभा है। वह किसान आधारित क्षेत्र है वहां पर जितना नलकूप है वह बिजली के अभाव में या तो बंद हो चुका है या ट्रांसफार्मर नहीं लगने की वजह से बंद पड़ा है। महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र के मुहम्मदपुर जैसे दर्जनों नलकूप हैं जहां ट्रांसफार्मर जल गया है या चोरी हो गया है, जिसे नहीं लगाया जा रहा है और किसानों की खेती बाधित हो रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज भी माधोपुर सुस्ता में नलकूप का ट्रांसफार्मर लगना था और एक महादलित टोला में ट्रांसफार्मर लगना था, लेकिन महीनों से एस0डी0ओ0 वहां का कह रहे हैं कि आज लगाउंगा, कल लगाउंगा- आज मैं जब तीन बार फोन किया तो उन्होंने फोन उठाने का काम नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यही बिजली विभाग की करतूत है। महोदय, पूरे क्षेत्र में सामाजिक न्याय की बात करनेवाले सरकार दलित, महादलित, अति पिछड़े के टोला में दर्जनों ट्रांसफार्मर चोरी हो गया या जल गया उसे महीनों से दौड़ा दौड़ाकर थका चुके हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा रहा है। महोदय, कुढ़नी, केशरिया, मछुआरा टोला, हरिशंकर, मनियारी के महादलित टोला जैसे दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां आजादी के 68 वर्ष बीतने के बाद वहां बिजली नहीं पहुंचाया जा सका है। महोदय, आज भी दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां बांस और बल्ला लगाकर लोग बिजली जलाते हैं और बिल जमा कर रहे हैं, लेकिन उनको पोल नसीब में नहीं है। महोदय, किशुनपुर मधुबन के महादलित टोला एक ऐसा टोला है जहां ट्रांसफार्मर हुजूर लगाया गया और ट्रांसफार्मर लगते ही जल गया, लेकिन उस महादलित को हजारों का बिल आ रहा है। जब बार-बार अफसर को कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर आपने लगाया और ट्रांसफार्मर जल गया आप बिल क्यों भेज रहे हैं तो वह कहता है कि सर, आज देख लूंगा, कल देख लूंगा। यह तो स्थिति है ऊर्जा विभाग की। महोदय, बिजली कनेक्शन के लिए पैसा जमा करके 6-6 महीना तक दौड़ना पड़ता है, लेकिन उसे बिजली नहीं मिल रहा है, कनेक्शन नहीं मिल रहा है। साथ-साथ सरकार ने बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए मुजप्फरपुर में ऐस्सेल कंपनी को दिया था, लेकिन ऐस्सेल कंपनी अपना अलग से मीटर- पता नहीं मुम्बई से लाया है कि कहां से लाया है, अपना मीटर लगा दिया है और मीटर वह इतना चलता है कि पहले 500 रू0 जिस आदमी का बिल आता था उसका प्रत्येक महीना 5000 बिल आ रहा हैं, यह तो स्थिति है

बिजली विभाग का और जनता का दोहन हो रहा है। महोदय, सरकार का संकल्प था कि बिहार के लोगों को 24 घंटा बिजली दिया जायेगा, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों या बड़े शहर छोड़कर के देहात में लोग जाकर, मैं देहात का विधायक हूँ। मैं जानता हूं, जब मैं शाम में जाता हूँ किसी के यहां नेवता पुरने के लिए तो देखता हूँ कि वहां अंधेरा है, बच्चे बैठे हैं पूछता हूं कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो तो कहता है कि बिजली नहीं है। जिस सरकार में बच्चे को पढ़ाने के लिए बिजली नहीं है, वह क्या कर सकती है, यह देखने की बात है। महोदय, गांव में बच्चों को पढ़ने के समय शाम में बिजली नहीं मिलती इससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है। महोदय, बिहार में बिजली एवं विधि व्यवस्था के चलते कोई भी उद्योगपति बिहार में अपना उद्योग लगाना नहीं चाहते हैं। 2015 में केन्द्र में सरकार जब बनी थी तो उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाने की मंशा पाले थे, लेकिन ज्योंही देखा कि यहां की विधि व्यवस्था बिगड़ रही है तो उद्योगपति बिहार में आना बंद कर दिया। विधि व्यवस्था का भी मामला है और बिजली भी उसको सही ढंग से मिलने की आशा नहीं है। महोदय, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का दायित्व बनता है कि राज्य का अधिकांश आबादी वाला लोग गांव में बसते हैं उनकी सुविधा का पूरा घ्यान रखा जाय। महोदय, अभी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। सरकार ने अति पिछड़ों को, दलितों को जातियों को आरक्षण देने का काम किया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन कोटा बढ़ाने की मांग करता हूँ। महोदय, पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों को 20 प्रतिशत आरक्षण.....व्यवधान।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें। श्री ललन पासवान जी प्रारंभ करें।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, बिजली बिहार के आम साढ़े 11 करोड़ लोगों के जीवन की आवश्यकता है, जीवन का लाइफ लाइन है, लेकिन मैं जहां से आता हूं मैं जरूर बधाई दूंगा कि बिजली का विकास हुआ है चूंकि नीतीश कुमार जी और नरेन्द्र मोदी जी एक ही मंच पर आ गये हैं तो विकास स्वाभाविक है, लेकिन मैं जहां से आता हूँ मैं वहीं से शुरू करता हूँ। प्रत्यय अमृत जी को बधाई।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : आप 2 ही मिनट में समाप्त कीजिएगा।

श्री ललन पासवान : दलित की बात है तो आसन से कुछ समय मिलना चाहिए। महोदय, मैं जिस इलाके की बात कर रहा हूँ वहां आजादी के बाद बिजली देखा नहीं है नौहट्टा, चेनारी, शिवसागर माननीय विधायक अशोक जी बोल रहे थे..... क्रमशः।

टर्न–24/अशोक/17.03.2016

श्री ललन पासवान : क्रमशः 70 गांव मेरा है पहाड़ पर, आजादी के बाद आज तक बल्ब ही नहीं देखा, बगल में कैमूर जिला का अधौरा 109 गांव, पहाड़ पर 250–300 गांव है, आजादी के 68–70 वर्ष के बाद भी बिजली का लाईन, बिजली का तार, बिजली का बल्ब देखा ही नहीं है– विकास जरूर कर रहा है , हम कहां कह रहे हैं, हम बधाई जरूर देना चाहते है। प्रत्यय अमतृ साहब पर्यावरण से कोशिश भी कर रहे हैं,प्रोजेक्ट भी बनाये हैं, पहली बार गुप्ताधाम, गुप्ताधाम जहां बिजली पहुंचने का, जो पर्यटन स्थल है, शिव न जाने कब पैदा हुये, कब भस्मासुर को आर्शीवाद दिये थे अमरतत्व का, वहां बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया है, हम इनको जितनी बधाई दे कम है । 7 मार्च का ड्यू डेट था, 7 मार्च खत्म हो गया, पर्यावरण से जल्दी संज्ञान हो जाय और पहाड़ के लोगों को, गुलाम लोगों को, गुलाम लोग, आज भी चुनॉरियों का पानी पीते है और कभी लाईन देंखे नहीं उनको कम से कम रोहतास ओर कैमूर के ग्यारह, यानी कम से कम तीन सौ गांव और चार–पांच प्रखण्ड– अधौरा, चैनपुरचांद, नीचे रामपुर–भगवान पुर का इलाका, चैनारी, शिवसागर– जंगल का इलाका पूरा का

पूरा आज 25 और 16 केवी पर जला रहा है श्रीमान् । माननीय श्रवण कुमार जी, मैंने कभी गलत नहीं बोला है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये ललन जी ।

श्री ललन पासवान : अब खत्म ही कर रहे हैं । इसलिए वहां बिजली मिल जाय, हम सदन के माध्यम से आदरणीय पर्यटन मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, माननीय श्रवण कुमार जी आप राज्य की महोत्सव मानते हैं, आप देव का महोत्सव मनाते है - गुप्ताधाम जहां शिव ने अमरत्व का वरदान भस्मासुर को दिया था, आप गये भी है, एक बार इमानदारी से उसको पर्यटक स्थल घोषित करवा दीजिए, सुन लिया जाय एकमिनट, पर्यटक स्थल घोषित करा दीजिए और बिजली तो पहुंचा ही दीजिए ।

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्री ललन पासवान : सर, सर । एक मिनट । और अनुसूचित जाति का आवासीय विद्यालय, कल्याण मंत्री यहां बैठे हैं, आवासीय विद्यालय जितने हैं पूरे बिहार में- 300 से 400 आवासीय विद्यालय हैं, खानाबदोश की जिन्दगी आजादी के बाद, सदन में बैठक मंत्री और विधायकां को चुनौती देता हूँ, उसका भोजन- दाल भात सब्जी खा लें, वह खानाबदोश की जिन्दगी जीता है .. ।

अध्यक्ष : श्री लाल बाबू राम ।

श्री लाल बाबू राम : महोदय, हमें सदन में बोलने का मौका दिये इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ । हमें सरकार के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विरूद्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सबसे पहले बिहार के राजनीति में बहुत बदलाव हुआ है, कई बदलाव क्रातिकारी हुये हैं । क्रांतिकारी बदलाव में, सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव 1990 के दशक में हुआ जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने । आदरणीय लालू प्रसाद जी दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के मसीहा बनकर आये और इस दलित समाज के लिए, गरीब तबके के सभी वर्गो के लिए, मान-सम्मान और विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील रहे । एक समय था कि जनप्रतिनिधी के लोगों को चुनाव में ही देखते थे लेकिन समय को बदलते हुये श्रद्धेय लालू जी गांव, कसबों में दलितों के बीच में, गरीबों के बीच में गये और उसके सुख, दु:ख में शामिल हुये और उनको मानसिक रूप से मजबूत किये और बोलने का अधिकार दिये और आह्वान किये कि ये दलित, शोषित, पीड़ित पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो और आज मैं गरीब मजदूर का बेटा लाल बाबू राम सदन में

बोल रहा है यह देन श्रद्धेय श्री लालू प्रसाद जी का है । मैं उनको प्रणाम करता हूॅ अैर उर्जा विभाग पर इतना कहना चाहता हूॅ, सभी वक्ता बोले हैं, जिस तरह से भोजन, वस्त्र और आवास का जीवन में जरूरत है आज के आधुनिक युग में उर्जा का उतना ही महत्व है । एक जमाना था जब उर्जा विभाग की बिजली कुछ परिवार, कुछ गांव तक ही सीमित था, लेकिन 1990 के बाद बदलाव आया । आज हम महागठबन्धन सरकाकर के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री, विभाग के सभी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूॅ कि कम संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी हर घर बिजली लगातार पहुचाई जा रही है । और जब चुनाव था तो हम देखते थे कि जब बी.जे.पी. के जितने भी वक्ता भाषण देते थे तो दो मुद्दा नहीं छोड़ते थे । बिजली आई, बिजली आई, कुछ लोग, प्रायोजित लोग आगे बैठे रहते थे वे कहते थे कि नहीं, लेकिन पीछे से जनता बोलती थी कि बिजली आई, हर घर आई और लगातार आई और भा.ज.पा. के झांसे में नहीं आयेंगे, महागठबन्ध को जितायेंगे और सरकार को बनायेंगे । आज बी.जे.पी. के लोग कोने में सिमट गये हैं, सरकार का विरोध विपक्षी के लोग करते हैं, जो हम देंख रहे हैं सदन में । सकारत्मक विरोध होना चाहिए, नकारात्मक नहीं । एक दूसरी बात बोलनाा चाह रहे थे, बराबर बोलते थे हमारे बी.जे.पी. के वक्ता कि अच्दे दिन आने वाले हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रमोद बाबू, लाल बाबू को बोलने दीजिए ।

श्री लाल बाबू राम : वे कहते थे कि काला धन निकाल कर प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रूपया देंगे । अच्छे दिन कहां गये ? आप कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे अभी जब स्मार्ट सिटी.....

अध्यक्ष : लाल बाबू जी, आप अच्छा बोल रहे है, लेकिन अब समय खत्म होगा, एक मिनट में जो-जो कहना है क्षेत्र के बारे में तो बोल लीजिए ।

श्री लाल बाबू राम : सरकार बिजली के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है । हमारे सकरा विधान सभा क्षेत्र में मुजफ्फरपुर जिला और वैशाली, राजीव गांधी विद्युतीकरण क्षेत्र में पड़ता है, वहां बहुत काम हुआ हैं और कुछ सुधार की गुंजाइश है, मुजफ्फरपुर जिला के सकरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सकरा और मुरौल मिला करके क्रमशः

टर्न-25-17-03-16- ज्योति

क्रमशः

श्री लाल बाबू राम : सकरा विधान सभा के अन्तर्गत सकरा और मुरौल मिलाकर वहॉ 35 हजार उपभोक्ता हैं जिसमें दो सेक्शन बनाया गया है । बरियारपुर में, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा का निर्माण कराया गया है । बरियारपुर में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जाय और मुरौल में जो ढोली विद्युत आपूर्ति प्रशाखा है, उसके अन्तर्गत गायघाट-बंदरा-और कुड़हनी का 7 क्षेत्र पड़ता है जो बड़ा क्षेत्र पड़ता है इसलिए विद्युत आपूर्ति प्रशाखा का निर्माण कराया जाय । हमारे सकरा विधान सभा में ऐसे भी बिल आ रहे हैं जिनको बिजली नहीं मिली है और बिजली मिली है तो उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर बिजली बिल आ रहा है । वहॉ एक अभियान चलाकर बिजली बिल सुधार किया जाय।

अध्यक्ष : ठीक है, धन्यवाद । माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, उर्जा ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, लगभग 19 माननीय सदस्यों ने उर्जा विभाग के बजट में अपनी बात को इस सदन में आपके माध्यम से आपकी अनुमति से रखने का काम किया है । अपनी अपनी जानकारी , अपनी अपनी सहूलियतें, अपनी अपनी इच्छाओं

के अनुसार लोगों ने अपनी बात रखी । मुझे इसमें बहुंत अधिक कुछ नहीं कहना है , न जाना है । तीन चार बातें महत्वपूर्ण रुप से उभर कर आयी हैं । नंबर -1 कि कुछ गांव छूट गए हैं , कुछ मुहल्ले छूट गए हैं , कुछ बस्तियॉ छूट गयी हैं । जिसमें दलितों का है , पिछड़ों का है , अति पिछड़ों का है , गरीबों का है । कुछ बाते आयीं कि कुछ जगह ट्रांसफार्मर बदलने का क्रम जो जारी है उसमें रह गया है जो छोटे ट्रांसफार्मर थे और बिजली बिल के विषय में ज्यादातर शिकायतें आयीं । महोदय, मुझे स्मरण हो रहा था जब हमलोग चले थे इसमें माले के माननीय सदस्य को छोड़कर करीब करीब सभी दल के लोगों ने बिहार बंटवावरे में इसी सदन में 2000 में साझीदारी किया था ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, बिहार-झारखण्ड बंटवारे के समय में माले के 6 सदस्यों ने वाक-आउट किया था ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : वही तो कह रहा हूँ । अलग से कोई बात नहीं कह रहा हूँ । राष्ट्रीय जनता दल , भारतीय जनता पार्टी , जनता दल यूनाईटेड - उस समय जनता दल यूनाईटेड नहीं समता पार्टी थी और कौंग्रेस भी, यही तो मैंने कहा । इसमें अमेंडमेंट की कहॉ जरुरत है । तो महोदय, मुझे स्मरण हो रहा था एक तो पहले भी संयुक्त बिहार में जो बिजली की उत्पादन होने की यूनिटें थीं वह कम थी लेकिन बिहार के हिस्से में केवल 440 मेगावाट हिस्सा आया । 110 की दो यूनिट मुजफ्फरपुर की 110 की दो यूनिटें बरौनी की , बरौनी की एक इकाई नंबर-2 जो थी वह टुकडुम-टुकडुम 10 -15 मेगावाट चलती थी और बिजली पैदा करने से ज्यादा उसमें तेल और कोयले की आपूर्ति में खर्चें ज्यादा होती थीं । अब महोदय, 60 के दशक में भेल ने अमेरिकन टेक्नोलॉजी 110 की यूनिट बनाने का काम किया था । लगभग देश के हर हिस्से में 110 यूनिट को बदल दिया गया । वह टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सार्थक नहीं थी । अब तो खैर 800 कुछ मेगावाट की यूनिटें आ रही हैं । विकास हुआ , विस्तार हुआ । वहॉ से महोदय, हम चले थे । जो ईस्टर्न रीजन का हिस्सा है 6-7 सौ मेगावाट मिलती थी उसी में रेल भी थी , उसी में नेपाल को भी देना पड़ता था और अपनी भी खपत थी। मोटा मोटी शहर को बिजली मिलती थी बाकी जगहों पर ग्रामीण क्षेत्र में तो कल्पना के बाहर की बात थी , जिला मुख्यालय में भी बिजली सुनिश्चित नहीं रहती थी । वहॉ से हमलोग प्रारम्भ किए थे । आज एक व्यापक बहस होती है महोदय, बार बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अपनी बिजली कितनी थी, यह प्रश्न टारगेटेड होता है। और चुनाव के समय में मुझे हैरत है कि गोयल साहेब ने भी यही सवाल उठाया था। प्रेस कौन्फ्रेंस करके कि हम भारत सरकार की ओर से बिजली देते हैं । बिहार की अपनी बिजली कुछ नहीं । तो मैंने इसीलिए इसका जिक्र किया कि

बिहार बंटवारे के समय में केवल क्षमता 440 की थी और भारतीय जनता पार्टी भी , एन0डी0ए0 की सरकार थी दिल्ली में , आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी उस समय रेल मंत्री भी थे , सात मंत्री भी रहे बाजपेयी जी के नेतृत्व में सभी लोगों की सहमति थी । तो 440 का हिस्सा ही मिला था । वहीं से प्रारम्भ हुआ और जैसा मैंने कहा कि 10-15 मेगावाट पैदा होती थी । लेकिन सौभाग्य हमारा - जब प्रारम्भ किया तो शून्य से । आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि 3400 से अधिक मेगावाट हमलोग ले रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं । अब पौलिटिकल बात अपनी जगह पर है । 4 महीना पहले नवम्बर में बिजली आयी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे लेकिन चार महीने के बाद माननीय मुख्यमंत्री की जिन्होंने प्रशंसा की , मैं धन्यवाद देता हूँ कि बिजली के मामले में बिहार अव्वल है और आगे आने वालों वर्षों में जो उनका 2019 तक का टारगेट है उन्होंने कहा कि नीतीश जी जो काम कर रहे हैं उस काम के आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण में बिहार नंबर वन राज्य बनेगा । लेकिन महोदय , 15-03 दीनदयाल विद्युत योजना का जिक्र करके - मैं उसपर बाद में आऊंगा । 10 वीं पंचवर्षीय योजना में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे केन्द्र में मंत्री थे दो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के लिए , माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बाजपेयी जी के नेतृत्व में प्रारम्भ करने का काम किया । ग्रामीण सड़क योजना 1000 की आबादी तक और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और उस विद्युतीकरण योजना का कंसेप्ट यह था कि गरीबों को केवल हम मुफ्त में कनेक्शन देकर इलेक्ट्रिफायड करेंगे विलेज में 10 परसेंट । बी0पी0एल0 स्कीम का बी0पी0एल0 आबादी का सर्वेक्षण करके 10 परसेंट हर रेवेन्यू विलेज में पंचायत भी नहीं जबकि नरसिंहाराव के सरकार के समय में ही पंचायत कंस्टीच्युशनल इकाई हो गयी थी लेकिन जो भी हुआ । प्रेम बाबू बाजपेयी जी जिन्दा है; आज कितनी अच्छी श्रद्धा आप रख रहे हैं कि बाजपेयी जी ने 100 परसेंट ग्रामीण सड़कों मे और 90. फी सदी राज्य को दिया था बिजली के क्षेत्र में, आपने 60 कर दिया , 60 आपने कर दिया 40 परसेंट ं राज्य को देना होगा बिजली के मामले में । अरे पढ़ा कीजिये । बिना पढ़े मत बोला कीजिये । पढ़ा कीजिये । भारत सरकार के जितना ही आप हकदार हैं" उतना ही हम भी हकदार हैं ।" हम भी भारत के नागरिक हैं । राज्य की नागरिकता नहीं है जो खो जायेगी । कहाँ से सिख लिए हैं भारत सरकार मतलब आप?

इसी सदन में हमलोग साक्षी हैं , भागी हैं । यह बहस हुई थी कि सरकार दिल्ली में किसी की हो राज्य को विशेष राज्य की दर्जा पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था। उस समय तो सरकार हमलोगों की नहीं थी । लेकिन प्रेम बाबू मनमोहन सिंह की सरकार ने बाजपेयी जी के सपनों को काटा नहीं । केवल नाम बदला । इन्होंने नाम

राजीव गांधी जरुर किया लेकिन आवंटन नहीं काटा । आपने तो आवंटन काट दिया अब अगर 1000 करोड़ रुपये के खर्च में राज्य को 100 करोड़ रुपया देना पड़ता था तो आज हमको 400 करोड़ रुपया देना पड़ेगा । दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति, डा0 राम मनोहर लोहिया जो हमलोगों के नेता थे राष्ट्रीयता के मामले में , भाषा के मामले में , विदेश नीति के मामले में , गैर कौंग्रेसवाद के सिद्धान्त पर सहमत थे ।

क्रमशः

टर्न–26/विजय/ 17.03.2016

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः क्रमशः महोदय, डा0 लोहिया कहते थे कि रोटी को अदलने बदलने से रोटी अच्छी बनती है सरकार को भी अदलने बदलने से लोकतंत्र ताकतवर होता है । उसके नाम पर आपने रखा मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन बाजपेयी जी ने 90 परसेंट देने के बाद अपना नाम नहीं जोड़ा किसी का नाम नहीं जोड़ा मनमोहन सिंह जी ने राजीव गांधी का नाम जरूर जोड़ दिया लेकिन पैसे नहीं घटाये । लेकिन आज जय जयकार हो रहा है । अब दीन दयाल उपाध्याय योजना के बाद प्रगति की बात कर रहे हैं बोल रहे हैं ।

महोदय, 15.3.16 आज है 17.3.16 दो दिन पहले ही यह अनुमति मिली है डाक टेंडर की । दीन दयाल उपध्याय योजना में जो पैसे आवंटित हुए हैं वह लगभग 8 हजार 9 हजार के करीब है और टेंडर की अनुमति मिल गयी है लेकिन जय जयकार पहले से हो रहा है । लेकिन आप अपने से ही प्रधानमंत्री के साथ है कि नहीं मानता चुनाव में जो बातें हुई, हुई । लेकिन पिछले दिनों हाजीपुर में सभी ने सुना कि बिजली के क्षेत्र में उन्होंने श्री नीतीश कुमार जी की प्रशंसा की और बधाई दिया । अगर आप प्रधानमंत्री से असहमत हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है, आपकी मर्जी । उपर कुछ नीचे कुछ । महोदय, एक बच्चा था वह स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में जब पढ़ता था तो उसको मास्टर ने पढ़ाया आई माने मैं कहता था स्कूल में आई माने मास्टर साहब,आई माने मास्टर साहब । जब घर पर गया तो फादर ने डांटा तो कहा आई माने पापा । फिर स्कूल गया तो जब मारा टीचर ने तो कहने लगा आई माने घर में पप्पा जी स्कूल में मास्टर साहब अगर यह फार्मुला है आपको पसंद है तो मुझे कुछ नहीं कहना है दिल्ली में वहां और यहां हम उनको झूठ बोलेंगे मुझे कुछ नहीं कहना ।

महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैं एक बात कहने में हिचक महसूस नहीं करता हूं । इतना काम होने के बाद भी अब बैठे हुए हैं हमारे माननीय माननीय नेता ये प्रसन्न नहीं हैं । ये मेरे लिए गर्व का विषय है क्योंकि जो उनकी कल्पना है, जो इनका कमिटमेंट है, जो इनकी दृष्टि है कि दुनिया के जो अर्थशास्त्री लोग कहते हैं किसी इलाके में, किसी राज्य में, किसी देश में अगर गरीबी का उन्मूलन करना हो तो दो के अलावा कोई तीसरा कोई काम नहीं करने की जरूरत है वह है पावर और कम्युनिकेशन को अपलोड करा दीजिये अपने आप ग्रोथ ले लेगा । ये जो मुख्यमंत्री की कल्पना है इसलिए और काम की अपेक्षा करते हैं यह हमारे लिए प्रेरणा का मामला है, गर्व का विषय है । कोई मुख्यमंत्री इतना ज्यादे 2012 में जितना

कमिट किया कि 2015 में अगर सुधार नहीं हुआ तो वोट मांगने नहीं माफी मांगने जायेंगे । दुनिया का पहला नेता मैं कहूं तो कोई एतराज नहीं है । इतने मुस्तैदी से उन्होंने करने का काम किया । मुझे खुशी है थोड़ा बहुत कोताही के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कल्पना के अनुरूप नहीं लेकिन मैं अपने विभाग के तमाम अधिकारी पदाधिकारी शुरू से लेकर अभी तक जिनलोगो ने काम करने का काम किया मैं उसके प्रति आभार प्रकट करता हूं जो वायदे को उन्होंने पूरा करने का काम किया । और आज प्रधानमंत्री ने भी कहा है भरोसा दिलाया है कि बिहार में नीतीश कुमार नं0–1 होगा ये भी विभाग के लिए बड़ी ही अच्छी बात है । अब महोदय 2012 का अगर बजट भाषण देखेंगे तो मैने कहा था वादा और इरादा मैंने कहा था कि– अध्यक्ष महोदय हमारे नेता हैं, हमने उन्हें नेता माना है तो जो उनका कमिटमेंट है जो उनका वादा है बिहार की जनता के लिए वह हमारा कर्त्तव्य वह हमारा सबकुछ बनता है जब उनको पूरा करेंगे । लेकिन क्या बिहार ऐसे रहेगा । इरादा भी हमने कहा था कि 2017 तक बिहार अपनी आवश्यकता की पूर्त्ति अपने माध्यम से करेगा सरप्लस होगा उसको कहने में मुझे कोई हिचक महसूस नहीं होती ।

अब महोदय, एक बात का और मैं जिक्र करना चाहूंगा । बिजली भारत सरकार की है कि राज्य सरकार की । बिजली को अध्यक्ष महोदय कानून में कोई आपके प्रधानमंत्री आए उन्होंने कानून नहीं बनाया यह पहले से आजादी के बाद ही था । इलेक्ट्रीसिटी एक्ट में क्या प्रोवीजन है महोदय कुछ चीजे भारत सरकार के डायरेक्ट अधिकार में है कुछ राज्य के अधिकार में है, कुछ दोनों के अधिकार में है । इलेक्ट्रीसिटी जो है दोनों के अधिकार क्षेत्र का विषय है । इलेक्ट्रिसीटी एक्ट असेम्बली नहीं बनाती पार्लियामेंट बनाती है । इलेक्ट्रिसीटी एक्ट में पांच भागों में हिन्दुस्तान को बांटा गया है उसी एक्ट के तहत । नौर्थ इर्स्टन रिजन, इर्स्टन रिजन, वेस्टर्न रिजन, नार्दन रिजन और साउदर्न रिजन । अब इस्टर्न रिजन में महोदय बिहार है, झारखंड है, उड़िसा है, बंगाल है, सिक्कम है । इन राज्यों में कानून के तहत पहले जो थे कि भारत सरकार जितनी युनिट लगायेगी उसका आकलन सी0इ0ए0 करता सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथोरिटी एक ऑटोनमस संगठन है वह विभिन्न राज्यों का आकलन करता है उसकी खपत कितनी है, उसकी आवश्यकता कितनी है और उसके हिसाब से वह लगाता और जिस राज्य में वह लगाता चूंकि पानी और जमीन राज्य को देनी होती तो 10 परसेंट पहले नियम यह था कि उस राज्य का हिस्सा है । 15 परसेंट केन्द्रीय मंत्री का एलौटी था तो हो गया टोटल 25 परसेंट बच गए 75 परसेंट । 75 परसेंट अमांग्स्ट द रिजनल स्टेट । जिस रिजन में अवस्थित है वह इंस्टॉल कैपेसिटी उस रिजन के स्टेट का शेयर होगा । अगर वह स्टेट फारगो करेगा हम नहीं लेगें तो बाकी रिजन में जाएगा । और एक अद्‌भुत बात और भी

है गौहाटी के सम्मेलन में हमलोगों ने उठाया मैने अपने लिए उठाया कि शेयर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे रेल के मंत्री रहे है बहुत दिनों तक रेल में नयी रेलवे लाइन बने या पुरानी बने टिकट दर एक ही होता है । लेकिन बिजली के क्षेत्रों में है कि जिन रिजन में पहले ही बन गया बिजली उस समय पचास लाख, पच्चीस लाख रू0 पर युनिट का कंस्ट्रक्शन कौस्ट हुआ करता था कौस्ट बहुत बढ़ा अब 8 रू0 पर मेगावाट होता है । तो कंस्ट्रक्शन कौस्ट प्लस आपरेशन का कौस्ट इसके बाद जो वैल्यु होता है वह आइडेंटीफाई होता है । मतलब जिन राज्यों में अब बन रहा है वहां बिजली ज्यादा महंगी मिल रही है । और जिन राज्यों में पहले बना वे सस्ती बिजली उपभोग कर रहे हैं । सबलोगों ने कहा कि जब एक देश है यह रिजनल डिसपैरिटी को खत्म करना चाहिए गोयल साहब । उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे । पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे मैं नहीं जानता लेकिन मैने कहा था । अलग से मैं उठाउंगा अगर वक्त मिला तो । तो इसलिए कि भारत सरकार की बिजली भारत सरकार अमेरिका में बिजली देने के लिए नहीं बनाती । भारत सरकार अपने ही राज्यों का एक औरगनाइजेशन है । कुछ ही राज्य है जहां भारत सरकार का अपना अधिकार है । बाकी तो राज्य का अधिकार है जमीन । जमीन, जल, सुरक्षा । अब रेल लाइन बनेगी तो राज्य की पुलिस जाएगी सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार की सेना है । जमीन हमारी, पानी हमारा । और महोदय, अभी नवीनगर में बन रहा है । चर्चा किया अब सुनील जी हैं भइया नवादा बुद्धि का केन्द्र रहा है पता नहीं कहां से भगवान मालिक है कह रहे थे कि नवीनगर में झारखंड और बंगाल ने कहा नहीं लेगे तो बिहार सरकार इसलिए निक्कमी है । अरे भइया 60 परसेंट हमारा बाकी भारत सरकार जहां ले जाय हमको क्या मतलब है। इसलिए यह नहीं है हमारा जो हिस्सा है वह है ही है । ज्वाइंट वेंचर कं0 है एन0टी0पी0सी0 के साथ है । हमारा हिस्सा उसमें होगा और यह कहते हुए महोदय मुझे खुशी हो रही है फेज-2 में जो 3 युनिट लगेगा उसमें एन0टी0पी0सी0 सैद्धांतिक सहमत हो गयी है कि 660 के बदले में 800 मेगावाट युनिट लगेगा । यह तो अपने आप ज्यादा बढ़ जाएगा । तो हम क्या करे उसमें । संपूर्ण देश में जो बनता है जो संपूर्ण सेंट्रल गवर्नमेंट का एलोकेशन है हम ही ले लेगे क्या, पैसा देना पड़ता है मुफ्त में बिजली नहीं मिलती है । इसलिए याद होगा चुनाव में मैने कहा था गोयल साहब को हिम्मत हो तो बिजली काट दें । काहे नहीं काटे । बिजली अगर काट देते तो नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री की सरकार नहीं बनती आपकी बात चल जाती । काटना चाहिए ।

क्रमशः

टर्न–27/बिपिन/17.3.206

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः क्रमशः आपकी बहस चल जाती । रेल भी तोड़ दीजिए । सुरक्ष,ा नेपाल से कोई घटना, चाईना से कोई घटना होगी तो आप सेना को वापस ले लीजिए क्योंकि भारत सरकार आपकी है । यहां तो आपकी सरकार है नहीं । नागरिकता राज्य की नहीं होती, नागरिकता भारत की होती है । एक वोट पार्लियामेंट को बनाने में दिया जाता है, एक वोट राज्य के निर्माण में दिया जाता है । मैंडेट आपको वहां मिला, आप वहां राज करिए, मैंडेट यहां माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार को मिला, गठबंधन को, यहां उनका राज्य चलेगा । दोनों राज्य जब मिलेगा तो जनता की खुशहाली होगी, अच्छाई आएगी, प्रगति होगी और उसके आप भी एक नियामक बनें । विपक्ष भी सरकार का अंग होता है । आलोचना करिए । जब राजतंत्र था महोदय, तो आलोचना करने वाले को हाथी से चपवा दिया जाता था, गोली से उड़ा दिया जाता था । अब विपक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है । लोकतंत्र की यही खूबसूरती है । डिसेन्सी, डिकोरम, डिसकसन, देन डिसिजन ये चार पाए लोकतंत्र के हैं और प्रेम बाबू, आप और हम जिस कम्युनिटी में पैदा लिए हैं, अगर लोकतंत्र नहीं होता तो इस घर में नहीं आ पाते, यह हमेशा ख्यालात रहे । गांव, गवई, गरीब, गुरूवा पगडंडियों पर चलने वाले आदमियों की यह विसात नहीं थी कि इस घर में आ पाए । राजा, रजवाड़ा, रायबहादुर लोग आते थे । यह हमेशा ख्यालात रहे । लोकतंत्र का पाया अगर कमजोर हुआ, हमलोगों ने अपने आपसे, अपने व्यवहार से इसको कमजोर करने का काम किया, तो आगे आने वाला संतति हमें माफ नहीं करेगा । इसीलिए हमेशा यह ख्याल रहे । बहस हो, शानदार बहस करिए । मैंने कल भी कहा था कि प्रेम से कोई बात हो, प्रेम से उत्तर हो । यही तो लोकतंत्र की खासियत है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर दो यूनिट, अब महोदय, इसकी भी एक कहानी है । एयरपोर्ट भारत सरकार की है मुजफ्फरपुर में । टावर का हाईट बढ़ाने की अनुमति नहीं दी । इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो समझौता बरौनी और मुजफ्फरपुर का हुआ था, उसमें यह सहमति बनी थी कि 110 की दो यूनिट सम विकास योजना के पैसे के आधार पर यह रिनोभेट होगा । ज्वायंट वेंचर कंपनी बनेगी । बरौनी हमारी कंपनी रहेगी, लेकिन एक्सर्टिज्म ज्यादा बेहतर है एन.टी.पी.सी. के पास टेक्निकल, इसीलिए उसके देख–रेख में वह 110 की दो यूनिट का भी मेंटेनेंस होगा लेकिन मुजफ्फरपुर में ढ़ाई सौ–ढ़ाई सौ मेगावाट की दो यूनिट बनेगी लेकिन चिमनी के हाईट को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने क्लीयर नहीं किया । इसीलिए मजबूरन 195 की दो बनी । अब महोदय, दिसम्बर 2016 तक चालू होने की संभावना है, दोनों यूनिट

195की, और नवीनगर में महोदय, तीन यूनिट 160मेगावाट का है, वह जून में पहला यूनिट, सितंबर 2017 में दूसरा यूनिट और मार्च, 2018 में तीसरा यूनिट । नवीनगर का रेल वाला जो है महोदय, उसमें पहला यूनिट मार्च, 2016 में जिसमें से हमलोग का 100मेगावाट होगा और बरौनी 2X250 का जो है वह 2016-17 तक पूरा होने का लक्ष्य है महोदय, इसीलिए, आगे आने वाले वर्षों में हमारी बिजली की क्षमता हजार मेगावाट से ज्यादा होगी । इसके साथ ही महोदय, मुख्यमंत्री जी का यह जो निश्चय है कि हर घर को हम बिजली देंगे, इसका भी लक्ष्य दो साल का है और हम कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार उस टारगेट से पहले ही पूरा हो जाए तो जेनरेशन के मामले में, ट्रांसमीशन के मामले में....

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: महोदय, दो बात बड़ी महत्वपूर्ण आई थी, एक बिजली विपत्रों में काफी शिकायतें महोदय आ रही हैं, सारे माननीय सदस्यों ने कहा, काफी पैसे बढ़ा कर बिल दिए जा रहे हैं महोदय, उस पर इन्होंने कुछ नहीं कहा और दूसरा ...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बाहर चले गए।)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 10करोड़ की लागत से ब्रेडा भवन बनाया जाएगा । बिहार ग्रीड कंपनी के द्वारा महोदय, बिहार पहला राज्य है जिसने ग्रीड कॉरपोरेशन भारत सरकार की संस्था और अपना जो ग्रीड कंपनी है, दोनों का एक ज्वायंट वेंचर कंपनी बनाया । सात जगहों पर महोदय, नवादा, छपरा, भागलपुर, गया, शेखपूरा, पटना एवं मुंगेर में 132के.भी.ए. की ग्रीड बनाने का 1792करोड़ रूपए की लागत से काम चल रहा है और जल्द ही उस काम को टारगेट के मुताबिक पूरा कर लिए जाऐंगे।

साथ ही, महोदय, पांच जगहों पर हमलोगों ने भारत सरकार के ग्रीड कॉरपोरेशन को रिकोमेंड किया है कि वो हमारे यहां हमारी क्षमता को देखकर बाहर से बिजली को लाने में हमें सहूलियत होगी । निर्माण करें । देखिए अब क्या होता है ?

इसके बाद कजरा के लिए आज भी अध्यक्ष महोदय, गोयल साहब से 9.00 बजे के करीब हमने बातें की कि चौसा का काम चल रहा है । पीरपैती की भी अनुमति मिल गई लेकिन कैबिनेट से नहीं हुआ है । कजरा के विषय में भी आप अविलम्ब निर्णय लें । अब देखिए । बहुत शोर करते हैं कि बिजली आई, बिजली बिहार को दे रहे हैं । अब देखिए, गोयल साहब नहीं करेंगे तो फिर देखते हैं आगे की बात । इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमलोग प्रयास करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जब जनता ने मैंडेट दे दिया है तो केन्द्र और राज्य झगड़े नहीं । आपस में

तालमेल करके, नहीं तो देश का, राज्य का अहित होगा । लेकिन महोदय, पॉलिटिकल इशु बनाना और दीन दयाल उपाध्याय तो अभी आई है लेकिन जैसा मैने कहा कि चुनाव में 3400मेगावाट बिजली प्राप्त की गई । कहीं यह शिकायत नहीं मिली । अगर बिजली की शिकायत मिलती कि बिजली आई, आई तो नहीं आई, तो वोट भी नहीं आता । इसलिए अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिकल अटरनेस से यह देश-दुनिया चलने वाला नहीं है । हमने प्रेम बाबू को प्रेम से कहे भी, तब भी वो भाग खड़े हुए । उनका फर्ज ही है । विरोधी हैं । वह विरोध नहीं करेंगे तो हमारा समर्थन थोड़े करेंगे । लेकिन मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वे अनवरत विरोध करते रहें और अगले पांच साल भी विरोध करते रहें, हमलोग अपने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश में, राज्य में आगे बढ़ने का काम करें । इन्ही शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य डा0 सुनील कुमार जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, वह हैं तो नहीं, फिर भी सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य डा0 सुनील कुमार अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

''इस शीर्षक की मांग 10/- से घटाई जाए ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि -

''ऊर्जा विभाग के संबंध में 31मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्त्ति के लिए 143,67,84,49,000/-(एक सौ तैंतालिस अरब सड़सठ करोड़ चौरासी लाख उनचास हजार) से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 17मार्च, 2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 31 है । अगर सदन की सहमति हो तो इसे संबंधित विभाग को भेज दिए जाए ।

(सदन की सहमति हुई)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 18मार्च, 2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।